लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 54 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. LIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 45—शुक्रवार, 22 अप्रैल, 1966/2 वैशाख, 1888 (शक)

No. 45—Friday, April 2, 1966/Vaisakha 24, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1277	सरकारी कार्यालयों को आयातित माल का सम्भरण	Supply of Imported Goods to Government Offices . .	7141–44
1278	मिश्र इस्पात कारखाने के लिये येनऋण	Yen Credit for Alloy Steel Plant	7144–46
1279	कारों के मूल्य	Prices of Cars	7146–49
1283	इस्पात कारखाने	Steel Plants	7149–51
1284	युरोपीय आर्थक समिति	European Economic Committee	7151–53
1286	कपडा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills . .	7153–57
1288	औद्योगिक बास्तयां	Industrial Estates . . .	7157–58

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1280	सरकारी क्षेत्र के उत्पाद	Public Sector Products . .	7158
1281	संयुक्त अरब गणराज्य से टेलीविजन सेटों का आयात	Import of T. V. Sets from U.A.R.	7158–59
1282	कतरन से इस्पात पिण्डों का निर्माण	Manufacture of Steel Ingots from Scrap	7159
1285	खादी का उत्पादन	Production of Khadi . .	7159
1289	कच्चे पटसन के मल्य	Prices of Raw Jute . . .	7159–60
1290	इस्पात का निर्यात	Export of Steel . . .	7160
1291	निर्यात कर्ताओं के सार्थ-संघ	Consortia of Exporters . .	7160
1292	चार सदस्यों के रेलवे का अमरीका का दौरा	Visit of Four-Member Railway Team to America . . .	7161
1293	खान तथा धातु मंत्रालय के अधीन बिजली घर	Power Stations Under the Ministry of Mines and Mietals .	7161
1294	दूधियों द्वारा धरना	Picketing by Milkmen . .	7162

---

*किसी नाम पर अंकित यह (+) चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—61 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1295	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के घड़ी बनाने के कारखाने का बन्द होना	Closure of H.M.T. Watch Factory	7162
1296	इमारती इस्पात	Structural Steel.	7162–63
1297	वस्तुओं के मूल्य	Prices of Goods	7163
1298	तेल शोधक कारखाने के लिये उपकरण बनाना	Manufacture of Equipment for Oil Refinery	7164
1299	काजू का निर्यात	Export of Cashew Nut	7164–65
1300	आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण किया जाना (इम्पोर्ट सब्स्टीट्यूशन)	Import Substitution	7165
1301	लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Licences	7166
1302	महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर	Maheshwari Devi Jute Mills, Kanpur.	7166
1303	पोलैंड का प्रतिनिधि मंडल	Delegation from Poland	7166–67
1304	पूर्वी पाकिस्तान के साथ रेल सम्पर्क	Rail Link with East Pakistan	7167
1305	पटसन का निर्यात	Export of Jute	7167
1306	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant	7167–68

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4201	लोहा तथा इस्पात के रद्दी टकड़ों की बिक्री	Sale of Iron and Steel Scrap	7168
4202	केले से रेशों का बनाया जाना	Extraction of Fibres from Banana	7168
4203	क्विलोन रेलवे स्टेशन	Quilon Railway Station	7168
4204	क्विलोन-त्रिवन्द्रम रेलवे फाटक (क्रासिंग)	Quilon-Trivandrum Crossing	7169
4205	केरल में रेलवे स्टेशनों तक जाने वाली सड़कें	Approach Roads to Rly. Stations in Kerala	7169
4206	कोट्टारक्कर तथा पुनलर स्टेशनों पर पासल कार्यालय	Parcel Offices at Kottarakara and Punalur Stations	7169
4207	केरल में हथकरघा सहकारी संस्थाएं	Handloom Co-operative Societies in Kerala	7170
4208	बट हुए (स्पन) रेशम का कारखाना	Spun Silk Factory	7170
4209	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at New Delhi Railway Station	7171
4210	नंगल के समीप अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Mill near Nangal	7171
4211	दस्तकारी की वस्तुओं का उत्पादन	Production of Handicrafts	7171

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4212	काजू का निर्यात	Export of Cashew Kernels .	7171–72
4213	राजकोट-जादर और भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन	Rajkot Jasdar and Bhavnagar-Tarapur Lines . . .	7172
4214	दो तथा तीन शायिकाओं वाले शयन डिब्बे	Two and Three Tier Sleeper coaches	7172–73
4215	कारैक्कुडी से मद्रास तक सीधे डिब्बे	Through Carriages from Karaikudi to Madras . . .	7173
4216	सीमेंट के कारखाने	Cement Factories . . .	7173–74
4218	कोयले का वर्गीकरण	Grading of Coal . . .	7174
4219	बिहार में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel in Bihar .	7174–75
4220	सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries .	7175
4221	करवी रलवे स्टेशन	Karwi Railway Station . .	7175–76
4222	रागौल रेलवे स्टेशन	Ragaul Railway Station . .	7176–77
4223	ग्वार गम का उत्पादन	Production of Guar Gum . .	7177
4224	पुनर्वेलन मिल	Re-Rolling Mills . .	7177
4225	निर्यात की अनेकता	Diversification of Exports . .	7177–78
4226	पूर्व रलवे पर पुलों का निर्माण	Construction of Bridges on Eastern Railway . . .	7178
4227	वार्सलीगंज के निकट डकैती	Dacoity near Waris Aleganj Station	7178
4228	दक्षिण पूर्व रेलवे में छंटनी	Retrenchment on S. E. Railway	7179
4229	बेबी फूड का उत्पादन	Manufacture of Baby Food .	7179
4230	पम्पेगंज रेलव स्टेशन पर राष्ट्रीय छात्र सेना दल के केडटों का रेलवे कमचारियों से झगड़ा	Clash of N. C. C. Cadets with the Railway Staff at Peppeganj Railway Station . . .	7179–80
4231	दियासलाई के कारखानों को बन्द कर देना	Closure of Match Factories	7180
4232	मोरवी अमरान संकरी (नेरो गेज) लाइन	Morvi Amran Narrow Gauge .	7181
4233	भारत उत्पादिता वर्ष	India Productivity Year . .	7181
4234	हथकरघे से बने कपड़े का निर्यात	Export of Handloom Cloth .	7181–82
4235	उड़ीसा में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Orissa	7182
4236	उड़ीसा के लिये सीमेंट का कोटा नियत किया जाना	Allocation of cement to Orissa	7182–83
4237	ब्रिटिश गिआना से शिष्टमंडल	Delegation from British Guiana	7183
4238	इटली को वस्त्रों का निर्यात	Export of Textiles to Italy .	7183
4239	निर्यात घर	Export Houses	7183–84

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4240	इगतपुरी-भुसावल सैक्शन (मध्य रेलवे) में बिजली लगाना	Electrification of Igatpuri Bhusaval Section (Central Railway)	7184
4241	पंजाब में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	Ambar Charkha Training Courses in Punjab . .	7184
4242	गया के निकट रेलगाडी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Gaya . .	7184–85
4243	रूसी तकनीकी सहयोग से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना	Setting up of Public Sector Enterprises with Soviet Technical collaboration . . .	7185
4244	पंजीकृत लोहा तथा इस्पात व्यापारी	Registered Iron and steel Dealers	7185
4245	सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries . .	7185
4246	खजूर और मेवों के आयात के लिये भारतीय जहाज	Indian Vessel for Import of Dates and Dry-fruits . . .	7186
4247	आयात निर्यात नियंत्रण कर्मचारी संघ	Import Exort Control Employees Association	7186
4248	आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी आदेश	Orders re : Casual Leave . .	7187
4249	अंदमान दीपसमूह में रबड़ और चाय के बागान	Rubber and Tea Plantations in Andamans	7187
4250	फिनलैंड अखबारी कागज की शीट	Finland Newsprint Sheet . .	7188
4251	पंजाब के लिये टीन तथा सीमेंट का नियतन	Allotment of Tin and Cement to Punjab	7188
4252	"एम्बेसेडर' कारों का निर्माण	Manufacture of Ambassador Cars	7189
4253	उत्तर प्रदेश में नये उद्योगो के लिये सहायता	Assistance for New Industries in U.P.	7189
4254	मास्को में भारतीय प्रदर्शनी	Indian Exhibition in Moscow .	7189–90
4255	लोहे और इस्पात की वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Items of Iron and Steel	7190
4256	काश्मीर जाने वाले पर्यटकों को रेल के किराये में रियायत	Concession in Fare for Tourists visiting Kashmir . . .	7190
4257	रेलवे कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Railway Staff .	7191
4258	बम्बई के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Train near Bombay	7191
4259	पूर्वोत्तर रेलवे में बिजली लगाना	Electrification on North-Eastern Railway	7191
4260	भारत जापान संयुक्त व्यापार	India-Japan Joint Trade Commission	7191–92
4262	सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Textile Goods .	7192
4263	त्रिवेन्द्रम में टाइटेनियम का कारखाना	Titanium Factory at Trivandrum	7192–93

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4264	टायर तथा टयूबों की कमी	Shortage of Tyres and Tubes .	7193
4265	दिल्ली से बम्बई तक एक्सप्रेस गाड़ी	Express Train from Delhi to Bombay	7193
4266	रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नारियल के छिलके का सडाना	Retting of Coconut Husk by Chemical Processes. . .	7194
4267	अलप्पी में नारियल जटा की चटाइयों का कारखाना	Coir Mats Factory in Alleppey .	7194
4268	समुद्र से मिलनेवाले खाद्य पदार्थों के निर्यातक	Sea Food Exporters . .	7194
4269	कपड़े का निर्यात	Export of Textiles . . .	7195
4270	ऊन के गोलो का आयात	Import of Wool Tops . .	7195
4271	विदेशों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के निर्यात कार्यालय	Export Offices of H.M.T. Abroad	7195
4272	अंगुर की शराब (वाइन) बनाना	Manufacture of Wine . .	7195–96
4273	हार्ड कोक पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Hard Coke . .	7196
4274	महाराष्ट्र में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Maharashtra	7196
4275	तांबे की नलियों का आयात	Import of Copper Tubes . .	7196–97
4276	केरल राज्य में थक्कानकुटुर में रेलगाड़ी के रुकने की व्यवस्था	Train Halt at Thekkankuttur in Kerala State	7197
4278	भारत बल्गारिया संयुक्त उपक्रम	Indo-Bulgarian Joint Ventures .	7197
4279	सुखाई गई मछली का श्रीलंका को निर्यात	Export of Dried Fish to Ceylon	7197
4280	ड्राइवर के बिना इंजन	Engine without Driver . .	7198
4281	रेल के डिब्बे	Railway Coaches . . .	7198
4282	राखा तांबा खाने	Rakha Copper Mines . .	7198–99
4283	कपड़े के मूल्य	Price of Cloth	7199
4284	महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Maharashtra	7199
4285	19 डाउन और 20 अप रेल गाड़ि यों का बागरोद में रुकना	Stoppage of 19 Down and 20 UP trains at Bangrod . . .	7200
4286	प्याज का निर्यात	Export of Onions . . .	7200–01
4287	लकड़ी के स्लीपरों में आग लगाया जाना	Burning of Wooden Sleepers .	7201
4288	मांडव (राजस्थान) में फलोराइट की खान	Fluorite Mine at Mandav (Rajasthan)	7201
4289	शयन डिब्बो (स्लीपर कोच) में ताले और चाबी की व्यवस्था	Lock and Key arrangement in Sleeper Coaches	7202
4290	अल्ट्रासानिक रेल फुलों डिटेक्टर	Ultrasonic Rail Flaw Detector	7202

अता० प्र० संख्या U.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4291	यात्रियों को तंग करने की घटना	Harrassment of Passengers .	7202–03
4292	रेलवे के कैरेज खलासियों की ऊनी वर्दियां	Woolen Uniforms for Carriage Khalsis	7203
4293	रेलवे के संगचल कर्मचारियों के लिए वर्दियां	Uniforms for Railway Running Staff . . .	7203–04
4294	रेलवे प्रशिक्षण स्कूल, चन्दौसी	Railway Training School, Chandausi	7204
4295	तीसरी श्रेणी के शयन डिब्बे (स्लीपर कोच)	Third Class Sleeper Coaches .	7204
4296	गोरखपुर में कागज बनाने का कारखाना	Paper Factory in Gorakhpur .	7204–05
4297	गोरखपुर जिले में रद्दी लोह (स्कैप गुड्स) का कारखाना	Scrap Goods Factory in Gorakhpur District	7205
4298	कीरतपुर साहिब स्टेशन पर रेलव गोदाम	Railway Godown at Kiratpur Sahib Station . . .	7205
	समापटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	7206
	प्राक्कलन समिती—	Estimates Committee—	
	एक सौ तीनवां तथा एक सौ चारवां प्रतिवेदन	Hundred and Third and Hundred and Fourth Reports .	7206
	लोकलेखा समिती—	Public Accounts Committee—	
	उनचासवां प्रतिवेदन	Forty-Ninth Report . .	7206
	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
	तीसवां प्रतिवेदन	Thirtieth Report . . .	7207
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re : Motion for Adjournment (Query)	7207
	सभा का कार्य	Business of the House . .	7207
	श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की परिस्थितियों के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Circumstances in which Shri Lal Bahadur Shastri Died	
	डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	7207–08
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	7208–09
	कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
	सैतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-seventh Report . .	7210–12
	अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	
	वैदेशिक कार्य मंत्रालय	Ministry of External Affairs—	
	श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh . . .	7213–14
	श्री हरिश्चन्द्र माथूर	Shri Harish Chandra Mathur	7214–16

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	7218–21
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	7221–23
श्री उ० मु० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	7223–24
श्री बाकर अली मिर्झा	Shri Bakar Ali Mirza . .	7224–25
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya .	7225–26
श्री कृ० चं० पंत	Shri K. C. Pant . . .	7226–27
श्री अन्सार हरवानी	Shri Ansar Harvani . .	7227–28
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee of Private Member Bills and Resolutions—	
छियासिवां प्रतिवेदन	Eighty-sixth Report . .	7228
साम्यवादी चीनके विस्तारवाद को रोकने के लिये प्रशान्त क्षेत्र में एकता के बारे में संकल्प—अस्वीकृत—	Resolution re: Pacific concord against Communist Chinese Expansionism—Negatived—	
श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi . .	7229
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	7229
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi. . .	7229–30
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh . .	7230
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद	Shri Brajeshwar Prasad . .	7230–31
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	7231
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy . .	7231
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . . .	7231–32
श्री खाडीलकर	Shri Khadilkar . . .	7232
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	7232
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	7233
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	7233
श्री बसुमतारी	Shri Basumatari . . .	7233
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	7233–34
श्री रंगा	Shri Ranga	7234–35
आपात की उद्घोषणा तथा भारत रक्षा-अधिनियम के बारे में संकल्प—	Resolution re: Proclamation of Emergency and Defence of India Act—	
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendra Nath Dvivedi .	7235–36

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 22 अप्रैल, 1966/2 वैशाख, 1888 (शक)
Friday, April 22, 1966/Vaisakh 2, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Supply of Imported Goods to Government Offices

+

*1277. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the extent of cut effected in the supply of imported goods to the various Government Offices and Departments on account of Emergency; and

(b) the names of the imported articles which are available from indigenous sources and are being imported in spite of their availability in the country?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पिछले पांच वर्षों में पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय द्वारा जो खरीद की गई उसमें उन विशिष्ट वस्तुओं के आयात के बावजूद जो अत्यधिक तकनीकी और मिली जुली वस्तुएं

थीं, देशी हिस्सा अधिक काफी अधिक रहा। की गई खरीद, देशी और आयातित, के अलग-अलग आंकड़े नीचे दिये गये हैं :--

अवधि	देशी	आयातित (करोड़ रुपयों में)	योग	योग में देशी हिस्सों का प्रतिशत
1961-62 . . .	216	49	259	81
1962-63				
अप्रैल--अक्टूबर, 1962 .	82	19	101	
अक्टूबर, 1962--मार्च, 1963 .	271	33	304	
	353	52	405	87
1963-64 . .	454	100	553	82
1964-65 . . .	357	99	456	78
1965-66				
अप्रल--नवम्बर, 1965 .	217	51	267	81

विदेशी मुद्रा संबंधी कठिन स्थिति का सामना करने के लिये आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का इस्तेमाल निरंतर और अधिक बढ़ाया जा रहा है। आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं की क्षमता उत्पन्न करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विशिष्ट विवरणों में इस प्रकार संशोधन किया जा रहा है जिससे वे देशी निर्माताओं के लिये उपयुक्त बन सकें तथा माल मंगाने वाले विभाग को देशी सामान स्वीकार करने के लिये तैयार किया जा रहा है।

जहां तक स्टेशनरी का संबंध है, सभी आयातित वस्तुओं का सम्भरण रोक देने का निश्चय किया गया है।

(ख) देश में उपलब्ध वस्तुओं के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है।

Shri M. L. Dwivedi : This is a vague answer. I want to know the names of articles being imported so that the House may understand whether these articles are available from indigenous sources or not.

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : मैंने बताया है कि न केवल आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान देश में बनाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है अपितु देश में बनाई जाने वाली वस्तुओं का और अधिक प्रयोग करने के लिये कार्यवाही की गई है। विवरण में दिये गये आंकड़े न केवल लेखन सामग्री से सम्बन्धित हैं, अपितु इसमें बहुत सी वस्तुएं प्रतिरक्षा संभरण से भी सम्बन्धित हैं।

Shri M. L. Dwivedi : Since when the import of Stationery articles has been or is being discontinued?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : पिछले तीन वर्ष से निर्माण तथा आवास मंत्रालय को लेखन सामग्री मंगाने के लिये कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है।

श्री प्र० चं० बरुआ : कुछ सरकारी अधिकारी आयातित कार आदि के भी शौकीन हैं। सरकार अपने कार्यालयों आदि में कब तक पूर्ण रूप से कार तथा अन्य देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करने लगेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : कारों का आयात नहीं किया जाता है केवल प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिए कुछ मोटर गाडियों का आयात किया गया है। मंत्रालयों द्वारा कारों का आयात करने की इच्छा व्यक्त की जाने पर भी उन्हें देश में निर्मित कारें दी जाती हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad : According to the statement, articles worth Rs. 99 crores were imported during the last year and during current year upto November, the import was to the extent of Rs. 51 crores. Is it an increasing trend or decreasing trend? By what time import of these articles will be stopped and what is the programme made by the government to reduce the percentage of import of these articles?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : ये वस्तुएं केवल लेखन सामग्री से ही सम्बन्धित नहीं है। डाक तथा तार विभाग और प्रतिरक्षा की आवश्यकता की प्राथमिकता को ध्यान में रख कर उनके लिए इन वस्तुओं का आयात किया जाता है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि देश के निर्माता उनको दी गई इस चेतावनी की परवाह नहीं करते हैं कि उनके द्वारा संभरण की जाने वली वस्तुएं खराब किस्म की होती हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान की किस्म का निरीक्षण किया जाता है। अन्य विभागों को सप्लाई किये जाने वाले सामान की किस्म की भी जांच की जाती है और उस पर भारतीय मानक संस्था का चिन्ह होता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निर्माता अच्छी किस्म की वस्तुएं बनाएं।

डा० रानेन सेन : निर्माण और आवास मंत्रालय ने निर्णय किया है प्रत्येक मंत्रालय अपने लिये लखन सामग्री स्वयं मंगाये। क्या इस मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को बता दिया है कि अब सभी आवश्यक सामग्री देश में बनी ही मंगाये। बाहर से कोई आयात न किया जाये और यदि हां, तो क्या मंत्रालय उसका पालन कर रहे हैं ? क्योंकि देश में बने सामान का प्रतिशत 1963–64 में 82 से घटकर इस समय 81 प्रतिशत हो गया है। यह समूची व्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रही है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : लेखन सामग्री का थोक संभरण लेखन सामग्री तथा मुद्रण के नियंत्रक द्वारा किया जाता है न कि विभागों द्वारा व्यक्तिगत रूप से। मैं बता चुका हूं कि पिछले तीन वर्ष से निर्माण और आवास मंत्रालय को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है।

Shri Sheo Narain : Which articles are being imported for government offices?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैं इस सम्बन्ध में बता चुका हूं। प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये विशेष प्रकार की मशीनें, जीप की किस्म की मोटर गाड़ियां, मोटर गाड़ी चसिस, ट्रांसमिटर, मोटर गाड़ियों के पुर्जे, बोरिंग मशीनें, टैंक, विमान, बम, हेली कोप्टर, एवियेशन स्प्रिग, जस्ता पिंड आदि कुछ सामान का आयात किया जाता है।

Shri Bibhuti Mishra : Have the Government directed the departments, using imported articles, for import substitution and is there any scheme to give award to those who will use indigenous articles and boycott the imported goods ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : All the departments were instructed, particularly after emergency and even before it, to use indigenous articles and necessary steps are also being taken in this connection. No foreign exchange is allocated to any Ministry for this purpose and therefore they cannot import them.

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि आयातित वस्तुओं को वरीयता देने का वास्तविक कारण यह है कि देशी माल अच्छे किस्म का नहीं होता है ? यदि हां, तो देश में निर्मित माल की किस्म में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विभुघेन्द्र मिश्र : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि इसके लिये किस्म नियंत्रण लागू किया गया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister in his reply has stated that some cars have been imported in some Ministries. May I know how much foreign exchange was incurred for this purpose ? Is it a fact that some machines and spares imported for the use of offices are sold in blackmarket in good condition?

श्री विभुघेन्द्र मिश्र : विदेशी मुद्रा की राशि विवरण में दी गई है ।

श्रीमती सावित्री निगम : अभी मंत्री महोदय ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि पिछले तीन वर्ष से लखन सामग्री का आयात बन्द किया गया है । किन्तु पहले इसी सभा में बताया गया था कि चूंकि नोट छापने का कागज भारत में नहीं बनता है, इसलिये उसका आयात किया जाता है । इनमें से कौनसा उत्तर सही है ? क्या पिछल तीन वर्ष से सभी प्रकार के कागज का आयात बंद कर दिया गया है अथवा नहीं ?

श्री विभुघेन्द्र मिश्र : मने बताया है कि अखबारी कागज और नोट छापने के कागज का आयात किया जाता है ।

मिश्र-इस्पात कारखाने के लिये यैन ऋण

*1278. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री किन्दर लाल :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये यैन ऋण में वृद्धि किये जाने के संबंध में जापान की सरकार के साथ कोई बातचीत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत से कितनी प्रगति हुई है ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether any negotiations have taken place with the Japanese Government for increasing Yen Credit?

Shri P. C. Sethi : The question of expansion of Durgapur Alloy Steel Plant is under consideration. A Japanese delegation came here for this purpose. We had talks with them but the size of expansion has not yet been finalised and we will have negotiations with them after the decision in this connection is taken.

Shri Bhagwat Jha Azad : What was the reaction of Japanese delegation on our request?

Shri P. C. Sethi : I have said that we had no talks about Yen Credit. We confined our talks to the expansion of the Alloy Steel Plant. We will have further talks only after taking a decision about the expansion.

Shri M. L. Dwivedi : What were the proposals put before the Japanese delegation by the Government and what was their reaction on those proposals?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh): The question is not that how the expansion will be effected but what we are considering is that after five years what kind of alloy steel will be produced, what will be its feasibility and what will be its demand. Therefore we will take decision after considering all these things.

श्री स० चं० सामन्त : इस कारखाने के विस्तार के लिये कितना येन ऋण मिलेगा और क्या इसके लिये मिलने वाले येन ऋण के अतिरिक्त और विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता होगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं समझता हूं कि और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी। विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय करने के बाद हमें ऋण मिलेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मिश्रित इस्पात कारखाने का कितना विस्तार किया जायेगा, इस पर कुल कितनी लागत आयेगी और इसमें से कितनी विदेशी मुद्रा होगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : सो० ई० बी० डी० ने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। उनमें 68,000 टन और 1,20,000 टन इस्पात के उत्पादन की क्षमता तक विस्तार करने की बात कही गई है। अब हम इन दोनो प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। सरकार इससे भी अधिक विस्तार करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या जापान की सरकार ने कोई आश्वासन दिया है कि यदि दुर्गापुर कारखाने के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय किया जाता है, तो वह उसके लिये पर्याप्त ऋण देगी अथवा नहीं ?

Shri T. N. Singh : There is no question of giving any assurance. First an outline will prepared for expansion and then we will have negotiations.

श्री राम सहाय पाण्डेय : उत्पादन के लिये क्या तिथि निर्धारित की गई है और विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि विलम्ब के लिये ठेकेदार उत्तरदायी हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह सच है कि कई कारणों से दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने में उत्पादन लक्ष्य तिथि में विलम्ब हुआ है। किन्तु अब कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है। ढलाई घर की हैमर बे लग चकी है। अगस्त, 1967 तक कारखाने में पूरा उत्पादन होने लगेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या अपना उत्तरदायित्व पूरा न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई, और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : विलम्ब के लिये ठेकेदार भी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध सभी संभव कार्यवाही की गई है और अब कार्य की प्रगति संतोषजनक है।

कारों के मूल्य

\+

***1279. श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री 9 अप्रैल, 1965 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बनाई जाने वाली कारों के मूल्य कम करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या निर्माण करने वाली फर्मों के साथ कोई समझौता हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुघेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

जैसा कि 9–4–1965 को पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में बताया जा चुका है कि सरकार द्वारा 10 प्रतिशत विनियमनकारी शुल्क लगा दिये जाने के बाद कुछ निर्माताओं ने 1965 में मूल्य बढ़ा दिये गये थे और निर्माताओं ने ऐसा सरकार की स्वीकृति बिना किया था। मूल्य वृद्धि की सावधानी से सरकार द्वारा जांच की गई और यह पता लगा कि यह मूल्य वृद्धि बहुत अधिक नहीं है। निर्माताओं को सरकार की इस बात पर अप्रसन्नता बता दी गई थी, और उन्होंने सरकार की स्वीकृति के बिना मूल्यों में वृद्धि कर दी थी और इसकी पुनरावृत्ति (तारांकित प्रश्न संख्या 264, दिनांक 27–8–1965 के उत्तर के द्वारा) न करने के लिये उन्हें चेतावनी दे दी गई थी।

कारों के मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रण की एक अनौपचारिक प्रणाली द्वारा निश्चित किये जाते हैं जिसके अधीन तैयार पुर्जों और/अथवा पुर्जों हिस्सों और सामान पर सरकार द्वारा लगाये गये वित्तीय करों में वृद्धि हो जाने से मूल्यों में स्वतः वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार समुद्री भाड़ा, आयातित हिस्सों के मूल्यों तथा आयातित मूल्य में 25 प्रतिशत तक कमी करके देशी उत्पादन की लागत में मूल्य वृद्धि के लिये अनुमति दी जाती है। अन्य वृद्धि के लिये निर्माण करने वाले कारखानों की लागत की सावधानी से जांच करने की अनुमति दी जाती है।

वर्तमान विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति को ध्यान में रखते हुये सरकार ने आयातित पुर्जों में कमी करने तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर दूसरी वस्तुओं का प्रयोग करने पर बल दिया है। निर्माण करने वाले कारखानों के कम उत्पादन, तैयार हिस्सों और कच्चे माल की अधिक लागत तथा सरकार द्वारा लगाये जाने वाले बढ़ते हुये करों को देखते हुये देश में निर्मित कारों के मूल्यों में कमी

करने की बहुत गुंजाइश है। सरकार द्वारा देश में बेची गयी कारों के मूल्यों पर लगातार निगरानी की जा रही है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, निर्माताओं द्वारा मूल्य में वृद्धि करने के दावों की सावधानी से परीक्षा करने के बाद ही अनुमति दी जाती है।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में यह कहा गया है कि :

"कारों के मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रण की एक अनौपचारिक प्रणाली द्वारा निश्चित किये जाते हैं जिसके अधीन . . . . . मूल्यों में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है।

इसमें आगे कहा गया है कि :

"इसी प्रकार समुद्री भाडा, आयातित हिस्सों के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है . . . । अन्य वृद्धि के लिये निर्माण करने वाले कारखानों की लागत की सावधानी से जांच करके ही अनुमति दी जाती है।"

मैं जानना चाहता हूं कि फिएट और एम्बेसडर कारों का लागत मूल्य अथवा उत्पादन मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः क्या है और इनमें कितना अन्तर है तथा सरकार इस अन्तर को किस प्रकार कम करने जा रही है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : वित्त मंत्रालय के कुछ लागत लेखा अधिकारियों ने देश में निर्मित कार के पुर्जों की लागत का अध्ययन किया था। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर सरकार विचार कर रही है और हम इस संबंध में मोटरगाड़ी निर्माताओं से बातचीत कर रहे हैं। मेरे पास एक विवरण है जिसमें तीनों किस्म के कारों के 1962 के मूल्य दिये गये हैं और यह बताया गया है कि 1966 में मूल्य क्यों बढ़े हैं। मुझे अनुमति हो, तो मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : अन्तर क्या है ?

Shri Sheo Narain : What is the difference?

Mr. Speaker : You may place the statement on the Table of the House? What is the difference?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : 1 जनवरी, 1962 को एम्बेसडर कार का एक्स फैक्टरी मूल्य 11,667 रुपये था और 1966 में यह बढ़ कर 13,554 रुपये हो गया। इस वृद्धि के लिये अलग अलग समय पर अलग अलग कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय : विक्रय मूल्य क्या है।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इसमें उत्पादन शुल्क अतिभार तथा अन्य खर्च को जोड़ कर विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है।

श्री भागवत झा आजाद : कितना ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैं नहीं बता सकता हूं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि कितने कर लगाये जाते हैं और मूल्य क्या है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विक्रय मूल्य जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि यह अन्तर करों से पूरा हो जाता है।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैं समझता हूं कि सरकारी कर 33⅓ प्रतिशत से कम नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : इस प्रश्न को स्थगित किया जाये . . . **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जानकारी एकत्रित करके सभा को दे सकते हैं . . . **(अन्तर्बाधा)**

श्री स० मो० बनर्जी : छोटी कारों के निर्माण के सरकार के प्रस्ताव की क्या स्थिति है जो गैर-सरकारी एकाधिपतियों के अत्याधिक मूल्यों को कम करने के लिये तैयार किया गया था ? क्या प्रस्ताव को सदा के लिये स्थगित कर दिया गया है अथवा इसकी क्रियान्विति की कोई संभावना है ।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैं समझता हूं कि इसका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है फिर भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि अभी इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। छोटी कार के निर्माण के संबंध में मंत्रालयों और योजना आयोग में मतभेद है। योजना आयोग का कहना है कि कम प्राथमिकता के कारण, इसमें निवेश नहीं किया जाना चाहिये। हम इस संबंध में मंत्रिमंडल में विचार करेंगे और एक महीने तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

श्री वी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय ने बताया है कि 1965 में सरकार द्वारा 10 प्रतिशत नियंत्रण संबंधी शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप कार निर्माताओं ने मूल्य बढ़ा दिये थे। निर्माताओं ने यह बिना सरकार की अनुमति से किया। सरकार ने इस बात के लिये क्या कार्यवाही की है कि कार निर्माता अनुचित मूल्य न बढ़ायें ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : निर्माताओं पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है किन्तु ऐसी व्यवस्था की गई है। जिससे वे बिना सरकार की अनुमति के मूल्य नहीं बढ़ाते हैं। इस मामले में उन्होंने सोचा चूंकि उत्पादन शुल्क लगाया गया है अतः वे स्वयं मूल्य बढ़ा सकते हैं। बाद में हमने उन्हें बताया कि शुल्क लगाये जाने पर भी वे बिना सरकार की अनुमति के मूल्य नहीं बढ़ा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : सदा यही होता रहा है कि सरकार की अनुमति के बिना ही मूल्य बढ़ा दिये जाते हैं। अतः क्या सरकार ने मूल्यों में और अधिक वृद्धि को रोकने के लिये कुछ कारगर उपायों पर विचार किया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैंने बताया है कि ऐसा केवल एक बार किया गया है। भविष्य में मूल्य बढ़ाने के लिये सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यदि छोटी कार का निर्माण सरकारी क्षत्र में होने लगेगा तो क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इसकी कीमत अधिक न हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव मात्र है ।

श्री दाजी : कार निर्माताओं को कितना मुनाफा मिलता है ? क्या सरकार को पता है कि एक निर्माता को कर देने के बाद चार वर्ष तक 18 प्रतिशत का मुनाफा हुआ ? मैं प्रीमियर आटोमोबाइल की बात कर रहा हूं ।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैं नहीं जानता कि क्या उन्हें मुनाफा होता है। किन्तु हाल ही में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि उन्हें कारों के निर्माण में घाटा हो रहा है।

श्री अन्सार हरवानी : अरब गणराज्य में नासर नामक छोटी कार का कितना मूल्य है और उसी का भारत में कितना मूल्य है ? क्या इसका कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : ऐसा लगता है कि कार निर्माताओं पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। क्या सरकार को पता है कि कारों की किस्म का स्तर उत्तरोत्तर गिर रहा है? पिछले डेढ़ वर्ष से शिकायतें मिल रही है कि फिएट और हिन्दुस्तान कारों की किस्म का स्तर गिर गया है। क्या सरकार का विचार किस्म पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखने का है अथवा उन्हें मुल रूप से विदेशी मुद्रा दी जायेगी और जो चाहें वह करने की अनुमति दी जायेगी?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : नई निर्मित कारों की किस्म के बारे में शिकायत मिलते ही उसकी जांच करने के लिये सरकार के तकनीकी विभाग के कर्मचारी भेजे जाते हैं और वे यह सुनिश्चित करते है कि अच्छी किस्म के अनुसार कार बनाई जाये। अब कारों का आयात नहीं किया जाता है। सी०के०डी० पैक के अतिरिक्त विस्तार अथवा पूंजगत वस्तुओं के लिये आयात करने की अनुमति नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा देते समय मूल्य अथवा कम से किस्म पर कोई नियंत्रण रखा है, और यदि हां, तो क्या नियंत्रण रखा है और उसके लिये कौन उत्तरदायी है?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इसके लिये तकनीकी विकास महानिदेशालय उत्तरदायी है।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know whether Government have any proposal to manufacture the car with cent per cent indigenous components; if so, by what time and, also when the demand of the country is met by internal production?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : देशी पुर्जों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। एम्बेसेडर कार में 90 प्रतिशत फिएट में 83 प्रतिशत तथा स्टैण्डर्ड कार में 76 प्रतिशत देश में निर्मित पुर्जों का प्रयोग होता है। हम दो-तीन वर्ष में पूरी तरह देश में निर्मित पुर्जों से कार बनाने लगेंगे।

इस्पात कारखाने

*1283. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने यह कहा है कि भारत को अब केवल अगले इस्पात कारखानों के बारे में ही नहीं अपितु आधा दर्जन और कारखानों के संबंध में निर्णय लेना होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वे सब स्थान चुन लिये हैं जहां ये कारखाने स्थापित किये जायेंगे?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether Government have selected the places where these plants are going to be located so that there would be no difficulty of the decision is taken?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : So far no decision has been taken about the location of these plants.

Shri Bibhuti Mishra : On the one hand Government want not to locate all the plants at one place and on the other hand they propose to locate the plants at the place where all the resources are available. Keeping in view the security point whether Government have any proposal to select the places so that no dispute would arise among states and districts?

Shri T. N. Singh : In such cases expert is appointed by the Government to examine suitability of the places. We generally take decision on the basis of their recommendation. In genuine cases we accept the recommendations of the expert committee.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या पांचवे तथा अन्य इस्पात कारखानों के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है ? चूंकि यह सुझाव दिया गया है कि बन्दरगाह के निकट का स्थान उपयुक्त होता है, अतः क्या सरकार इसके लिये स्थान के सम्बन्ध में पारादीव सहित सभी बन्दरगाहों के निकट के स्थानों पर विचार कर रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम बन्दरगाहों के शहरों के निकट परियोजना की उपयुक्तता तथा वांछनीयता आदि सभी बातों पर विचार कर रहे हैं। अब तक किये गये अध्ययन में पारादीव शामिल नहीं है। इसके बारे में हमे विशेषज्ञ राय नहीं मिली है। हमने विशाखापट्टनम् और गोआ की व्यवहारिकता पर विचार किया है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार ने इस्पात कारखाने के भावी ढांचों के बारे में सोचा है और क्या वे हिन्दुस्तान इस्पात कारखाने की तरह एक संगठन के अधीन होंगे अथवा प्रत्येक के लिये एक पृथक निगम होगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : माननीय सदस्य सरकारी उपक्रम समिति के चेयरमैन हैं। इस समिति ने इन्हीं समस्याओं के बारे में हमें महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। कोई अन्तिम निर्णय करने से पहले हम इस महत्वपूर्ण मामले के सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करेंगे। हम मामले पर विचार कर रहे हैं और इन सभी बातों पर अच्छी तरह विचार करने के बाद ही कोई निर्णय किया जायेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार इन इस्पात कारखानों की स्थापना के बारे में निर्णय करने से पहले उस समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी जो भारत में इस्पात की उत्पादन लागत के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था और क्या समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद इन इस्पात कारखानों के समूचा ढांचा तैयार किया जायेगा तथा उनका गठन किया जायेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस समिति का कार्य भिन्न है। यह भारत में वर्तमान इस्पात कारखानों के उत्पादन मूल्य ढांचे के सम्बन्ध में कार्य कर रही है। निश्चय ही इस जांच से महत्वपूर्ण निर्णयों को नहीं रोका जा सकता हैं। जहां तक चौथी पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, हम इसके बारे में योजना आयोग के साथ बातचीत कर रहे हैं।

Shri Sarjoo Pandey : May I know in which states and at which places these 12 proposed plants will be located?

Mr. Speaker: The hon. Minister has already answered this question.

Shri Raghunath Singh : It has generally been found that steel plants are set up near shipyard as large quantity is required for shipyard. Do the Government propose to set up a steel plant near Hindustan Shipyard or near Cochin Shipyard or Karwar Shipyard so that the demand of ship may be met ?

Shri T. N. Singh : The hon. Member has a long experience. The case of Vizag is under consideration.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार पंजाबी सूबे में इस्पात कारखाने स्थापित करने के विरुद्ध है; और यदि नहीं, तो क्या वहां पर कोई इस्पात कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम इसके कतई विरुद्ध नहीं हैं ।

श्री मुथिया : क्या श्री कुरेशी की अध्यक्षता में जापानी सर्वेक्षण दल ने, जो गत वर्ष सलेम गया था, सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और यदि हां, तो क्या सरकार ने सलेम इस्पात कारखानें के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जपानी अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और उस पर विचार किया जा रहा है। मैं बता चुका हूं कि समूचे इस्पात कार्यक्रम के बारे में योजना आयोग के साथ बातचीत की जा रही है और उसके बाद ही कोई निर्णय किया जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या सरकार स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिये गये इस आश्वासन का पता है कि जब कोई समिति नियुक्त की जाती है तो सरकार को इस बात का ध्यान रखनी है कि वह समिति के निर्णय के विरुद्ध कार्य न करे; और यदि हां, तो विशाखापत्तनम में पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में मंत्रिमंडल भी कोई निर्णय करेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन का यथासंभव पालन करने का प्रयत्न करुंगा।

Shri K. N. Tiwari : Is it a fact that the steel being produced at present is not consumed and huge undisposed stocks have been accumulated and if so whether Government have considered the possibility of reducing the expenditure and to increase the production in existing steel plants?

Shri T. N. Singh : This is a temporary phase. It is not advisable to finalise the programme on this basis.

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सभी भारतीय तथा विदेशी समितियों ने यह सिफारिश की है कि देश में खपत के लिये होस्पेट में सबसे अधि लोह आयस्क है इस लिये हासपेट में इस्पात कारखाना काफी सफल रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether a steel plant can be set up in Mahendragarh district of Hariyana and whether it is under Government's consideration?

Shri T. N. Singh : A licence has been given to Punjab Government to set up a pig iron plant there.

यूरोपीय आर्थिक समिति

+

*1284. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समिति ने साझा बाजार के सदस्य देशों में नि:शुल्क चाय जोन से सम्बधित व्यवस्था का विस्तार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने समय के लिये; और

(ग) जब से रियायत दी गई, 1964–65 में साझा बजार के सदस्य देशों को कितनी मात्रा में भारतीय चाय का निर्यात किया गया; और पिछले दो वर्षों में निर्यात की गई भारतीय चाय की तुलना में यह निर्यात कितना अधिक अथवा कम था और आगामी वर्ष में इन निर्यातों में कितनी वृद्धि होने की आशा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख) : जी, हां। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने चाय पर लगने वाले सीमा शुल्क के स्थान की वैधता अवधि जो पहिले 31 दिसम्बर, 1965 को समाप्त होने वाले दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावकारी थी, को एक वर्ष अर्थात 31 दिसम्बर, 1966 तक के लिये और बढा दिया।

(ग) 1962–63 में 336 लाख रुपये की 52 लाख किलोग्राम और 1963–64 में 321 लाख रु० की 48 लाख किलोग्राम चाय के निर्यात की तुलना में 1964–65 में भारत ने यूरोपीय साझा बाजार के देशों को 378 लाख रुपये की 56 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया। यूरोपीय साझा बाजार के देशों द्वारा चाय के आयात पर लगने वाले शुल्क के स्थगित रखने और निर्यात को बढाने के लिये किय गये प्रयासों में वृद्धि करने से, आशा है कि आगामी वर्ष में यूरोपीय साझा बाजार के देशों को चाय के निर्यात में अतिरिक्त वृध्दि होगी।

श्री प्र० चं० बरुआ: यूरोपीय साझा बाजार में भारत की चाय में कौन कौन से बडे प्रतियोगी देश है और क्या उन देशों से सीमा शुल्क के स्थागनकी वैधता के बाद चाय का निर्यात बढ़ गया है; यदि हां, तो किस देश से और उसकी मात्रा क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत है। या यह 60 लाख रुपये के बराबर है। मुख्यत: यह जर्मनी, फ्रान्स और इटली हैं।

श्री रंगा: प्रश्न अन्य देशों के बारे में था कि जो साझा बाजार में शामिल हो गये हैं।

श्री मनुभाई शाह : रोम की संधि के अन्तर्गत 6 देश है। उनमें से मुख्यत: जर्मन और इटली हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : चाय बोर्ड की पूरी कोशिश के बावजूद चाय के निर्यात की कमी के होने में कमी नहीं हुई है। आज हमारा निर्यात ब्रिटेन को कम होता जा रहा है। क्या सरकार चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क को वापिस करने पर पुनर्विचार करेगी ताकि साझा बाजार के देशों में चाय उचित मूल्य पर जा सके और प्रतियोगी देशों का मुकाबला कर सके ?

श्री मनुभाई शाह: माननीय महोदय को चाय के बारे में काफी अनुभव है। यूरोपीय साझा बाजार में भारत की चाय बहुत कम जाती है। हमारा बाजार तो ब्रिटेन में है और वह देश साझा बाजार का सदस्य नहीं है। यह प्रश्न तो यूरोपीय साझा बाजार से सम्बन्धित है। भारत से बहुत थोड़ी मात्रा में चाय साझा बाजार देशों में जाती है। परन्तु साझा बाजार से हम बहुत रुचि रखते है और मैं सदन को बता चुका हूं कि सीमा-शुल्क के स्थगन से हमें 60 लाख रुपये का लाभ हुआ है और 2 वर्षों से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह संतोषजनक काम है।

Shri M. L. Dwivedi : The hon. Minister has said that suspension of custom duty is being extended for one year. I want to know whether Government is considering this suspension on permanent basis.

Shri Manubhai Shah : We can only request for suspension. We hope there would be permanent suspension. The economic policy of E. C. M. has not yet been

finalised. It is under consideration. That is why they have not abolished this duty permanently. We hope that all the countries of Rome Treaty will bring this at zero tarrif permanently.

श्री भागवत झा आजाद : क्या माननीय मंत्री का ध्यान विदेशी समाचार पत्रों के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है और वह यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होना चाहता है। इससे राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों को बहुत हानि होगी; यदि हां तो सराकर इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

श्री मनुभाई शाह : ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने के बारे में राष्ट्रमंडल व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन ने दो वर्ष तक कहा है कि साझा बाजार में जाते समय ब्रिटेन को विकास शील राष्ट्रमंडलीय देशों को कैसी सुविधाएं दिलानी चाहिये जो पहले से ही उपलब्ध है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या विश्व के निर्बाध व्यापार वाले देशों में किसी ओर देश को भी रियायत मिली है ; यदि हां, तो क्या उनकी निर्यात में भी वृद्धि हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक चाय का संबंध है ऐसे चार देश है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है वैसी सुविधाएं सभी को मिलेंगी।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

+

*1286. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री फिरोडिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय संकट के कारण जो कुछ कपड़ा मिल बन्द हो गये हैं अथवा बन्द होने वाले हैं उनके कामकाज को जांच करने के लिये कुछ मंत्रालयों के पदाधिकारियों की एक समिति हाल में बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी हां। इस उद्देश्य से अन्तर्मन्त्रालय समितियां नियुक्त की गयी हैं।

(ख) प्रतिवेदनों के शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : जहां तक अच्छी किस्म के कपड़े के उत्पादन का सम्बन्ध है अधिकांश कपडा मिले अच्छा काम कर रही हैं परन्तु कुछ मिले बन्द हो गई हैं और कुछ बन्द होने वाली हैं। सरकार इस बात के लिये क्या ठोस कार्यवाही करने वाली है जिससे कि उत्पादन कम न हो और मजदूर बेरोजगार न हों ? जिस समय मिलें बन्द होती है मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और तब मजदूरों की कोई परवाह नहीं करता।

श्री शफी कुरेशी : इसी कारण हमने हस्तक्षेप किया है। हमने उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत एक समिति नियुक्त की है जो मिल के कार्यों की जांच करेगी तथा देखेगी कि क्या मिल वित्त के अभाव के कारण अथवा कुप्रबन्ध के कारण

कार्य नहीं कर रही है। बेरोजगारी को मुख्य समस्या को भी ध्यान में रखा गया है। इसी लिये हमने हस्तक्षेप किया है जिससे कि लोगों की जबरण छुट्टी न हो सके और कि उनको बेरोजगार न किया जा सके।

श्री राम सहाय पाण्डेय : समिति का नियुक्त किया जाना ठीक है परन्तु यह छलावा मात्रा है। जब कभी भी प्रश्न उठता है तो समिति नियुक्त कर दी जाती है। जिस समय मिल बन्द होती है और मजदूर बेरोजगार होते हैं उस समय सरकारने मजदूरों की सहायता के लिये क्या ठोस कार्यवाही की है? क्या मजदूरों की सहायता के लिये सरकारने कोई योजना बनाई है ?

श्री शफी कुरेशी : प्रश्न यह है कि जिस समय सरकार मिल को अपने अधिकार में लेती है तो मजदूरों को उनकी अवशिष्ट मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार मजदूरों को हानि नहीं होती।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the attention of the Government have been drawn to the statement of Shri Ruia in Bombay that unless Government reduces the rate of dearness allowance the Mills would continue to be closed? I would also like to know the reasons for not taking over such Mills and allowing them to be threatened like that?

Shri Shafi Qureshi : There is no question of our being afraid of. We are keeping a strict watch on it. As soon as we find that the Mill owners are deliberately closing the Mill we will take necessary action.

Shri Tulsidass Jadhav : The Sholapur Spinning and Weaving mill is not functioning for the last two and a half year. Two committees were appointed to go into the affairs of this Mill. Both the Committees have already presented their reports. Now it is learnt that a third Committee is being appointed. I would like to know the action taken by Government in regard to this Mill during the last three years. The steps taken by Government to re-employ the labourers rendered unemployed as a result of the closure of this Mill.

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : First of all this Mill was taken over by the Maharashtra Government in 1951 or 1952 under the Employment Relief Act. Thereafter a committee was appointed under the industries Act but that was not the responsibility of the centre. Even then correspondence has been done with the Maharashtra Government on this subject.

श्री रंगा : यह तो एक रोगी बच्चे की तरह है।

श्री मनुभाई शाह : यह उस बच्चे की तरह है जो स्थायीरूप से रोगी है परन्तु माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि कपड़य उद्योग के इस बीमार बच्चे को सदा के लिये अपने अधिकार में ले लेना चाहिये तथा इस के स्थान पर एक बड़ी तथा आधुनिक मशीनों वाली मिल लगाई जानी चाहिये। हमने महाराष्ट्र सरकार को यह बता दिया है और उन्होंने हमारे इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is a problem of the closure of Mills and there is also a problem that the Mills are running into loss. May I know the suggestion of the Government to solve these two problems? May I also know whether Government would consider to give the labourers due share in the management as well as in the profit so that the production is increased and also the Mills function in the proper way?

Shri Manubhai Shah : We want that the labourers get due share in management and in profit. There is a different system for different set of units. That has no concern with this.

श्री तिमय्या : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बंगलौर की दो कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं और कि मजदुरों ने भूख-हड़ताल कर रखी है? यह राज्य सरकार के लिये बहुत चिन्ता का विषय है। विधान सभा के सदस्य भी इस विषय पर क्षुब्ध है और वे चाहते हैं कि मिलों को सरकार अपने अधिकार में ले लें। क्या सरकार ने इस स्थिति को सुधारने हेतु कोई कार्यवाही की है अथवा राज्य सरकार को इस बारे में कोई सुझाव दिया है।

श्री मनुभाई शाह : यदि उचित जांच के पश्चात यह पता लगा कि यह एकक आर्थिक रूप से कार्य करने योग्य है तो राज्य तथा केन्द्रीय सरकार इसको अपने अधिकार में ले लेगी।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि अधिकांश मिलें कुप्रबन्ध तथा प्रबन्ध में भ्रष्टाचार होने के कारण बन्द हो गई है? यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार उन मिलों को अपने अधिकार में लेने अथवा कम से कम समवाय विधि प्रशासन के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने मे इतना विलम्ब कर रही है?

श्री मनुभाई शाह : हमने तुरन्त कार्यवाही की है।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : क्या तुरन्त कार्यवाही की है? वर्षों से यह मामला लटक रहा है?

श्री मनुभाई शाह : 600 या 700 एककों में से केवल 19 एकक बन्द हुए हैं। सभा इस बात को सराहना करेगी कि इन 19 एककों में से सरकार 14 एककों को अपने अधिकार में ले लिया है। शेष मिलों में 50,75 अथवा 100 वर्ष पुरानी मशीने लगी हुई हैं। पुरानी मशीनों तथा कुप्रबन्ध के कारण उत्पादन बहुत कम है और इस प्रकार ये मिलें पूर्णतया खराब हैं इसलिये इनको बन्द ही कर दिया जाना चाहिये।

श्री रामनाथन चेट्टियार : गत सप्ताह वाणिज्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वह स्टेट बैंक को ऐसी मिलों की वित्तीय सहायता का निदेश नहीं देंगे जिनको वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। माननीय मंत्री बतायेंगे कि उनके विचार में ऐसी दूसरी कौन सी एजन्सीयां है जो ऐसी मिलों की सहायता कर सकती हैं जिनको वित्तीय सहायता की आवश्यकता है?

श्री मनुभाई शाह : ऐसा लगता है कि सरकार क्षेत्र में स्थापित किये गये स्वायत्त निगम को स्वायत्तता से सभा इर्षा करती है। यदि स्टेट बैंक वित्त नहीं देता है तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हमने सदा यह निर्णय कर लिया है कि हम अपनी निदेश जारी करने की शक्तिका प्रयोग नहीं करेंगे। परन्तु जहां पर इन मिलों को रहा रखना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है तो हम ऋण देने अथवा न देने की बात स्वायत्त निकायों पर छोड़ देते हैं।

Shri Ragunath Singh : A cotton mill in my Varanasi Constituency is lying closed for the last 12 years; whether Government would be kind enough to take it over?

Shri Manubhai Shah : It may now be written off.

श्री रानेन सेन : कपड़ा मिलों के पश्चात अब जूट मिलें भी बन्द होना आरम्भ हो गई हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि इस बात की जांच के लिये मंत्री स्तर की एक समिति नियुक्त की गई है। क्या मंत्री महोदय को विदित है कि दूसरी जूट मिलों के साथ साथ कलकत्ता की

लक्ष्मी नारायण जूट मिल भी धीरे धीरे बन्द हो रही है। इसके क्या कारण हैं यह केवल मिल मालिक ही जानते हैं। यदि यह सच है तो इन मिलों के विशेषकर लक्ष्मी नारायण जूट मिल के बन्द होने के बारे में क्या कार्यवाही की है।

श्री मनुभाई शाह : जहां तक जूट उद्योग का सम्बन्ध है उसमें लगातर विस्तार हो रहा है और इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन हुआ है। सच यह है कि केवल इसी उद्योग में तीसरी योजना के लक्ष्यों से भी अधिक उत्पादन किया है। जहांतक लक्ष्मी नारायण जूट मिल्स का सम्बन्ध है उनके मालिक लगातार बदल रहे हैं। केवल कानपुर की महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बन्द होने का खतरा है जिसे कार्य की एक समिति जांच कर रही है।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know the instructions given to this committee consisting of the official of this Ministry for investigation? Is it a fact that they have also been given instructions to see whether in the present circumstances the existing law which have been referred to by the Deputy Minister is quite sufficient to deal with or any improvement is needed therein?

Shri Manubhai Shah : There is no defect in the law or with implementation. Government is powerful enough but it does not mean that this power should be misused. (**interruptions**)

Whatever power is required to be used and wherever it is to be used is being used fully and I can say that this is the only country where Government interferes so freely in the management of the industry. I had stated last time that we want these industries Act to be further amended so as to take over the Mill or industry which has been mismanaged and taken over by the Government for not running it smoothly instead of handing it over to the previous owners.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कानपुर के अधिकांश कपड़ा बनाने वाले एकक, जिनमें वह मिल भी शामिल है, जिसका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है, मध्यम श्रेणी का तथा मोटे कपड़े का उत्पादन करते हैं और कि ये मिलें बहुत पुरानी हैं? इसको देखते हुए क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अथवा सरकार ने कानपुर में कपड़े की दो नई मिलें लगाने के लिये अनुज्ञा मांगी है और यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकारने अनुज्ञा दे दी है या नहीं?

श्री मनुभाई शाह : हमने ही यह सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था कि कानपुर की समस्या की यही हल है कि वहां पर कपड़े की दो आधुनिक मिलें लगाई जाये ताकि पुरानी मिलों का स्थान नई मिलें ले सकें। जैसे ही ये प्रस्ताव हमारे पास आयेंगे हम इनकी मंजूरी दे देंगे।

श्रीमती सावित्री निगम : एक ओर तो समिति नियुक्त की गई है और दूसरी ओर एक के बाद एक कपड़ा मिल बन्द हो रही है। मेरे विचार में किसी भी समिति के नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जानते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी राय दे रही है। उनको अपना प्रश्न पूछना चाहिये।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं जानना चाहती हूं कि समिति नियुक्त करने तथा मामले में विलम्ब करने की बजाय सरकार इन मिलों के प्रबन्ध को अपने अधिकार में क्यों नहीं लेती और जिन राज्य सरकारों ने मिलों को अपने अधिकार में ले लिया है उनका समर्थन क्यों नहीं करती, उदाहरणतया कानपुर की म्यूर मिल्स सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त राशि क्यों नहीं दी जिससे कि वह इस मिल को आधुनिक बना सकती तथा इसको अच्छे तरीके से चला सकती?

श्री मनुभाई शाह : जैसा मैंने बताया हमने 14 मिलों को वित्तीय सहायता दी है। दस दूसरी मिलों को मद्रास, महाराष्ट्र और गुजरात की स्थानीय सरकारें सहायता कर रही है। जहां पर विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच किये जाने पर यह मालूम पड़ता है कि राशि सुरक्षित नहीं है वहां पर समिति बनाई जाती है। प्रत्येक मिल का अलग अलग उद्देश्य है उनके ऋण सम्बन्धी राशि अलग अलग है। इसलिये प्रत्येक चीज की जांच करना आवश्यक है जहां पर हम देखते है कि सहायता देना लाभदायक है वहां पर हम अवश्य ही सहायता देते है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just now stated that many Mills are closed. I would like to know whether Government is considering to give some interim relief to workers before the findings of the Committee where the Mills have already been closed.

Shri Manubhai Shah : As the hon. Member is aware there is a provision in the Industries Disputes Act far giving lay off compensation to those employees who have rendered at least ten years service. Ten years back this Act was passed by this House.

Shri Tulsidas Jadhav : The hon. Minister has just now stated that lay off compensation is given to the labourers. But in the Sholapur Mills which has been mentioned by hon. Minister, workers have neither lay off compensation nor funds & society nor the owners have given thier own share of Provident fund. Workers have tried their best but they could not get anything. I would like to know the action proposed to be taken by Government?

Shri Manubhai Shah : Law is very powerful. If the concerned labour Union approaches the Provident Fund Commissioner or the Industrial Labour Commissioner they will get all those funds even if the Commissioners might have to liquidate the property of the Mills.

Shri Tulsidas Jadhav : Nothing has been given so far.

Shri Manubhai Shah : You should try for that.

औद्योगिक बस्तियां

***1288. श्री रा० बरुआ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में औद्योगिक बस्तियों के विकास के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में योगदान देने के लिये औद्योगिक बस्तियों को सशक्त बनाने की कोई योजना आरम्भ की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभूघेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 6120/66।]**

श्री रा० बरुआ : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि 1956 में जब औद्योगिक बस्तियां संबंधी कार्यक्रम आरम्भ किया गया था तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 1965 के अन्त तक विभिन्न राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों द्वारा 442 औद्योगिक बस्तियां की स्थापना का

कार्य आरम्भ किया गया था परन्तु उनमे से केवल 180 बस्तियों का कार्य ही पूरा हो सका है और इन में से केवल 75 प्रतिशत बस्तियां तो उत्पादन करने की स्थिति में हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि प्रगति इतने धीरे क्यों हो रही है?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : धीमी प्रगति का कारण निधि का अभाव नहीं बल्कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के सबन्ध में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उस कारण राज्य सरकारें अधिक सावधानी से कार्य करना चाहती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी क्षेत्र के उत्पाद

*1280. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **उद्योग** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1252 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के कुछ उत्पादन की मांग में कमी के क्या कारण है;

(ख) क्या इन उत्पादों के लिये निर्यात-स्रोत ढूंढ़ने की संभाव्यताओं का पर्याप्त रूप से पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : प्रश्न संख्या 1252 के उत्तर में पाइप प्लांट राउरकेला, तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० के कोयला धोने के कारखानों; राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, और खनन तथा सम्बंधित मशीन निगम में क्षमता का कम उपयोग उत्पादों की मांग में कमी होना बताया गया था।

(क) तेल उद्योग के पाइप संयंत्र द्वारा निर्मित पाइपों की मांग में अस्थायी तौर पर कमी आ गई है। कोयला धोने के कारखानों की मांग में कमी अब नहीं रही है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा खोदे गये कोयले तथा खनन और सम्बद्ध मशीन निगम द्वारा तैयार की गई मशीनों की मांग हमारी कोयला खानों द्वारा अच्छे किस्म के कोयले की खपत में कमी हो जाने के कारण अभी भी कम है।

(ख) और (ग) : आस्ट्रेलिया के लिये पाइप लाइनों का निर्यात करने के वास्ते प्रयत्न किए जा रहे हैं। वर्गीकृत कोयले के निर्यात की मांग बहुत कम है जिसके लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की क्षमता बेकार पड़ी है। खनन मशीनों के निर्यात के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं।

संयुक्त अरब गणराज्य से टेलिविजन सेटों का आयात

*1281. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के भारत-संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार करार के अन्तर्गत संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत को अपने देश में निर्मित टेलिविजन बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त अरब गणराज्य ऐसे कुल कितने टेलिविजन सेट देगा; और

(ग) उसकी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : संयुक्त अरब गणराज्य के टेलिविजन सेट निर्यात संगठन का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि हाल ही में भारत आया था। उसने तकनीकी विशिष्टियों, मूल्य, माल देने की शर्तों आदि को प्रारंभिक बातचीत राज्य व्यापार निगम के साथ कर ली है। सभी विषयों पर सन्तोषजनक फैसला हो जाने के बाद लगभग 1000 से 1500 तक सेट दिये जा सकते हैं। परन्तु वास्तविक संख्या तथा शर्तों का पता केवल बात-चित के दौरान ही चल सकेगा।

कतरन से इस्पात पिण्डों का निर्माण

*1282. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतरन से इस्पात पिण्ड बनाने के लिये तीन 'कानकास्ट युनिट' स्थापित करने के लिये आशय पत्र दे दिये हैं।

(ख) यदि हां, तो ये युनिट कहां स्थापित किये जायेंगे और उनकी अनुमानित सम्मिलित उत्पादन-क्षमता कितनी होगी; और

(ग) क्या ये यनिट गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दो इकाइयां बम्बई में और तीसरी इकाई आर्कोनम (मद्रास राज्य) में स्थापित करने का प्रस्ताव हैं। इन तीनों इकाईयों की कुल क्षमता 230,000 टन के लगभग है।

(ग) मद्रास की इकाई राज्य सरकार की योजना है तथा दूसरी दो इकाइयाँ गैर सरकारी क्षेत्र में होंगी।

खादी का उत्पादन

*1285. **श्री रामचन्द्र उलाका** :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी का उत्पादन काफी गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) चालू वर्ष में खादी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कच्चे पटसन के मूल्य

*1289. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि हाल के महीनों में कच्चे पटसन के मूल्य बढ़ जाने से उद्योग को हुए घाटे को देखते हुए अधिक कर-समंजन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : जी, हां। इस विषय में सरकारी निर्णय शीघ्र घोषित किये जाने की आशा है।

इस्पात का निर्यात

*1290. **श्री फिरोडिया** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को तीन लाख टन इस्पात का जिसमें रेल की पटरियां तथा पाइप भी शामिल है निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा; और

(ग) यह निर्यात किन शर्तों पर किया जायेगा ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) अस्थायी रूप से 1966-67 में लगभग 500, 000 टन तैयार इस्पात का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात किये जाने वाले इस्पात में गोल छड़ पत्ती, रेल की पटरी, ढांचे, 10-14 गेज की चादर, पारेदार पट्टियां और बिलेट की थोड़ी मात्रा सम्मिलित है।

(ख) और (ग) : इस समय यह बताना समयपूर्व होगा कि निर्यात किन किन देशों को किया जाएगा और निर्यात की शर्तें क्या होंगी। ये बातें बहुत हद तक विभिन्न देशों की मांग और वहां की मण्डियों की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं।

निर्यात कर्ताओं के सार्थ-संघ

*1291. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मुदलियार समिति" ने निर्यातकर्ताओं के सार्थसंघों को विशेष सुविधाएं दिये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) क्या निर्यातकर्ताओं के किन्हीं सार्थ-संघों को अब तक कोई विशेष सुविधाएं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सुविधाएं दी गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : जी हां।

(घ) निर्यातक सार्थ-संघों को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित की जाती हैं। गत वर्षों में इन सुविधाओं के अंतर्गत, विश्वभर को या एक क्षेत्र को निर्यात करने का एकाधिकार, निर्यात सम्बर्द्धन के लिये विपणन विकास निधि से सहायता और निर्यात के सौदों के सम्बन्ध में विदेशों के दौरे करने के लिये विदेशी मुद्रा और सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित रहे हैं।

Visit of Four Member Railway Team to America

*1292. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Daljit Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Firodia :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a four-member Railway team went to America on the 8th April, 1966 to obtain credit;

(b) if so, the particulars thereof; and

(c) the purpose for which the credit would be utilised?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes Sir.

(b) & (c). The team is to discuss with the International Development Association (an affiliate of the World Bank) the terms of a credit to cover the foreign exchange payments necessary for the Railway programme, principally for component parts of rolling stock and electrification, signalling, workshop machinery, etc. after taking into account other (bilateral) finance available for meeting the cost of railway stores and components.

खान तथा धातु मंत्रालय के अधीन बिजली घर

*1293. **श्री पे० वेंकटासुब्बया :** **श्री प० ला० बारुपाल :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री तिरुमल राव :**

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तथा पूर्णतया उसके द्वारा वित्तपोषित बिजलीघरों के नाम क्या है ?

(ख) क्या इन बिजलीघरों में पैदा की जाने वाली बिजली पड़ोसी राज्यों को दी जा रही है और यदि हां, तो किन किन राज्यों को; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) दो इस प्रकार के विद्युत् केन्द्र राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन तालचर और गिरिदीह में तथा एक नयवेली लिगनाइट निगम के अधीन है ।

(ख) और (ग) : तालचर के पास अतिरिक्त शक्ति नहीं है तथा गिरिदीह का विद्युत् केन्द्र बंद किया जा रहा है। नयवेली विद्युत् केन्द्र से नयवेली उद्योग-समूह (काम्पलैक्स) की आवश्यकता पूरी होने पर अतिरिक्त शक्ति मद्रास ग्रिड को दी जाती है।

Picketing by Milkmen

*1294. **Shri Balmiki :** **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Daji :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some milkmen from Uttar Pradesh and workers of the 'Khoya Union' have been picketing since the 3rd April, 1966 in front of his bungalow in New Delhi to protest against the behaviour of the Government Railway Police;

(b) if so, the nature of their demands; and

(c) the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) About 15 persons claiming to be milkmen from U. P. came to the Railway Minister's residence on 3-4-66 and, when told that the Minister was away on tour, squatted on the pavement opposite the residence till the Minister, on return, met them on the morning of 4-4-66, when they dispersed after his assurance that their grievances would be looked into.

(b) Their demands consisted of earlier departure of 2 ATD Passenger, punctual running of trains used by them unjustified action of Controller on duty at Tundla in detaining their train etc.

(c) AATD Passenger is being started earlier from 1-4-66 to the extent feasible. Punctual running of trains used by milkmen is being closely watched and every effort is being and will continue to be made to ensure punctual running of trains. The action of the Controller on duty at Tundla, on inquiry, was found justified.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के घड़ी बनाने के कारखाने का बन्द होना

*1295. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के घड़ी बनाने के कारखाने को पुन: बन्द करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इस कारखाने के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ग) उन कर्मचारियों को रोजगार देने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

इमारती इस्पात

*1296. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है जिसमें परिषद् ने यह सिफारिश की है कि यदि भारतीय मानक संस्थान द्वारा तैयार किये गये मानकों पर अमल किया गया तो इमारती इस्पात की बहुत बचत हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मानक संस्था के कुछ संशोधित मानकों पर पहले ही अमल किया जा चुका है ; जहां तक दूसरों पर अमल करने का प्रश्न है इस्पात के बड़े बड़े उत्पादकों और भारतीय मानक संस्था की बैठकें बुलाई जा रही हैं जिनमें उत्पादकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर विचार किया जा सके और उन्हें दूर किया जा सके। ऐसी आशा है कि इन कठिनाइयों को दूर करने के बारे में निर्णय शीघ्र ही हो जायेगा।

Prices of Goods

***1297. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri P. C. Borooah :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any efforts are being made to make up the difference in prices of goods produced by the Indian industrialists and foreign goods of the same standard so that goods manufactured in India can be sold in foreign countries at competitive prices;

(b) the basic reasons for high prices of goods manufactured in India while in foreign countries the goods of the same standard are available at cheaper rate; and

(c) the type of goods manufactured in India which are not able to find market abroad due to higher prices ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) Some of the reasons for high prices of goods manufactured in India are:

(i) Sheltered market;

(ii) Too much increasing demand of commodities in comparison to their production in the country.

(iii) Less economic sizes of units of manufacture.

(iv) Use of worn out machinery and lack of adequate progress in modernisation and automation.

(v) Shortage of raw materials.

(vi) High labour costs.

(vii) Difficulties of finance.

(viii) Higher freight charges; and

(ix) Special facilities afforded in competing countries.

(c) Competition in international markets is most keen in the case of manufactured goods.

तेल शोधक कारखाने के लिये उपकरण बनाना

*1298. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 788 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य वस्तुओं के साथ साथ तेल शोधक कारखाने के उपकरण बनाने की परियोजना स्थापित करने के संबंध में तकनीकी परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : तकनीकी रिपोर्ट के मिलने के बाद से पूंजीगत उपकरण तथा पूर्ति के साधन इत्यादि के बारे में कुछ पूरक आंकड़े भी प्राप्त हो गए हैं। इनकी जांच की जा रही है। इस सयंत्र में 2,20,000 टन वैसल, हीट एक्स्चेंजर तथा पाइप फैब्रीकेशन इत्यादि का उत्पादन होगा। इस परियोजना पर कुल अनुमानित लागत 1025 लाख रु० (टाउनशिप को छोड़ कर) आयेगी। इसमें से 250 लाख रु० विदेशी मुद्रा में होगा।

काजू का निर्यात

*1299. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पुर्तगाली उपनिदेशों तथा पूर्वी अफ्रीका के देशों में यंत्र-चालित काजू कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं जो उन देशों में पैदा किये जाने वाले काजू को खपत कर लेंगे और भारत को काजू के निर्यात की कम गुंजायश रह जायेगी ;

(ख) उपरोक्त देशों से होने वाले आयात पर निर्भरता कम करने तथा काजू के उत्पाददों के निर्यात के वर्तमान स्तर को बनाये रखने अथवा बढ़ाने के हेतु देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) काजू का निर्यात बढ़ाने के लिये अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) काजू के देशी उत्पादन को चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक 1.35 लाख मी० टन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3.28 लाख मी० टन करने की योजना बनायी गयी है। चौथी योजना में 4.5 लाख एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र में काजू के पौधे लगाये जायेंगे। ये पौधे पांचवी योजना की अवधि में फल देंगे।

(ग) इस समय एक विशेष निर्यात संवर्धन योजना चालू है जिसके अधीन काजूगिरी निर्यातकों को विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है, जैसे कच्चा काजू, बक्सों के पट्टे, अस्तर की

सामग्री, मशीनों और फालतू हिस्सों आदि का आयात। इस योजना के अन्तर्गत टीन की चादरों का भी सम्भरण रियायती कीमतों पर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त एर्नाकुलम में काजू निर्यात संवर्धन परिषद भी स्थापित है। काजू निर्यात संवर्धन परिषद के एक विदेश कार्यालय ने 1-1-65 से ब्रुसेल्स में काम करना शुरू कर दिया है जो पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र, जोकि काजू की गिरी का एक सम्भावित बाजार है, में संवर्धनात्मक कार्यों की देखरेख करता है।

आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण किया जाना (इम्पोर्ट सब्स्टीट्यूशन)

*1300. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री फिरोडिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग में आधुनिक तकनीक के नए तरीकों तथा आयत की जाने वाली वस्तुओं के देश में बनाए जाने के उपायों का आविष्कार करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) जी, हां। आविष्कार संबंधी प्रतिभा को प्रेरित करने तथा आयात होते वाली वस्तुओं के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड ने निम्न तरीके लागू किए हैं:

(1) उत्कृष्ट आविष्कारों के लिये पुरस्कार प्रतियोगिताएं जो वर्ष में दो बार होगी, तथा

(2) आविष्कारों को बढ़ावा देने के काम में औद्योगिक उद्यमों द्वारा भाग लेने की एक योजना।

(ख) इन दो योजनाओं की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :

(1) पुरस्कार प्रतियोगिता में उन आविष्कारों के लिये पुरस्कार दिया जाएगा जो पेटेंट के योग्य हों या पिछले पांच वर्षों से पहले जिनका पेटेंट न किया गया हो तथा ये या तो

(क) एक मूल उत्पाद या प्रणाली; अथवा

(ख) वर्तमान उत्पाद या प्रणाली में उसकी उपयोगिता बढ़ा कर अथवा लागत घटा कर या दोनों ही प्रकार से सुधार; या

(ग) आयातित उत्पाद या प्रणाली के स्थान पर प्रयुक्त होने योग्य हो; तथा आविष्कार देशी निर्माण के रूप में होना चाहिये और यथासम्भव भारतीय माल से होना चाहिये।

(2) उद्यम में भाग लेने की योजना में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के निजी उद्यमों को आमन्त्रित किया जाता है। वे अपने कर्मचारियों के उन उत्पाद या प्रणालियों के लिए सुझाव दे सकते ह जिनकी तकनीकी दल द्वारा स्वयं या आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड की सहायता से बनाए गए दल ने जांच करली हो। यदि तकनीकी दल इन सुझावों को अमल के योग्य समझता है तो उनके विकास की रूपरेखा तैयार करली जाती है और लागत का अनुमान लगा लिया जाता है। इसके बाद उद्यम को अपना सुझाव पूर्ण विवरण तथा तकनीकी दल की तमाम सिफारिशों के साथ आविष्कार सम्वर्द्धन बोर्ड के सामने उसके द्वारा विचार करने तथा वित्तीय सहायता देने के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है।

लाइसेंसों का दिया जाना

*1301. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **उद्योग** मंत्री 25 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों को लाइसेंस देने की नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की आशा है; और

(ग) पहली नीति में क्या त्रुटियां है जिन्हें दूर किये जाने का विचार हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : ये प्रस्ताव विचाराधीन है। शीघ्र ही कोई निर्णय किये जाने की आशा है।

महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर

*1302. **श्री स० मो० बानर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर के कामकाज की जांच करने के लिये समवाय के कामकाज का एक सर्वेक्षण दल नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक जांच पूरी हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। वाणिज्य मंत्रालय, कम्पनी ला बोर्ड और उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों का एक सर्वेक्षण दल मे० महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया है।

(ख) जांच पूरी हो चुकी है आर दल का प्रतिवेदन सरकार को अभी प्राप्त हुआ है तथा वह विचाराधिन है।

पोलेंड का प्रतिनिधि मंडल

*1303. **श्री फिरोडिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलेंड के विदेश व्यापार मंत्री दिल्ली के निकट कुछ फैक्टरियां देखने गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह सिफारिश की थी कि उन फैक्टरियों में बनी कुछ वस्तुओं का निर्यात उनके देश को किया जाये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : पोलंड के विदेश व्यापार मंत्री ने दिल्ली के निकट ट्रैक्टर, कृषि-उपकरण, मोटरें, रेल के अनुषंगी हिस्से आदि का निर्माण करने वाले कारखानों का निरीक्षण किया और उनकी प्रगति पर अत्याधिक संतोष प्रकट किया। उन्होंने इन कारखानों द्वारा बनाये जाने वाले मोटर के पुर्जों कृषि उपकरणों तथा रेल के अनुषंगी हिस्सों के आयात के बारे में भी दिलचस्पी प्रकट की।

Rail Link with East Pakistan

*1304. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are re-establishing rail link with East Pakistan;

(b) if so, when it is likely to be established; and

(c) the reasons for its discontinuance?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) This has not yet been decided.

(b) Does not arise.

(c) The running of Indo-Pakistan trains was discontinued on the Eastern side with effect from 7th September, 1965 due to the outbreak of hostilities between India and Pakistan.

पटसन का निर्यात

*1305. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन का निर्यात हाल में गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : प्रश्न सम्भावतः जूट के माल के निर्यात के बारे में है। 1964 के 161 करोड़ रुपये की तुलना में 1965 में निर्यात किये गये जूट के माल का मूल्य 184 करोड़ रु० के लगभग था। गत वर्ष के निर्यात की अपेक्षा 23 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें जूट के माल निर्यात बढ़ाने के लिये उठाए गये कदमों का ब्यौरा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6121/66।]**

बोकारो इस्पात कारखाना

*1306. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने का शिलान्यास करने के लिये रूस के प्रधान मंत्री को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव किया गया है कि सोवियत प्रधान मंत्री अपनी आगामी भारत यात्रा में कारखाने का औपचारिक रूप से शिलान्यास करें।

लोहा तथा इस्पात के रद्दी टुकड़ों की बिक्री

4201. श्री कर्णी सिंहजी : क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा धातु के रद्दी टुकड़ों के भारतीय व्यापार निगम द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित एक शिष्टमंडल लोहा तथा इस्पात के रद्दी टुकड़ों की थोक बिक्री के बारे में बात-चीत करने के लिये जापान गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) शिष्टमंडल ने जापान को व्यापारिक फर्मों के साथ बातचीत की थी और जापान को 100,000 टन रद्दी लोहा बेचने में सफल हुआ।

केले से रेशों का बनाया जाना

4202. श्री अ० क० गोपालन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार की केले के पत्तों से रेशे बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये मशीनें कहां से मंगाई जायेंगे; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी इस योजना को लागू करने का है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी) (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

क्विलोन रेलवे स्टेशन

4203. श्री अ० क० गोपालन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरै रेलवे सलाहकार समिति ने रेलवे अधिकारियों से क्विलोन रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण करने की प्रार्थना की है क्योंकि यह बहुत पुराना हो चुका है; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

क्विलोन त्रिवेन्द्रम रेलवे फाटक (क्रासिंग)

4204. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरने (क्रासिंग) के लिये पर्याप्त सुविधायें न होने के कारण पाराबूर में क्विलोन त्रिवेन्द्रम रेलवे फाटक (क्रासिंग) पर बहुत विलम्ब हो जाता है;

(ख) क्या एस०एन० कालेज क्विलोन के सामने एक क्रासिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका निर्माण-कार्य कब आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

केरल में रेलवे स्टेशनों तक जाने वाली सड़कें

4205. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कायमकुलम-मवेलीकारा तथा चेंगान्नूर रेलवे स्टेशनों तक जाने वाली सड़कें प्रयोग करने योग्य नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्माण-कार्य को तुरन्त आरम्भ करने का विचार है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी, नहीं । कायनकुलम, मावेलिक्करा और चगनूर रेलवे स्टेशन के पहुंच मार्ग इस्तेमाल के लिए ठीक हालत में हैं । कहीं-कहीं मरम्मत का जो काम आवश्यक समझा गया है, वह हो रहा है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

कोट्टारक्कर तथा पुनलूर स्टेशनों पर पार्सल कार्यालय

4206. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोट्टारक्कर तथा पुनलूर रेलवे स्टेशनों (दक्षिण रेलवे) पर कोई भी पार्सल कार्यालय नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इसके बारे में जनता की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) कोट्टारक्करा स्टेशन पर अलग पार्सल घर नहीं है लेकिन पुनलूर स्टेशन पर अलग पार्सल घर की व्यवस्था है । कोट्टारक्करा स्टेशन पर पार्सलों को एक कमरे में रखा जाता है जो स्टेशन मास्टर के कमरे से लगा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता, क्योंकि दोनों स्टेशनों पर इस समय जो सुविधाएं हैं, वे वहां के यातायात के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं ।

केरल में हथकरघा सहकारी संस्थाएं

4207. **श्री प० कुन्हन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 में केरल में हथकरघा सहकारी संस्थाओं के लिए कुल कितने विद्युत्-चालित करघे मंजूर किये गये;

(ख) किन-किन सहकारी संस्थाओं को ये करघे बांटने के लिए चुना गया है; और

(ग) क्या पालाप्पुरम और कोल्लमगोड सहकारी संस्थाएं भी उनमें सम्मिलित की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) कुछ नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

बटे हुए (स्पन) रेशम का कारखाना

4208. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में तैयार होने वाला अपशिष्ट रेशम (सिल्क वेस्ट) नामक कच्चा माल मसूर में बटे हुए रेशम के कारखाने की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) क्या अपशिष्ट रेशम की बाकी मात्रा का निर्यात करने दिया जाता है और यदि हां तो कितनी मात्रा में; और

(ग) क्या बटे हुए रेशम के कारखाने को पिछले पांच वर्षों से लाभ हो रहा है और यदि हां, तो अब तक प्रत्येक वर्ष में कुल कितना लाभ हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) हां। 1964-65 में दक्षिण भारत में उत्पन्न होने वाले 3.22 लाख कि० ग्रा० सिल्क वेस्ट का निर्यात किया गया।

(ग) 1962-63 से चन्नापटना की बटे हुए रेशम की सरकारी मिल को लाभ हो रहा है जैसाकि निम्न सारणी से प्रकट होता है :—

वर्ष	लाभ या हानि
	(लाख रु० में)
1960-61	0.90 हानि
1961-62	1.54 हानि
1962-63	1.35 लाभ
1963-64	4.05 लाभ
1964-65	4.01 लाभ

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना

4209. श्री राम हरख यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 मार्च, 1966 की रात को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक चलती हुई गाड़ी से एक यात्री गिर गया था और मर गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस दुर्घटना के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) सवाल नहीं उठता।

नांगल के समीप अखबारी कागज का कारखाना

4210. श्री राम हरख यादव : क्या **उद्योग** मंत्री 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1002 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नांगल के समीप कीरतपुर साहिब पर एक अखबारी कागज का कारखाना खोलने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारखाने को किसी विदेशी उपक्रम के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है; और

(ग) इस परियोजना पर लगभग कितना खर्च आयेगा और उसमें सरकार कितना व्यय वहन करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : गैर-सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का संयंत्र नंगल क्षेत्र में लगाने का एक प्रस्ताव है, लेकिन निश्चित स्थान अभी नहीं बताया गया है। विदेशी सहयोग की शर्तों और परियोजना की रूप रेखा बनाने एवं उसकी वित्त-व्यवस्था करने के संबंध में ब्यौरे की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

दस्तकारी की वस्तुओं का उत्पादन

4211. श्री राम हरख यादव : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने दस्तकारी की वस्तुओं की उत्पादित क्षमता को बढ़ाने के लिये 100 उत्पादन केन्द्र खोलने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : मामला विचाराधीन है।

काजू का निर्यात

4212. श्री वारियार :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काजू के निर्यात पर किस्म नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में काजू निर्यात संवर्धन परिषद् की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के कार्य-संचालन के बारे में विदेशी खरीदारों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात किये गये कुल माल में से कितने प्रतिशत माल की किस्म के बारे में खरीदारों ने शिकायतें की हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) काजू की गिरियों के निर्यात पर किस्म नियंत्रण के लिये, काजू निर्यात सम्वर्द्धन परिषद की इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है। परिषद की ऐसी एक योजना पहले थी जो 31 मार्च, 1966 तक चालू रही।

(ख) योजना में निम्नलिखित बातें शामिल थीं :—

(1) वर्गीकरण, नामकरण तथा परिभाषा करना।

(2) कीड़ों द्वारा होने वाली खराबी, टूटी हुई या सड़ी गली गिरियां, काले या बादामी धब्बे और कठोर छिलका जैसे दोषों से मुक्त करना।

परिषद् के निरीक्षण कर्मचारी, काजू की गिरियों का निरीक्षण यह तय करने के लिये किया किया करते थे कि खेप किस्म और वर्गीकरण नामकरण की परिभाषाओं के अनुरूप तथा दोष-रहित है या नहीं। किस्म के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाने के बाद परिषद के निरीक्षण कर्मचारी निर्यात योग्यता के प्रमाणपत्र दिया करते थे और पैक करने वाले पेटियों पर निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् के लेबल लगाया करते थे।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेशी खरीदारों ने किस्म के बारे में जो शिकायतें की वे 1965-66 के कुल निर्यात के 0.2 प्रतिशत के विषय में थीं जोकि निर्यात की गयी काजू गिरियों के मूल्य में से 50,000 रुपये से कुछ ही अधिक होता है।

राजकोट-जादर और भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन

4213. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम रेलवे पर दो प्रस्तावित नई रेलवे लाइनों, राजकोट-जादर और भावनगर-तारापुर के बीच के यातायात के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) से (ग) : राजकोट-जसदान मीटर लाइन और भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन रेल सम्पर्कों के नये यातायात सर्वे और पहले के इंजीनियरिंग अनुमान को अद्यतन बनाने के काम हो रहे हैं जो 71,652 रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किये गये हैं।

दो तथा तीन शायिकाओं वाले शयन डिब्बे

4214. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हो कर जाने वाली तथा दिल्ली से आरम्भ होने वाली भारतीय रेलों की कुछ डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में दो तथा तीन शायिकाओं वाले बहुत से शयन डिब्बे लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो जिन गाड़ियों में शायिकाओं वाले शयन डिब्बे लगाये गये हैं, उनका तथा शायिकाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक बयान रखी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6122/66]

कारैक्कुडी से मद्रास तक सीधे डिब्बे

4215. श्री वै० तेवर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामेश्वरम एक्सप्रेस में लगे हुए कारैक्कुडी से मद्रास तक सीधे जाने वाले तीसरे दर्जे के डिब्बों में बहुत भीड़ रहती है तथा यात्रियों को असुविधा होती है;

(ख) कारैक्कुडी और तिरुचारूल के बीच के रेलवे स्टेशनों में मद्रास के लिये तीसरे दर्जे के औसतन कितने टिकट बिकते हैं;

(ग) क्या सरकार यातायात की मांग को पूरा करने के लिये अतिरिक्त सीधे डिब्बे लगाने के लिये विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। इसका मुख्य कारण यह है कि कम दूरी वाले यात्री थोड़ी दूर की यात्रा के लिए भी सीधे सवारी डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं।

(ख) अक्टूबर, 1965 में की गयी गणना के अनुसार कारैक्कुडी-तिरुवरूर (तिरुवरूर को छोड़ कर) खण्ड के स्टेशनों से मद्रास क्षेत्र के स्टेशनों के लिए जारी किये गये तीसरे दर्जे के टिकटों की दैनिक औसत संख्या लगभग 45 है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस मार्ग पर भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से 1-4-1966 से मद्रास-तिरूच्चिरापल्ली के बीच मुख्य लाइन पर एक जोड़ी अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ियां नं० 153 और 154 चलायी गयी हैं। इन गाड़ियों का मेल मायुरम स्टेशन पर 139/140 मायुरम-कारैक्कुडी सवारी गाड़ियों से होता है। उसी तारीख से पहले और तीसरे दर्जे का एक मिला-जुला सीधा सवारी डिब्बा भी कारैक्कुडी हो कर मद्रास एगुम्बूर और मानामदुरै के बीच 119/120 मद्रास-तिरूनेलवेलि एक्सप्रेस और इससे मेल लेने वाली अन्य गाड़ियों में चलाया जायेगा। कारैक्कुडी और मद्रास के बीच यात्रा करने वाले यात्री भी इस अतिरिक्त सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

Cement Factories

4216. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of new cement factories likely to be established in the country during the Fourth Five Year Plan;

(b) the names of the places, Statewise, where these factories are to be set up;

(c) the names of the places surveyed by the Cement Corporation to find lime stone; and

(d) the number of factories out of them which would be set up in the private sector and also of those which would be set up by the Cement Corporation?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibudhendra Misra) : (a) to (d). Full details of the locations approved by Government for setting up cement factories, Statewise and sectorwise, have been placed before this House in reply to Starred Question No. 225 on the 25th February, 1966. It is difficult to say at this stage how many of the licensed schemes are likely to materialise during the Fourth Five Year Plan. The Cement Corporation is currently surveying limestone deposits in seven locations (Sedam, Gokak, Mandhar, Katni, Jagdalpur, Neemuch and Paonta).

कोयले का वर्गीकरण

4218. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले का वर्गीकरण करने की वर्तमान व्यवस्था क्या है;

(ख) क्या कोयले के वर्गों या प्रारंभिक वर्गीकरण की जांच करने के लिये नियमित रूप से कोयले के नमूने लेने के लिये नमूने लेने वाले सहायकोंकी संख्या अपर्याप्त है;

(ग) क्या यह सच है कि नमूने लेने वाले सहायकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण महीनों तक कोयला खानों से कोयले के नमूने नहीं लिये जाते;

(घ) क्या इन पदों के लिये चुने गये सब उम्मीदवार नियुक्त किये जा चुके हैं और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कोयले के वर्गों की समुचित तथा नियमित रूप से जांच पड़ताल करनेके लिये पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने में कितना समय लगेगा?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जैसे ही कोई पट्टी खोली या पुन: खोली जाती है उसे जांच अधिकारियों द्वारा लिये गये पट्टों के नमूनों के आधार पर अस्थायी श्रेणी दे दी जाती है। तदुपरान्त श्रेणी का अन्तिम निर्धारण सामान्यत: नमूने लेने वाले सहायकों तथा खास मामलों में जांच अधिकारियों द्वारा लदान के समय लिये गए नमूनों के आधार पर होता है।

(ख) हां, महोदय।

(ग) कुछ मामलों में नमूने लेने में विलम्ब हुआ है परन्तु यह विलम्ब नमूना लेने वाले सहायकों के अभाव में उतना नहीं हुआ है जितना इन सहायकों के एकाएक पहुंचने पर भरे हुए वैगनों की अनुपलब्धि के कारण।

(घ) और (ङ) : मार्च 1965 में नमूना लेने वाले सहायकों के पद के लिये बनाई गई उम्मीदवारों की एक सूची का उपयोग आवश्यकतानुसार रिक्त स्थान भरने के लिये किया जा रहा है।

बिहार में बिना टिकट यात्रा

4219. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में बिहार में पूर्व रेलवे के किन किन सेक्शनों पर सबसे अधिक संख्या में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग पाये गये; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री(डा० राम सुभग सिंह) : (क) किऊल-गया, पटना-गया और गोमो-बरवाडीह खण्डों पर।

(ख) इन खण्डों पर जांच का काम तेज़ किया गया है। इसके अलावा गाड़ियों को रास्ते में अनियत स्थान पर खड़ा करके, वाणिज्यिक अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अचानक संकेन्द्रित जांच की जाती है। जिसमें पुलिस की भी सहायता ली जाती है। इसके अतिरिक्त इन खण्डों पर जांच के काम में तेज़ी लाने के लिए चल टिकट परीक्षकों के कुछ विशेष दस्ते भी बनाये गये हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

4220. श्री कोल्ला वेंकेय्या :
श्री म० ला० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **उद्योग** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1252 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के किन किन उद्योगों ने इस बीच अपने काम काज में सुधार किया है और कौन कौन से उद्योगों ने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : एक विवरण साथ में नत्थी है।

विवरण

निम्नलिखित कारखाने अब अधिक उत्पादन कर रहे हैं :—

(1) हिन्दुस्तान स्टील लि० का टिन प्लेट संयंत्र।
(2) हिन्दुस्तान स्टील लि० का व्हील तथा ऐक्सिल संयंत्र।
(3) हिन्दुस्तान स्टील लि० के कोयला धोने के कारखाने।
(4) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की किलबुरु लौह खनिज परियोजना।
(5) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया का सिन्दरी कारखाना।
(6) हिन्दुस्तान केबल्स लि० का भूमिगत को-सक्सियल केबल कारखाना।
(7) हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल।
(8) इंडियन आयल कारपोरेशन लि० का बरौनी का तेल-शोधक कारखाना; तथा
(9) हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लि० का पेनिसिलीन कारखाना।

हिन्दुस्तान टैलीप्रिन्टर्स ने अपने उत्पादन को पूरी क्षमता तक बढ़ा लिया है।

Karwi Railway Station

4221. Shrimati Savitri Nigam : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme for the renovation of Karwi Railway Station (Central Railway) and for the construction of a shed there was formulated in 1962-63 and was postponed later on; and

(b) the decision taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) The scheme was subsequently approved and included in 1964-65 Works Programme. The work on the scheme is in progress. It includes the following works:—

(i) Provision of a separate tourist platform.

(ii) Shifting of IIIrd Class Waiting Hall.

(iii) Improvements to approach road and circulating area.

(iv) Additional Booking Window.

(v) Drainage Arrangements.

(vi) Electrification.

(vii) Provision of cover over platform (100' × 36'-6").

Ragaul Railway Station

4222. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri P. C. Borooah : **Shri Subodh Hansda :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the passengers are confused on account of the name of Ragaul given to Maudah Railway station on the Kanpur-Banda Branch line of the Central Railway;

(b) whether Government have received suggestions now to rename Ragaul Railway Station as Maudah in view of the fact that the name of Maudah station was changed as Ragaul since there was another station bearing the name of Maudah which had gone to Pakistan; and

(c) if so, the reasons for the delay in changing the name?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) to (c). A statement is attached.

STATEMENT

Ragaul Railway station

(a), (b) & (c). Ragaul railway station was originally named as Maudah but this name was altered to Ragaul from 1-9-1920 in consultation with the Local Civil authorities owing to the occurrence of misdespatches of telegrams, parcels and goods as a result of the similarity of the name of the station with the names of the following existing stations.

1. Mohuda (S.E. Railway).

2. Madha (Central Railway).

3. Mahudha (Western Railway).

Further , Ragaul station is also served by Ragaul Post Office which position is in conformity with the principle that the names of the Railway station and the serving post office should, as far as possible, be identical.

Suggestion to change the present name 'Ragaul' to 'Maudha' has been made on a number of occasions. In view however, of the circumstances explained above, it was decided that the existing name of 'Ragaul' for the station should continue.

A station serves a number of villages and places, only one of which can be adopted as the name of the station. It would, therefore, not be possible, in any case, to indicate by a station name, all places served by that station.

Production of Guar Gum

4223. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the proposal to set up new units to increase the production capacity of Guar Gum is under consideration of the Planning Commission; and

(b) if so, the extent of its capacity not being utilised uptill now and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibudhendra Mishra) : (a) & (b). Rural Industries Planning Committee of the Planning Commission is interested in manufacture of Guar Gum on small scale in such of the Rural Industries Projects areas where raw materials are readily available. A model scheme regarding the process etc. for the manufacture of Guar Gum has been circulated to some rural industries project areas with a view to exploring the possibility of setting up of small untis for the manufacture of Guar Gum. It is, however, too early to expect any results at this stage.

Re-Rolling Mills

4224. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to state :

(a) whether the Re-rolling Mills Association, Madras, has submitted any memorandum to the effect that small factories are not given billets in adequate quantity;

(b) if so, the reasons therfor; and

(c) whether any discrimination is made between big and small factories?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No discrimination is made between small and big re-rollers. However, M. S. billets are allotted only to registered billet re-rollers.

निर्यात की अनेकता

4225. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बल्लभ नगर (गुजरात) में हुए 19 वें अखिल भारतीय वाणिज्य सम्मेलन में निर्यात में विविधता लाने की कोई योजना तैयार की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है तथा योजना को क्रियान्वित करने में सहायता देने के लिये सरकार से क्या कार्यवाही करने को कहा गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्व रेलवे पर पुलों का निर्माण

4226. श्री मधु लिमये :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि झाझा और गिद्धौर (पूर्व रेलवे) के बीच रेलवे लाइन पर दो पुलों के निर्माण में विलम्ब होने के कारण मुंघेर जिले के जमुई सब-डिवीजन में नागी आरक्षण सिंचाई योजना की नहरों के विस्तार का कार्य रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पुलों के निर्माण-कार्य को तेजी से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि नहर का पानी रेलमार्ग के नीचे से जा सके ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) से (ग) : पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन पर क्रमश: किलोमीटर 368/3–4 और 373/10–11 पर साइफ़न पुल बनाने के लिए बिहार सरकार ने दो सुझाव दिये है। किलोमीटर 368/3–4 के निर्माण-कार्य का नक्शा और अनुमान राज्य सरकार की सलाह से अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है और आशा है यह काम अगले मानसून से पहले पूरा हो जायेगा। किलोमीटर 373/10–11 के निर्माण-कार्य का नक्शा भी राज्य सरकार द्वारा मंजूर कर दिया गया है और इसका अनुमान मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। राज्य सरकार से अनुमान की मंजूरी मिलते ही वास्तविक काम शुरू कर दिया जायेगा ।

Dacoity near Waris Aleganj Station

4227. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently some dacoits attacked a train at Garsanda Halt near Waris Aleganj Railway Station on the Eastern Railway;

(b) if so, the loss suffered thereby; and

(c) whether some of the dacoits have been captured?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

दक्षिण-पूर्व रेलवे में छंटनी

4228. **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में हाल में बहुत से कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों की; और

(ग) इस छंटनी के क्या कारण हैं और क्या रेलवे यूनियन ने इसका विरोध किया था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : किसी नियमित कर्मचारी की छंटनी नहीं की गयी है। लेकिन काम खत्म होने या कम हो जाने के कारण 13002 नैमित्तिक मजदूरों को हटा दिया गया है, जिसके खिलाफ़ यूनियनों ने लिखा-पढ़ी की है।

बेबी फूड का उत्पादन

4229. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने चौथी योजना अवधि में विटामिन युक्त सस्ते दाम वाली बेबी फूड का उत्पादन करने के लिए पांच कारखानों की स्थापना का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने चार कारखानों की स्थापना करने के लिए सुझाव दिया है जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता 3 मीट्रिक टन प्रति दिन होगी। इन कारखानों में विटामिन युक्त बच्चों का दूध छुड़ाने वाले सस्ते दुग्ध खाद्य के अतिरिक्त चिकनाई रहित दुग्ध पाउडर खाने में काम आने वाला मूंगफली का आटा तथा गेहूं का आटा तैयार किया जायेगा। यह प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और इसका ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

पेप्पेगंज रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय छात्र सेना दल के केडेटों का रेलवे कर्मचारियों से झगड़ा

4230. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 जनवरी, 1966 को पूर्वोत्तर रेलवे पर गोरखपुर जाने वाली एक सवारी गाड़ी में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के केडेटों तथा रेलवे संग-चल कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब रेल गाड़ी पेप्पेगंज स्टेशन पर पहुंची, तो कुछ केडेट ड्राइवर के पास गये और उसकी मारपीट की; और

(ग) क्या पुलिस ने अपराधी लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन दुर्घटना 2-1-1966 को हुई।

(ख) जी हां।

(ग) गोरखपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/332/353 और भारतीय रेल अधिनियम 127 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है और अभी उसकी जांच-पड़ताल हो रही है।

दियासलाई के कारखानों को बन्द कर देना

4231. **श्री कोल्ला वेंकय्या :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री ग्र० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री काशीनाथ दुर्रे :
श्री म० प० स्वामी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोटेशियम क्लोरेट और लाल फासफोरस न मिलने के कारण दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में दियासिलाई के कारखानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कितने कारखाने बन्द हो गये हैं और कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये; और

(ग) सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने तथा बेरोजगार व्यक्तियों को क्या सहायता दी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुघेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां। यह ठीक है कि पोटाशियम क्लोरेट तथा लाल फास्फोरस की अस्थायी कमी के कारण दक्षिणी क्षेत्र के दियासलाई कारखानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(ख) सम्बंधित राज्यों से इस बात की पुष्टि कर ली गई है कि लगभग 800 कारखानों के पास पूरा काम नहीं था या वे बंद हो गए जिसके कारण लगभग 8,000 लोगों को या तो पूरा काम नहीं मिला या वे बेरोजगार हो गए।

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) दक्षिण भारत के सारे दियासलाई कारखानों में पोटाशियम क्लोरेट का वितरण करने के लिए पोटाशियम क्लोरेट के तीन उत्पादकों के सहयोग से उनके उत्पादन का एक "पूल" बना कर उसका वितरण दियासलाई के कारखानों को उनके द्वारा दिए जाने वाले उत्पादन शुल्क के आधार पर करने की प्रणाली लागू की गई है। फरवरी 1966 के दौरान दियासलाई कारखानों में कुल 101 मी० टन पोटाशियम क्लोरेट का वितरण किया गया था। मार्च, अप्रैल तथा बाद के महीनों में 130 मी० टन पोटाशियम क्लोरेट और देने का प्रबन्ध कर लिया गया था जो प्रति 100 ग्रुस दियासलाई की डिबियों पर 5.5 कि० ग्रा० के राशन के हिसाब से बैठता है। अब अप्रैल, 1966 से प्रति 100 ग्रुस दियासलाई की डिबियों पर 8 कि० ग्रा० देने का प्रबन्ध कर लिया गया है।

(2) राज्य व्यापार निगम द्वारा रुपया क्षेत्र के देशों से 300 मी० टन पोटाशियम क्लोरेट का आयात करने का इन्तजाम कर लिया गया है।

(3) दक्षिण भारत के दियासलाई कारखानों को कुल 167,612 रु० के मूल्य का लाल फास्फोरस आयात करने के लिए आयात लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं।

Morvi-Amran Narrow Gauge Railway Line

*4232. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri M. N. Swamy :**
Shri Kolla Venkaiah : **Shri Laxmi Dass :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that **Government** have closed **Morvi-Amran** narrow gauge railway line; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) and (b). Traffic on only the Sanala-Amran Road section of the Morvi-Sanala-Amran Road narrow gauge line was closed with effect from 25-10-65 after consultation with the Gujarat Government. The reasons for the closure are:

(1) This section was running at a loss for a number of years (Rs. 1.40 lakhs in 62-63) and its continued operation would have resulted only in further losses to the public exchequer.

(2) the released P. W. materials, rolling stock etc., from this section will be used for the urgent rehabilitation of the Morvi-Tankara narrow gauge line.

(3) the area is well served by road and no inconvenience is likely to be caused to the public due to this dismantlement.

(4) after the track is dismantled the formation will be handed over to the State Government for forming an all weather road in the area.

भारत उत्पादिता वर्ष

4233. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में भारत उत्पादिता वर्ष, 1966 के उद्घाटन के अवसर पर इस वर्ष को सफल बनाने के हेतु अमरीका से एक उत्पादिता विशेषज्ञ को बुलाने का कोई सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबूधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हथकरघे से बने कपड़े का निर्यात

4234. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में हथकरघा निर्यात संवर्धन संगठन ने, अपनी सहयोगी संस्थाओं को छोड़कर, स्वत: कितनी मात्रा में हथकरघे से बने हुए कपड़े का निर्यात किया है; और

(ख) उक्त अवधि में व्यापारी संस्थाओं के पास निर्यात के लिये आये हुए क्रयादेशों के आधार पर उन्हें कितनी मात्रा में हथकरघे से बना हुआ कपड़ा बेचा गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : हथकरघा निर्यात संवर्द्धन संगठन नामक कोई संगठन नहीं है। संभवतः, यह प्रश्न भारतीय दस्तकारी एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड के बारे में है। इस निगम ने 31 दिसम्बर, 1965 को समाप्त होने वाली तिमाही में 13,41,124.52 रुपये मूल्य के हथकरघा वस्त्र निर्यात किये। इसी अवधि में इसने अपने व्यावसायिक सहयोगियों को 57,683.74 रु० मूल्य के हथकरघा वस्त्र स्थानीय तौर पर बेचे। व्यावसायिक सहयोगियों को बेचे गय कपड़ में से उनके द्वारा किये गये निर्यात की सही मात्रा के बारे में निगम को कोई जानकारी नहीं है। 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाली तिमाही में हुए निर्यात की जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में लघु उद्योग

4235. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन महीनों में उड़ीसा से लघु उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कितने व्यक्ति विदेश भेजे गये; और

(ख) वे किन किन देशों को भेजे गये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के लिये सीमेंट का कोटा नियत किया जाना

4236. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को वर्ष 1965–66 में कितने सीमेंट की आवश्यकता थी; और

(ख) उड़ीसा के लिये उस अवधि में वस्तुतः कितना सीमेंट नियत किया गया?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) राज्य कोटे के अन्तर्गत राज्य सरकार की मांग के अनुसार 959,286 मी० टन।

(ख) राज्य कोटे के अन्तर्गत राज्य सरकार को अप्रैल से दिसम्बर, 1965 की अवधि के लिए 1,49,550 मी० टन सीमेंट का नियतन किया गया था जिसमें जनता और राज्य सरकार के विभागों की आवश्यकताएं सम्मिलित है।

1–1–1966 से सीमेंट से नियंत्रण हटा देने के बाद से सीमेंट उद्योग मोटे तौर पर पहले के नमूने के आधार पर ही सीमेंट भज रहा है। राज्य सरकारों का नियतन अब मूल्य समझौते के अन्तर्गत सरकारी विभागों की आवश्यकताओं तक ही सीमित कर दिया गया है। 1966 की प्रथम अवधि (जनवरी-मार्च, 1966) के सम्पूर्ण उत्पादन के 50 प्रतिशत में से, जो सरकारी आवश्यकताओं के लिए रक्षित होता है, उड़ीसा सरकार को 24,000 मी० टन का नियतन किया गया था। जनता की आवश्यकता सीमेंट

उद्योग द्वारा बाकी 50 प्रतिशत के रक्षित उत्पादन में से पूरी की जाती है। सरकारी विभागों की अतिरिक्त आवश्यकता भी जो ऊपर बताये गये सरकारी कोटे से पूरी नहीं की जा सकती, उद्योग के साथ पत्रव्यवहार करके अरक्षित कोटे में से पूरी की जा सकती है।

ब्रिटिश गिआना से शिष्टमंडल

4237. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश गिआना के उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल हाल में नई दिल्ली आया था; और

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल की यात्रा के दौरान भारत तथा ब्रिटिश गिआना के बीच पारस्परिक सहायता के हेतु उद्योग तथा व्यापार के विकास के लिये यदि कोई समझौता किया गया तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिटिश गिआना के व्यापार एवं उद्योग मंत्री ने किया था।

(ख) ब्रिटिश गिआना से 10,000 टन चावल की खरीद के लिये बातचीत सफलतापूर्वक होने वाली है और ब्रिटिश गिआना को हमारा निर्यात बढाने की अच्छी सम्भावनाएं है। भारतीय उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल जार्जटाउन भेजने की सम्भावना विचाराधीन है।

इटली को वस्त्रों का निर्यात

4238. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली ने जनवरी, 1966 में भारत से वस्त्रों के आयात पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटा दिया था;

(ख) यदि हां, तो इटली में संभाव्य बाजार का पता लगाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इटली द्वारा की गई सुविधाओं के फलस्वरूप व्यापार में कितनी वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) इटली को कोरा कपड़ा और आटे भरने की सूती बोरियों के निर्यात के अच्छे अवसर हैं। लगभग दस लाख गज कपड़े के निर्यात के सौदे पहले ही हो चुके हैं। भारतीय सूती कपड़े के लिये इटली के बाजारों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) बाजार सर्वेक्षण पूर्ण होने के पहले यह अनुमान लगाना कठिन है कि व्यापार का परिणाम किस सीमा तक बढ़ेगा।

निर्यात घर

4239. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **उद्योग** मंत्री ३ दिसम्बर, १९६५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात घर तथा प्रेषण कार्यों के लिये पैकिंग करने के एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी सरकारी कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों पर इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इगतपुरी-भुसावल सैक्शन (मध्य रेलवे) में बिजली लगाना

4240. **श्री मा० ल० जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में इगतपुरी तथा भुसावल के बीच बिजली लगाने का काम शीघ्र पूरा होने की सम्भावना है; और

(ख) यात्रियों के यातायात की अधिकता को देखते हुए यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या उस लाइन पर नई जनता तथा शटल रेलगाड़ियां चलाने की कोई संभावनाएं है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) इगतपुरी-भुसावल खंडपर बिजली लगाने का काम कई चरणों में 1967 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

(ख) जी, हां। बिजलीकरण का काम पूरा हो जाने के बाद अतिरिक्त लाइन क्षमता उपलब्ध होने पर यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए जनता और शटल गाड़ियों सहित अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के बारे में विचार किया जायेगा।

पंजाब में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

4241. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान पंजाब में कितने अम्बर चर्खा पाठ्यक्रम आयोजित किये गये थे;

(ख) इस प्रशिक्षण में कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया; और

(ग) उक्त अवधि में इस कार्य पर कुल कितना खर्च हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 51।

(ख) 719।

(ग) 34,461 रु०।

Derailment near Gaya

4242. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 30th January, 1966 two wagons of a goods train derailed between Paraiya and Guraru Railway Stations, above 12 miles west of Gaya Railway Junction on the Grand Chord line on the Eastern Railway resulting in the dislocation of traffic;

(b) if so, the cause of this accident; and

(c) the amount of loss caused to Railway property as a result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath):
(a) One wagon had derailed.

(b) The accident was due to the failure of mechanical equipment.

(c) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 16,400.

रूसी तकनीकी सहयोग से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना

4243. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी तकनीकी सहयोग से इस समय सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) क्या उनके निर्माण-कार्य में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विश्वनेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6123/66 ।]**

पंजीकृत लोहा तथा इस्पात व्यापारी

4244. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र में इस समय पंजीकृत लोहा तथा इस्पात व्यापारियों की संख्या पृथक् पृथक् कितनी है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : दो विवरण-सभा-पटल पर रख दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6124/66 ।]**

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

4245. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत जयपुर अधिवेशन के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विश्वनेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार की वर्तमान नीति वही है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिछले जयपुर अधिवेशन में उसके अध्यक्ष द्वारा बताई गई थी और वह आयोजित लक्ष्यों और उपलब्ध साधनों पर भी निर्भर करती है । फिर भी सरकार न केवल औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची 'क' में सम्मिलित सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का ही विस्तार करने का प्रयत्न करेगी वरन् अन्य उद्योगों का भी विस्तार करेगी जिनमें उपभोक्ता उद्योग भी सम्मिलित है ।

खजूर और मेवों के आयात के लिये भारतीय जहाज

4246. **श्री प० चं० बर्मन :**
श्री स० चं० सामंत :
श्री ब० कु० दास :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइसेंस देने की प्रणाली आरम्भ करने के बाद से फारस की खाड़ी के क्षेत्रों से आयात किये जाने वाले खजूर और मेवों के मूल्य कई गुना बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो खुला-सामान्य-लाईसैंस-अवधि में मूल्य क्या थे और वर्तमान मूल्य क्या है;

(ग) खुला-सामान्य-लाइसेंस-अवधि में आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती थी और उतनी ही मात्रा के माल के लिये इस समय कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि खुला-सामान्य-लाइसेंस-अवधि में पाल वाले भारतीय जहाज इन क्षेत्रों से पूरा माल ले आकर आते थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग): खजूर के अतिरिक्त अन्य मेवों के लिये लाइसेन्स प्रणाली जनवरी, 1950 और खजूरों के विषय में जनवरी, 1957 से पहले पहल चालू की गई। लाइसेंसों की वर्तमान प्रणाली दोनो के लिये ही अक्तूबर, 1962 से चालू की गई और उससे पहले की अवधि खुला-सामान्य-लाइसेंस की अवधि मानी जाती है। तत्काल उपलब्ध जानकारी के आधार पर दो विवरण तैयार किये गये हैं और वे संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6125/66।]** इस में ये तथ्य बताये गये हैं :—

(क) खजूरों के अतिरिक्त सूखी मेवा विषयक कुल परिमाण, विदेशी मुद्रा में कुल मूल्य, और आयात की प्रति इकाई के घोषित मल्य का औसत। ये 1948–52 और 1963–65 तक के वर्षों के विषय में हैं, और

(ख) खजूरों के विषय में कुल परिमाण विदेशी मुद्रा में कुल मूल्य और आयात की प्रति इकाई के घोषित मूल्य औसत। ये 1954–58 और 1963–65 तक के वर्षों के विषय में हैं।

(घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज़ पर यथासमय रख दी जायगी।

आयात निर्यात नियंत्रण कर्मचारी संघ

4247. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात नियंत्रण कर्मचारी संघ, बम्बई से संघ को मान्यता दिये जाने के लिये एक आवेदन-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय असैनिक सेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियम, 1959 उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा अवैध हो गया है। इन नियमों के संशोधन का प्रश्न गृह मंत्रालय के विचाराधीन है। इन नियमों में संशोधन हो जाने के बाद संघ को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा। फिर भी, आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक को औपचारिक मान्यता पर बल दिये बिना ही संघ के साथ कार्यवाही करने की सलाह दी गयी है।

Orders re: Casual Leave

4248. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Home Affairs have issued orders to the effect that if any employee comes late, his half day's casual leave would be deducted;

(b) whether he is aware that thousands of employees of the Central Government and semi-Government offices come from several cities situated on the Delhi-Panipat Section;

(c) whether it is a fact that several institutions have represented that because of the change in the timings of the offices, the trains running on this section either reach Delhi/New Delhi stations much ahead of the time of these offices or much later, and that consequently the employees are put to lot of inconvenience; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, but late attendance up to an hour on not more than two occasions in a month due to unavoidable reasons is condoned by the competent authority.

(b) A number of office staff come to Delhi from stations on Delhi-Panipat Section.

(c) A representation from Secretary, Government Emplovee's Association, Narela, for change in the present schedules of 2 DP and 4 DP Panipat-Delhi shuttles or alternatively introduction of an additional train, has been received.

(d) It has not been found operationally feasible to change the timings or introduce an additional train, as suggested by the Association. Nor does it appear necessary as morning trains arrive New Delhi/Delhi at suitable spacings, *viz.* 60 Dn. arr. New Delhi 07.55 hrs., 2 DP arr. Delhi at 09.25 hrs. and 4 DP arr. Delhi at 10.15 hrs. Similarly, evening trains leave at suitable timings, *viz.* 1 DP dep. Delhi 17.05 hrs., 1 DU dep. Delhi 18.10 hrs. and 3 DP dep. Delhi 19.25. hours.

अंदमान द्वीपसमूह में रबड़ और चाय के बागान

4249. श्री कन्डप्पन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीपसमूह में रबड़ के बागान पुन: लगाने में क्या बाधाएं हैं; और

(ख) क्या अन्दमान द्वीपसमूह में चाय के बागानों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है और क्या इस कार्य के लिये कोई योजना बनाई गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) अण्डमन द्वीप समूह में रबड़ की खेती के लिए रबड़ बोर्ड की चालू प्रायोगिक प्रायोजना में 1965-66 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों के क्रमिक कार्यक्रम में 500 एकड़ में पौधे लगाने का विचार है। इस प्रायोजना को अमल मे लाने में कोई बाधा नहीं आई है।

(ख) इन द्वीपों में चाय की खेती की संभावनाएं ढूंढने के लिये अण्डमन द्वीप समूह में एक अध्ययन दल भेजने का प्रस्ताव है।

फिनलैंड अखबारी कागज की सीट

4250. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा 1962–63 में भारतीय बन्दरगाह पर फिनलैंड के अखबारी कागज की सीट का प्रति मीट्रिक टन खर्च, बीमा, भाटक संविदा मूल्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या सरकार को पता है कि आयात करने वाले एक ऐजेन्ट, मेसर्स अब्दुल्ला फिदे अली एण्ड कम्पनी, बम्बई, ने वास्तविक मूल्य से 7 रुपये प्रति मीट्रिक टन अधिक मूल्य लिया और इस प्रकार उसने उक्त अवधि में अधिकार पत्र की शर्तों और निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम के नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन किया ;

(ग) क्या मुख्य नियंत्रक तथा वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने भी मूल्य का गलत हिसाब लगाया; और

(घ) यदि हां, तो लाइसेंसधारियों के वैध अधिकारों की सुरक्षा के लिये उक्त निर्यात करने वाले ऐजेन्ट तथा इस व्यापार में अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राज्य व्यापार निगम ने मुख्य भारतीय बन्दरगाहों पर 60 पौंड प्रति मीट्रिक टन लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर अखबारी कागज के तख्तों का आयात करने के लिये फरवरी, 1962 में स्केनन्यूज असोसिएशन, स्टाकहोम (जोकि स्कैण्डिनेविया देशों के अखबारी कागज के निर्माताओं का एक संघ है) के साथ संविदा किया था।

(ख) से (घ) : अखबारी कागज का बीजक सामान्यत: कुल वजन के आधार पर बनाया जाता है और लाइसेंस शुद्ध वजन के आधार पर दिये जाते हैं, अत: घड़े की व्यवस्था करनी आवश्यक थी। 1962–63 में अखबारी कागज के आयात लाइसेंस 60 पौंड प्रति मीट्रिक टन लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के आधार पर दिये गये थे। इसमें घड़े आदि को समाविष्ट करने के लिए उसने मूल्य के, जितने के लाइसेन्स दिये गये थे, 3 प्रतिशत (लगभग) का अतिरिक्त प्रभार भी शामिल किया गया था। एक लाइसेंसधारी से यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि अधिकार पत्र-प्राप्त मे० अब्दुला फिदे अली एण्ड कम्पनी, बम्बई ने अधिक मूल्य लिया और चोर-बाजारी की। शिकायत करने वाले ने स्वयं इस फर्म की परस्पर तय की गयी शर्तों (जिसमें ब्याज, दलाली, माल उठाने-धरने के प्रभार आदि शामिल थे) पर अपने व्यादेशक एजेन्ट के रूप में चुना था। उल्लिखित तथ्यों के प्रकाश में शिकायत की जांच की गयी और पता चला कि अधिकार पत्र प्राप्त कम्पनी ने निर्दिष्ट मूल्यों के भीतर ही माल का आयात किया और इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि आयात निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियम का उल्लंघन हुआ है। अत: सरकार द्वारा कोई कार्रवाई किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब के लिये टीन तथा सीमेंट का नियतन

4251. **श्री दलजीत सिंह :** क्या उद्योग मंत्री 18 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2425 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार को, राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से बेघर-बार हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये, टीन तथा सीमेंट के अभ्यंश (कोटा) की बहुत आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : पंजाब के सीमावर्ती जिलों में सीमेंट का सम्भरण बढ़ा दिया गया है। जनवरी से मार्च, 1966 की अवधि में राज्य के अमतसर, फीरोजपुर और गुरूदासपुर जिलों को 11,125 मी० टन सीमेंट भेजा गया था। जहां तक सीमावर्ती क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए टीन के कोटे का सम्बन्ध है, पंजाब सरकार के पास से कोई भी निवेदन नहीं मिला है।

'एम्बेसेडर' कारों का निर्माण

4252. श्री रा० बरुआ : क्या उद्योग मंत्री 18 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 632 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को एम्बेसेडर कारों के दोषों के बारे में अलग-अलग शिकायतें मिली है जिनके बारे में निर्माणकर्त्ताओं को निर्माण सम्बन्धी दोषों को दूर करने के लिए बताया गया है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र) : ऐसी शिकायतों के आंकड़े नहीं रखे गये है। फिर भी इस प्रकार की शिकायतों की संख्या अधिक नहीं है।

उत्तर प्रदेश में नये उद्योगों के लिये सहायता

4253. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कर्मरकर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को नये औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो 1965 में और 1966 में अब तक कुल कितनी राशि दी गई; और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी राशि मांगी थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (ग) : उद्योगों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत लघु एककों, सामान्य सुविधा केन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों को ऋण देने तथा लघु एककों के लिये विद्युत सहायता, और शिल्पियों को प्रशिक्षण के दौरान वजीफ़ा देने के लिए राज्य सरकारों को लघु उद्योगों का विकास करने के लिए अर्थात् ऋण तथा अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता एकमुश्त दी जाती है। औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को ऋण भी दिए जाते है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 1965–66 के लिए केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार से दी गई :—

लघु उद्योगों का विकास के लिए ऋण तथा अनुदान	औद्योगिक बस्तियां ऋण
90.96 लाख रु० (अस्थायी तौर पर)	31.70 लाख रु० (अस्थायी तौर पर)

1966–67 में उत्तर प्रदेश के लिए लघु उद्योगों और औद्योगिक बस्तियों के हेतु केन्द्रीय सहायता को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के कार्यकारी दल द्वारा 1966–67 की वार्षिक योजना के लिये तैयार किये गये अस्थायी अनुमान निम्न प्रकार है :—

लघु उद्योग . . .	180.62 लाख रु०
औद्योगिक बस्तियां . .	21.00 लाख रु०

मास्को में भारतीय प्रदर्शनी

4254. श्री विश्राम प्रसाद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई-अगस्त, 1963 में मास्को में आयोजित भारतीय प्रदर्शनी के दर्शकों को स्मारिका के रूप में देने के हेतु बिल्ले बनाने के लिये बम्बई की एक फर्म को एल्यूमिनियम तथा अविकारी इस्पात (स्टेनलेस स्टील) के आयात के लिये लाइसेंस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन बिल्लों को बनाने के लिये कितने मूल्य के तथा कितनी मात्रा में एल्यूमिनियम तथा अविकारी इस्पात की आवश्यकता थी; और

(ग) इस लाइसेंस के दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : यह सच नहीं है कि जुलाई-अगस्त, 1963 में मास्को में हुई भारतीय प्रदर्शनी के दर्शकों को देने हेतु बिल्ले बनाने के लिये बम्बई की एक फर्म को एल्यूमिनियम तथा बेदाग इस्पात के आयात के लिये लाइसेंस दिया गया था। बम्बई की फर्म ने बहुत ही थोड़े समय में और नाम मात्र की लागत पर, जो कि बाजारी कीमत से काफी कम थी उपर्युक्त प्रदर्शनी में वितरण करने के लिये सरकार द्वारा अपेक्षित एल्युमिनियम निर्मित लगभग 2–1/2 लाख स्मारिकाओं का सम्भरण किया। सोवियत रूस स्थित जिन फर्मों से कहा गया था वे भी इस प्रकार के बिल्ले इतने थोड़े समय में और भारतीय फर्मों द्वारा ली गयी कीमतों से दुगुनी तिगुनी कीमतों पर भी बनाने के लिये तैयार नहीं थीं। मामूली सी लागत पर इतनी बड़ी संख्या में फर्म द्वारा भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिये बनाये गये बिल्लों के काम और सरकार की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उसके द्वारा किये गये विशेष प्रयत्नों की कद्र करते हुये उसके अपने कारखाने में अनुमोदित उत्पादन के उद्देश्य से अपेक्षित कच्चे माल का आयात करने के लिये उसे 1 लाख रु० के कुल मूल्य का तदर्थ आयात लाइसेंस दिया गया था।

लोहे और इस्पात की वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाना

4255. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात की ओर अधिक वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं पर से; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) अभी तक लोहे और इस्पात की ओर अधिक वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाने का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Concession in Fare for Tourists Visiting Kashmir

4256. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a concession in railway fare has been announced for tourists visiting Kashmir;

(b) if so, the basis thereof; and

(c) the duration for which the concession will remain in force?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) From certain nominated stations, which number more than a hundred, rail-*cum*-road return tickets for Srinagar are issued on the basis of 1⅓ single journey rail fares in the case of First and Second Classes and 1½ single journey rail fares in the case of Third Class.

(c) From lst April to 31st October, 1966.

रेल्वे कर्मचारियों की शिकायतें

4257. श्री युद्धवीर सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन रेलवे के पंजीकृत कार्मिक संघो, विशेषकर अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर/असिस्टेंट स्टेशन मास्टर संघ के माध्यम से भेजी गई रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देता, तथा अधिकारी लोग उन्हें मुलाकात करने का अवसर भी नहीं देते और उनके पत्रों के उत्तर भी नहीं दिये जाते; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जब किसी की मार्फत कर्मचारियों की शिकायतें नोटिस में आती हैं तो उन पर हमेशा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। अ-मान्यता प्राप्त युनियनों के पदाधिकारियों की मुलाकात करन का मौका दिता जाता और उनसे मिलने वाले पत्रों का उत्तर नहीं दिया जाता, चाहे ऐसी यूनियनें ट्रेड यूनियन अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड क्यों न हों। यही बात स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की एसोसियेशनों पर भी लागू होती है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि अ-मान्यताप्राप्त संस्थाओं की मार्फत लिखा-पढ़ी को प्रोत्साहन न दिया जाय।

बम्बई के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

4258. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 नवम्बर, 1965 को मध्य रेलवे पर बम्बई से 20 मील दूर थाना और विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनों के बीच एक उपनगरीय रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के परिणामस्वरूप यातयात अस्त-व्यस्त हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ी के पटरी से उतर जाने के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ): (क) जी, हां।

(ख) यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

पूर्वोत्तर रेलवे में बिजली लगाना

4259. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में पूर्वोत्तर रेलवे के किन किन स्टेशनों पर बिजली लगाई गई;

(ख) इस कार्य पर कुल कितना खर्च हुआ; और

(ग) वर्ष 1966–67 में किन किन स्टेशनों में बिजली लगाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : एक बयान नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6126/66।]**

भारत-जापान संयुक्त व्यापार

4260. श्री फिरोदिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च शक्ति प्राप्त भारत जापान संयुक्त व्यापार आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : भारतीय व्यापार तथा उद्योग मण्डल संघ के नियंत्रण पर जनवरी–फरवरी, 1966 में जापानी आर्थिक मिशन के भारत के दौरे के समय एक उच्च शक्ति प्राप्त भारत जापान संयुक्त व्यापार आयोग स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था। दौरे पर आए हुए मिशन और संघ के मध्य हुई बात चीत के परिणाम स्वरूप यह स्वीकार किया गया कि भारत में भारत जपान व्यवसाय सहयोग समिति और जापान में उसका प्रतिरूप, जापान भारत व्यवसाय सहयोग समिति स्थापित करने के लिये कदम उठाये जायें ताकि दोनों देशों के व्यापारियों के मध्य विचार विमर्श और सम्पर्क बढ़ाया जा सके। यह भी स्वीकार किया गया है कि दोनों समितियों की प्रथम संयुक्त बैठक टोकियों में यथाशीघ्र की जाये। भारतीय व्यापार तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा ब्यौरा तैयार किया जा रहा रहा है।

सूती कपड़े का निर्यात

4262. श्री रा० बख्शा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़े की लागत बढ़ जाने से हमारे सूती कपड़े के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

[विवरण

सूती कपड़ो के मूल्य तथा किस्म दोनों के बारे में ही भारत अन्य निर्यातक देशों से होने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करता रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारतीय कपड़ा अधिक मूल्य होने के कारण विदेशी बाजारों से न निकल जाय, अनेक कदम ाये हैं। सूती कपड़ा की उत्पादन लागत में रूई का सब से बड़ा भाग होता है। इसे कपड़ा मिलों को पर्याप्त परिमाण में तथा उचित मूल्यो पर उपलब्ध कराया जाता है। सूती कपड़े का निर्यात करने वाले मिलों को रंग, रसायन आदि का आयात करने में कुछ सहायता दी जाती है जिससे उनका निर्यात बढ़ सके। उन्हें सूती कपड़ा मिलों की वे मशीने आयात करने की भी अनुमति दी जाती है जो देश में उपलब्ध नहीं होती जिससे कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा पुनः संस्थापन का गति तेज हो सके और इस प्रकार ये मिल प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी किस्म का कपड़ा तैयार कर सकें। कपड़ों की किस्म अच्छी रखने तथा उसे और भी सुधारने के लिये सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। कानूनी तौर पर एक वस्त्र समिति बना दी गई है। इसके कार्यों में देश में खपने वाले तथा निर्यात किये जाने वाले दोनों ही प्रकार के कपड़ों की किस्मों के मानक निर्धारित किया जाना भी शामिल है। इसके अलावा अच्छी किस्म के कपड़े का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये देश के प्रत्येक प्रसिद्ध कपड़ा मिल में एक किस्म नियन्त्रण विभाग भी रहता है। निर्यात होने वाले कपड़ों का लदान से पूर्वनिरीक्षण भी किया जाता है। निर्यात करने वाले विभिन्न मिलों को 10,000 स्वचालित तकुवे लगाने के लाइसेन्स दिये गये हैं जिससे बिल्कुल दोष रहित कपड़े का निर्यात किया जा सके।

त्रिवेन्द्रम में टाइटेनियम का कारखाना

4263. श्री वासुदेवन नायर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम स्थित टाइटेनियम कारखाने में उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस बढ़े हुए उत्पादन के कारण विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होने का अनुमान है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : जी, हां। इस कारखाने को अपनी क्षमता 6,500 मी० टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 24,500 मी० टन प्रतिवर्ष करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। 1964-65 के दौरान 62 लाख रु० के मूल्य का 3000 मी० टन टिटेनियम डाइआक्साइड का आयात इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये किया गया था। लाइसेंस दी गई अतिरिक्त क्षमता के कार्यान्वित हो जाने पर इस उत्पाद के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा में बचत की जा सकेगी।

Shortage of Tyres and Tubes

4264. Shri Hukam Chand Kachhawaiya : Will the Minister of Industry be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a scarcity of Dunlop and Goodyear tubes of cycles and scooters in the market;

(b) whether it is also a fact that tyres of the said Companies are being sold in the black market; and

(c) if so, whether Government propose to check this black marketing?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibhudhendra Misra) : (a) There is no shortage of Dunlop and Goodyear scooter tubes in the market. As regards cycle tubes also there is no overall shortage in the country. However, there is a consumer preference for cycle tubes of Dunlop and Goodyear makes and the manufacturers of these are not in a position to meet the entire demand in the country.

(b) & (c). There have been some reports regarding overcharging by the dealers in the case of Dunlop and Goodyear cycle tyres. Whenever specific complaints supported by sufficient evidence regarding black marketing in these tyres are received, appropriate steps have been and are being taken by Government through the manufacturers to ensure that the erring dealers are suitably dealt with.

दिल्ली से बम्बई तक एक्सप्रेस गाड़ी

4265. श्री फिरोदिया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बरास्ता मध्य रेलवे दिल्ली से बम्बई तक एक नयी एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाने का है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के लोगों ने अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं जिनमें उन्होंने एक नई रेल गाड़ी चलाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : मध्य रेलवे के मार्ग पर बम्बई वी० टी० और दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने के लिये अभ्यावेदन मिले हैं। लेकिन विभिन्न खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता उपलब्ध न होने के कारण अभी इस रास्ते पर अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है। इस मार्ग पर लाइन क्षमता बढ़ाने के काम हो रहे हैं, जिनके पूरा होने पर अतिरिक्त गाड़ी चलाने के बारे में विचार किया जायेगा।

रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नारियल के छिलके का सड़ाना

4266. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नारियल के छिलके को सड़ाने की लागत कम करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या नारियल जटा अनुसंधान संस्था ने यह तकनीकी समस्या हल की है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नारियल की जटा उतारने के प्रयोग केन्द्रीय कायर अनुसन्धान संस्था, कलावूर में किये गये हैं किन्तु कोई सफलता नही मिली। लागत घटाने के बदले रासायनिक प्रक्रिया से जटा उतारने से लागत बढ़ जाती है।

अलप्पी में नारियल जटा की चटाइयां बनाने का कारखाना

4267. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलप्पी में नारियल जटा की चटाइयां बनाने के लिये एक यंत्रीकृत कारखाना स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ में अलप्पी स्थित कारखाने में 5 शक्तिचालित करघे रहेंगे। यह नारियल जटा की चटाइयों का उत्पादन करेगा और उत्पादों का निर्यात किया जायगा। 5 शक्तिचालित करघों के आयात के लिये आदेश दिए जा चुके हैं और उनके शीघ्र ही पहुंच जाने की आशा है। कारखाने की इमारत के निर्माण कार्य के लिये कदम उठाये जा चुके हैं।

समुद्र से मिलने वाले खाद्य पदार्थों के निर्यातक

4268. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र से मिलने वाले खाद्य पदार्थों के जिन निर्यातकों ने शल्कन शायबान (पीलिंग शैड) बना रखे हैं उनके विरुद्ध कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे चलाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन निर्यातको से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन की मेज़ पर रख दी जायगी।

कपड़े का निर्यात

4269. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया के कुछ देशों को कपड़े का निर्यात कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन किन देशों को कपड़े का निर्यात कम हो गया है तथा कितना कितना; और

(घ) निर्यात में हुई कमी को रोकने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिये 1966 में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6127/66]**

ऊन के गोलों का आयात

4270. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा उत्पादन संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें भारतीय ऊन के बदले में ऊन के गोलों की आयात की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, ती इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के निर्यात कार्यालय

4271. **श्री फिरोडिया :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के निर्यात कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितने कार्यालय खोले जायेंगे और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा मिलने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) : इस सम्बन्ध में प्रस्ताव करने से पहले कम्पनी इस बात पर विचार कर रही है कि वह विदेश स्थित इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद तथा राज्य व्यापार निगम के विभिन्न कार्यालयों की सेवाओं का कहां तक इस्तेमाल कर सकती है।

अंगूर की शराब (वाइन) बनाना

4272. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में अंगूर बड़ी मात्रा में उगाये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अंगूर उत्पादकों को विपणन की सुविधाओं के अभाव में बहुत असुविधाएं उठानी पड़ती है और उन्हें काफ़ी हानि होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अंगूर की शराब अथवा अन्य पेय पदार्थ तैयार करने के लिये क्या सुविधायें दी हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विश्वकेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी कोई भी कठिनाइयां सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है।

(ग) शराब बनाने के लिए और लाइसेंस देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हार्ड कोक पर से नियंत्रण हटाना

4273. श्री यशपाल सिंह : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हार्ड कोक के मूल्य तथा वितरण पर से नियंत्रण हटा लिया गया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है।

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) उत्पादन की लागत तथा अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने की पृष्ठभूमि में इसे हटाया गया था।

Cement Factory in Maharashtra

4274. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the possibility of setting up a cement factory in Rajura and Chanakha area in Yeotmal District of Maharashtra State, and

(b) if so, whether a decision has been taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibhudhendra Misra : (a) and (b). A letter of intent has been issued on 17-2-1966 to M/s. The Associated Cement Companies Ltd., Bombay for setting up a factory with an annual capacity of 400,000 tonnes for the manufacture of portland cement at Ghugus in Chanda District of Maharashtra. 2 further applications for licence—one for location at Ghugus (Chanda District)/Rajur (Yeotmal District) and another for Mukhutban location in Yeotmal District, have been recently received and are under consideration.

तांबे की नलियों का आयात

4275. श्री दे० शि० पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये जाने के लिये रुपये में भुगतान करके भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा यूगोस्लाविया से आयात की गई तांबे की नलियों का छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास आयुक्त द्वारा 19 जुलाई, 1965 तथा 26 फरवरी, 1966 को राज्य-वार किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह आवंटन किस आधार पर किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) एक विवरण साथ में रखी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6128/66।]**

(ख) 19 जुलाई, 1965 को किया गया नियतन राज्यों के उद्योग निदेशकों द्वारा बताई गई तांबे की ट्यूबों की मांग (रुपयों में) पर आधारित था। प्रत्येक राज्य द्वारा बताई गई मांग के अनुपात के अनुसार कुल उपलब्ध 7 लाख रु० की राशि वितरित की गई थी।

26 फरवरी, 1966 को किया गया नियतन राज्यों के उद्योग निदेशकों द्वारा बताई गई तांबे की ट्यूबों (टनों में) की निर्धारित वार्षिक मांग पर आधारित था। आसाम, जम्मू और काश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर जिन्हें लक्ष्य आधार पर नियतन किया गया था, प्रत्येक राज्य की यथानुपात मांग (टनों में) के अनुसार कुल उपलब्ध 15,91,600 रु० की राशि का वितरण किया गया।

केरल राज्य में थक्कानकुट्टूर में रेलगाड़ी के रुकने की व्यवस्था

4276. श्री मुहम्मद कोया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में तिरूर के निकट थेक्कानकुट्टूर में रेलगाड़ी के रुकने की व्यवस्था करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : इस पर विचार किया जा रहा है।

भारत-बलगारिया संयुक्त उपक्रम

4278. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री फिरोडिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलगारिया की सरकार भारत और बलगारिया के सहयोग से पंजाब राज्य में संयुक्त औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर; और

(ग) इस पर कुल कितना खर्च होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : बलगारिया के जनवादी गणराज्य का एक व्यापार शिष्टमंडल जो मार्च-अप्रैल, 1966 में भारत आया था, चण्डीगढ़ भी गया था जहां उसने पंजाब सरकार के अधिकारियों से बातचीत की थी। इस बातचीत में किये गये निर्णय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सुखाई गई मछली का श्रीलंका को निर्यात

4279. श्री वासुदेवन नायर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रधान हाल में श्रीलंका गये थे; और

(ख) क्या भारत से श्रीलंका को सुखाई गई मछलियों के निर्यात के बारे में कोई करार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मार्च 1966 में समद्री उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद, एर्नाकुलम के प्रधान के नेतृत्व में तीन व्यक्तियों के एक दल ने श्रीलंका का दौरा किया।

(ख) सहकारी थोक संस्थान, श्रीलंका के साथ भारत से श्रीलंका को सुखी मछलियों के और अधिक निर्यात करने की व्यवस्था कर ली गई है।

Engine without Driver

4280. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a railway engine along with 3 bogies moved without driver from Dinanagar up to Dhariwal, a distance of 20 miles on the 29th March, 1966; and

(b) if so, the causes thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The accident occurred on 28-3-66.

(b) The cause is under investigation.

रेल के डिब्बे

4281. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रेल के डिब्बे पमाने पर बनाये जाते है; और

(ख) यदि हां, तो फालतू डिब्बों का निर्यात करने के लिय क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जो, हां आवश्यकता के अनुसार ।

(ख) विदेशो से पूछताछ किये जाने पर कई बार प्रतियोगी दरें पेश की गयी है । एक भारतीय निर्माता को मीटर लाइन के 35 सवारी डिब्बों के लिए आर्डर भी प्राप्त हो चुका है जिनकी कीमत लगभग 59 लाख रुपये है । सवारी डिब्बों के निर्यात के लिए आगे प्रयास किया जा रहा है ।

राखा तांबा खानें

4282. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न बिहार में राखा तांबा खानों तथा आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुण्डा खानों में से तांबा निकालने के लिये किन्ही दूसरे देशों से सहयोग प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है; और

(ग) करार की शर्तें तथा निबन्धन क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : बिहार के राखा तांबा निक्षेपों के विकास के लिय तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के हेतु रूसी राज्य संघ से कहा गया है । आंध्र प्रदेश

में अनिगुडल के तांबा निक्षेपों के विकास में सहायता प्रदान करने का अमरीका की फर्म ने एक प्रस्ताव भेजा है।

(ग) ऊपर के दोनों प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कपड़े के मूल्य

4283. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कपड़े के थोक तथा फुटकर व्यापारी कपड़े की लोकप्रिय किस्में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 30 मार्च, 1966 को नागरिक सम्भरण विभाग ने दिल्ली में कुछ दुकानों पर छापा मारा था;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश के कुछ स्थानों, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, से कुछ सूचनाएं मिली थीं कि नियंत्रित कपड़े की कुछ किस्में अंकित कीमतों से अधिक पर बेची जा रही हैं। नागरिक सम्भरण विभाग ने, वस्त्रायुक्त कार्यालय के प्रवर्त्तन स्कन्ध के सहयोग से 30 मार्च, 1966 को दिल्ली में कुछ थोक दुकानों का निरीक्षण किया। पता चला है कि दो थोक व्यापारी कपड़े पर अंकित खुदरा कीमतों से अधिक कीमतें लेते हुये पाये गये। इन दोनों मामलों में अभियोग चलाने के लिये कार्रवाई की जा रही है। बाद में अप्रैल, 1966 के पहले सप्ताह में और कुछ निरीक्षण किये गये और पता चला है कि ग्यारह फुटकर व्यापारियों ने अधिक कीमत ली हैं। इन ग्यारह मामलों में भी अभियोग चलाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। निरीक्षण परिस्थिति पर कड़ी दृष्टि रखे हुये है और उसने सभी राज्य सरकारों को नियतकालिक सरकार करने की सलाह दे दी है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कपड़े की नियंत्रित किस्में अंकित किमतों से अधिक पर न बेची जायं।

नवीनतम सूचनाओं से प्रकट होता है कि लगभग सभी स्थानों पर उपभोक्ताओं को नियंत्रित कपड़ा नियंत्रित खुदरा कीमतों पर बेचा जा रहा है।

Industrial Development of Maharashtra

4284. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the pace of the industrial development of Maharashtra has been very slow and unsatisfactory; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibhudhendra Misra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Stoppage of 19 Dn. and 20 Up Trains at Bangrod

4285. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Kashi Ram Gupta :
Shri S. M. Banerjee : Shri Daji :
Shri Maurya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the stoppage of 19 Dn. and 20 Up trains running between Delhi and Bombay has been cancelled at Bangrod station in Ratlam Division since the 1st April, 1966;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether much inconvenience is being experienced by the passengers as a result thereof and they have even tried to stop the train forcibly there; and

(d) if so, the steps being taken to stop the train at Bangrod station?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, with the approval of Western Railway's Time Table Committee and Local Government.

(b) Owing to very meagre long distance traffic offering at Bangrod.

(c) & (d). As suitable alternative services are available in 129 Dn./130 Up Baroda-Mathura Parcel-cum-passenger trains scheduled to stop at Bangrod and which precede the Expresses with a short margin, there is no inconvenience to the passengers, nor is the restoration of stoppage of Dehra Dun Expresses justified.

प्याज का निर्यात

4286. श्री मुथिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्रीलंका की सरकार भारतीय निर्यातकों में अवांछनीय प्रतियोगिता पैदा करके न्यूनतम मूल्यों पर प्याज खरीदती है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप प्याज की खेती में भारी कमी होने के अलावा भारत को विदेशी मुद्रा की भारी हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्याज का निर्यात-मूल्य निर्धारित करने का है; और

(घ) मद्रास के आयात तथा निर्यात के संयुक्त नियंत्रक की अध्यक्षता में एक शिखर निकाय स्थापित करने के 20 मार्च, 1965 को किये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) लंका की सरकार ने फरवरी 1965 से टैण्डर प्रणाली का प्रचलन करके अपने खाद्य आयुक्त के द्वारा प्याज के आयात का केन्द्रीयकरण कर लिया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य आयुक्त सम्भावित विदेशी सम्भरणकर्त्ताओं से भाव मंगाता है । आयात की कीमत तथा परिमाण निर्धारित करने के पश्चात निजी व्यापारी गत वर्षों में किये गये अपने व्यापार के आधार पर वास्तविक आयात करते हैं। टैण्डर प्रणाली ने निस्संदेह हमारे निर्यातकों में प्रतियोगिता पैदा कर दी है ।

(ख) 1964 में लंका को निर्यात किय गय 65,816 मी० टन प्याज से 215 लाख रु० प्राप्त हुये और 1965 में 60,500 मी० टन के निर्यात से 156 लाख रु० प्राप्त हुये। सरकार को इस बारे

में पता नहीं है कि लंका की सरकार द्वारा टैण्डर प्रणाली का प्रचलन करने के परिणामस्वरूप प्याज की खेती पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है ।

(ग) तथा (घ) : मामला विचाराधीन है ।

लकड़ी के स्लीपरों में आग लगाया जाना

4287. **श्री बसवन्त :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 अप्रैल, 1966 को जब कुछ उपद्रवी लोगों ने पूर्वी रेलवे के लालगोला स्टेशन पर पुल के नीचे लगे लकड़ी के स्लीपरों में आग लगा दी थी तो तीन रेल गाड़ियों को कृष्णानगर, धुबुलिया और मुड़ागाच्छा स्टेशनों पर रुकना पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। सही स्थिति यह है कि धुबुलिया और मुड़गाच्छा स्टेशनों के बीच कि०मी० 114/7/8 पर पुल नं० 24 में लगे लकड़ी के स्लीपरों के ढेर में अचानक आग लग गयी । शायद इंजन से कोयले की चिंगारी निकलने की वजह से यह दुर्घटना हुई । जांच से पता चला कि आग अचानक लग गयी । आग बुझाने के लिए तुरन्त कार्रवाई की गयी । पुल की मरम्मत का काम तेजी से पूरा किया गया । संरक्षा की दृष्टि से कुछ गाड़ियां रोक ली गयीं और जब यह प्रमाणित हो गया कि गाड़ियों के आने जाने के लिए पुल उपयुक्त है तो गाड़ियां सामान्य रूप से चलने लगीं ।

Fluorite Mine at Mandav (Rajasthan)

4288. **Shri Rattan Lal :** Will the Minister of **Mines** and **Metals** be pleased to state :

(a) whether the development work of Fluorite Mine in village Mandav of of District Dungarpur (Rajasthan) is to be undertaken by Rajasthan Government or the Central Government during the Fourth Plan;

(b) the steps taken in this regard and the estimated amount to be spent thereon; and

(c) whether Fluorite is expected to be available there in sufficient quantity ?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) The development of the Mando-ki-pal fluorite deposits in Dungarpur district (Rajasthan) will be taken up by the Rajasthan Government.

(b) Beneficiation tests had been conducted on the samples of ore and it has been found that both metallurgical and acid grade fluorite concentrates could be produced. Following the preparation of a feasibility report by a Canadian firm, the State Government are taking steps to appoint a Consulting Engineer for the design, erection and commissioning of a plant to produce concentrates. The cost of the project is tentatively estimated at Rs. 175 lakhs.

(c) The 'proved' reserves in the deposits are 1·6 million tonnes and 'probable' reserves another 0·40 million tonnes. 300 tonnes of ore per day are expected to be produced.

शयन डिब्बों (स्लीपर कोच) में ताले और चाबी का व्यवस्था

4289. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहलेजा घाट नरकटियागंज सेक्शन पर दो शायिकाओं वाले शयन डिब्बों में ताले और चाबी की व्यवस्था किये जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रात के समय यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए इन डिब्बों के दरवाजों में ताला लगाने की व्यवस्था पर विचार करने के सम्बन्ध में अभी हाल में एक सुझाव मिला है ।

(ख) ताला लगाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे आवश्यक कार्रवाई कर रही है ।

अल्ट्रासानिक रेल फ्लॉ डिटेक्टर

4290. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी रेलें महीन दरारों का पता लगाने के लिये काराट क्रामैर अल्ट्रासानिक रेल फ्लॉ डिटेक्टर का प्रयोग कर रही है ; और

(ख) उसका क्या परिणाम रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे ।

(ख) इन डिटेक्टरों की सहायता से दोनों रेलों पर अभी तक कुल मिलाकर 611 किलोमीटर रेल पथ में खराब पटरियों की जांच की गयी है और इस जांच के फलस्वरूप जिन पटरियों को बदलना जरूरी है, उन्हें बदलने के लिए कार्रवाई की गयी है ।

यात्रियों को तंग करने की घटना

4291. श्री दिगे : **श्री मुकाने :**
श्री कांबले : **श्री भा० दा० देशमुख :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 मार्च, 1966 को खडवा-काचेगुडा पैसेंजर गाड़ी से यात्रा करने वाले विद्यार्थियों के एक दल ने हिंगोली और धामनी के बीच एक स्त्री तथा पुरुष यात्रियों को तंग किया था ;

(ख) क्या रेलगाड़ी में एक लड़की के साथ छेड़-छाड़ की घटना भी हुई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारी तंग किये जाने वाले यात्रियों को कोई संरक्षण नहीं दे सके ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इस जांच के परिणाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 16 मार्च, 1966 को बासमत-नगर स्टेशन पर 581 खण्डवा-काचेगुडा सवारी गाड़ी के गार्ड को एक यात्री ने बताया कि कुछ विद्यार्थियों ने उसकी पगड़ी बाहर फैंक दी है और वे उसे उस डिब्बे में नहीं घुसने दे रहे हैं, जिसमें वह हिंगोली से यात्रा कर रहा है ।

(ख) इस तरह की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली ।

(ग) गाड़ी के गार्ड ने सरकारी रेलवे पुलिस के एक सिपाही को उस यात्री की सहायता करने के लिए कहा और वह सिपाही गाड़ी में उसके साथ गया ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

Woollen Uniforms for Carriage Khalasis

4292. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the supply of woollen uniforms to the carriage khalasis has been discontinued;

(b) if so, since when; and

(c) the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, except on certain divisions of the South Eastern Railway and temporarily on Western Railway.

(b) From Winter, 1965-66.

(c) Under the standardisation on an all-Railway basis, the Khargpur, Khurda Road and Waltair Divisions of the South Eastern Railway have been reclassified as "All Summer" areas and the supply of woollen jersies previously given has been discontinued.

On the Western Railway the supply of Jersies has been discontinued in view of the economy orders issued in January, 1966 to the effect that Railways should keep on following their Dress Regulations prevailing prior to standardisation in February 1963 if that was comparatively less liberal. On the Western Railway Jersies were not being supplied to Carriage Khalasis prior to standardisation in February, 1963.

Uniforms for Railway Running Staff

4293. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of uniforms provided to the railway running staff has been reduced;

(b) whether it is also a fact that previously they were provided with four coats and four pants annually but now the number has been reduced to three each; and

(c) if so, the reasons therefor and also for lowering the quality of the cloth?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) & (c). According to the standardisation of Uniforms done in Feb. 1963, only Guards and Brakesmen are eligible to four sets of summer uniforms in places which have both summer and winter but in view of the present Emergency and the need for stringent economy in expenditure, instructions have been issued in Jan. 1966 that till the end of 1966-67, Railways should not implement these

orders and that they should keep on following their old practice prevailing prior to this date if that was comparatively less liberal. This has resulted in the number of sets for summer being reduced in certain cases to three sets or a lower number as may be admissible according to the Dress Regulations of the Railways prevailing prior to February, 1963.

As regards quality of cloth, efforts are made to obtain good quality of cloth through Government agencies, as far as possible.

Railway Training School, Chandausi

4294. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the trainees who have recently joined the refresher course in the Railway Training School, Chandausi have sent their complaints to Government telegraphically;

(b) if so, the nature of the complaints; and

(c) the steps taken to remove their grievances?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

तीसरी श्रेणी के शयन डिब्बे (स्लीपर कोच)

4295. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मार्गों पर चलने वाली प्रमुख रेलगाड़ियों में 1 अप्रैल, 1966 से तीसरी श्रेणी के अतिरिक्त शयन डिब्बे लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन गाड़ियों में ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं । लेकिन 1—4—66 से निम्नलिखित गाड़ियों के तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने की सुविधा की व्यवस्था की गयी है :

(i) नं० 53 डाउन/54 अप मदरास-हैदराबाद एक्प्रेस गाड़ी ।
(ii) नं० 89 अप/90 डाउन हावड़ा-मदरास तेज़ सवारी/एक्सप्रेस गाड़ी
(iii) नं० 25 डाउन/26 अप कोचिन-बेंगलूरु एक्सप्रेस गाड़ी ।
(iv) नं० 41 डाउन/42 अप मदरास-कोचिन-केरल एक्सप्रेस गाड़ी ।
(v) नं० 207 अप/208 डाउन बेंगलूरु-पूना दक्कन एक्सप्रेस गाड़ी ।
(vi) सप्ताह में दो बार चलने वाली नं० 5 अप/6 डाउन टाटानगर-वाल्तेर एक्सप्रेस गाड़ी ।

गोरखपुर में कागज बनाने का कारखाना

4296. डा० महादेव प्रसाद : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों का एक दल कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिये गोरखपुर जिले के कुछ स्थानों में हाल में गया था और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) दल की रिपोर्ट मई, 1966 के अन्त तक मिल जाने की आशा है ।

Scrap Goods Factory in Gorakhpur District

4297. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he went to Anandnagar in Gorakhpur district in February, 1966;

(b) if so, whether some people had requested him at that time or before that time regarding the setting up of a scrap goods factory in Gorakhpur district and he had given an assurance to take necessary steps in this regard; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). Some persons spoke about their intention to put up a rolling mill based on scrap. No formal proposal, however, has since been received.

कीरतपुर साहिब स्टेशन पर रेलवे गोदाम

4298 श्री दलजीत सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री 11 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1970 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीरतपुर साहिब स्टेशन पर गोदाम वाले कमरे का आकार क्या है तथा गोदाम के लिये बनाये जा रहे अथवा जाने वाले कमरे का आकार क्या है ;

(ख) कीरतपुर साहिब स्टेशन पर 1966 में अब तक सीमेंट तथा उर्वरक के कुल कितने बोरे आये ; और

(ग) ये बोरे कहां रखे गये ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) माल रखने के लिए $10' \times 20'$ का एक कमरा और साथ में $10' \times 8'-6''$ का एक बरामदा बनाया गया है । कोई नया निर्माण-कार्य नहीं हो रहा है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है ।

(ख) 1966 में अब तक उर्वरक के 135 और सीमेंट के 17 बोरे प्राप्त हो चुके हैं ।

(ग) ये बोरे बरामदे में तिरपाल से ढक कर रखे गये थे ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत इन अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) अत्यावश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजन के लिए उत्पादन तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 1966 जो दिनांक 26 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1027 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एस० ओ० 1028 जो दिनांक 28 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) एस० ओ० 1029 जो दिनांक 28 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6117/66।]**

इलायची नियम

श्री शफी कुरेशी : मैं इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 8 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1144 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6118/66।]**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

एक सौ तीनवां और एक सौ चारवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं शिक्षा मंत्रालय—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला नई दिल्ली, और केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी, के बारे में प्राक्कलन समिति का 103 वां और 104 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

उनचासवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुनझुनू) : मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1963-64 के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में लोक लेखा समिति का 49 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PULLIC UNDERTAKINGS

तीसवां प्रतिवेदन

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव क बारे में (प्रश्न)
RE:MOTION FOR ADJOURNMENT (Query)

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Mr. Speaker, I had tabled a motion for Adjournment signed by 28 Members.

Mr. Speaker : I will not listen in this manner. The hon. Member may write to me about it.

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : सभा को पता ही है कि विभिन्न मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को चर्चा तथा स्वीकृति के लिये किस क्रम में लिया जायेगा। कल कार्य-मंत्रणा समिति में यह सुझाव दिया गया था कि शुक्रवार, 29 अप्रैल, 1966 को 2 बजे शेष मांगों को सभा में मतदान के लिये रखा जाये। कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्यों तथा सभा के विभिन्न दलों के विचारों में विभिन्नता होते हुए भी मुझे आशा है कि आप इस बात के लिये सहमत होंगे कि शेष मागों को शुक्रवार, 29 अप्रैल को 2 बजे के लिये मतदान के लिये रखा जाये। मांगों पर मतदान के बाद सभा में वित्त विधेयक, 1966 को विचार करने तथा पारित करने के लिये लिया जायेगा।

महोदय, आप जानते ही है कि सभा 10 मार्च, 1966 को कार्य-मंत्रणा समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर चुकी है कि 30 अप्रैल को सभा की बैठक होगी। मैंने वचन दिया था कि मैं सभा का सत्र बढ़ाने के बारे में सभा को बताऊंगा। कल कार्य-मंत्रणा समिति में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार है कि लोक सभा की तीन और बैठकें—शनिवार, 14 मई और सोमवार, 16 मई और मंगलवार 17 मई, 1966 को हों। सत्र की बढ़ाई गई अवधि में विधान कार्य तथा विधान कार्य से भिन्न कार्य पूरे हो सकेंगे। हम कुछ वे अनियमित दिन वाले प्रस्ताव भी लेंगे जिनकी सिफारिश कार्य-मंत्रणा समिति ने की है।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की परिस्थितियों के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: CIRCUMSTANCES IN WHICH SHRI LAL BAHADUR SHASTRI DIED

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, the statement made by the Minister of External Affairs on the 16th February, 1966, regarding the death of Shri Lal Bahadur Shastri at Tashkent contains inaccuracies to which we want to draw the attention of the House.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

The Minister had stated that in the Prime Minister's room there was a telephone with a buzzer which could be activated simply by lifting the receiver and the buzzing also started in his doctor's and the attendant's rooms. However the photographs of his bed and the place around it do not show any telephone, but only a table lamp. It appears that the carelessness on our part as well as on the part of the U.S.S.R. Government is being covered up through an inaccurate statement.

Secondly, in the report signed by the seven doctors, it has been stated that Sarvashri Sahai, Kapoor and Sharma went to the room of personal doctor of the Prime Minister and informed him of the Prime Minister's illness. This means that dying Prime Minister was left alone in his room. But according to the statement of the hon. Minister in the House, at about 1·20 A.M. while Prime Minister's personal staff was packing the luggage for the morning flight, they saw the late Prime Minister at the door of their room. The Prime Minister passed a little and asked for doctor. Shri Sharma and Shri Kapoor hurried forward and escorted the Prime Minister to his room while Shri Sahai woke up the doctor who immediately rushed to the Prime Minister's room. The two versions were at variance.

There should be a parliamentary or judicial inquiry about the late Prime Minister's death. It is also surprising as to how the Russian doctors signed a report narrating circumstances of which they were personally unaware.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे खेद है कि डा० राम मनोहर लोहिया ने बहुत से आरोप लगाये हैं, जो बिल्कुल निराधार हैं।

सर्वप्रथम डा० लोहिया ने यह आरोप लगाया है कि मैंने 16 फरवरी के वक्तव्य में कहा था कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री के कमरे में एक बजर वाला टेलीफोन लगा हुआ था। अपने आरोप के पक्ष में उन्होंने यह तक पेश किया है कि मृत प्रधान मंत्री के बिस्तर तथा, आसपास के स्थान के चित्र में कोई टेलीफोन नहीं दिखाई देता है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि 16 फरवरी के अपने वक्तव्य में मैंने कहा था कि प्रधान मंत्री के आवास स्थान में दो टेलीफोनों के अतिरिक्त, जिनमें से एक आन्तरिक तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन था, एक घंटी वाला टेलीफोन भी था, जो रिसीवर उठाते ही सक्रिय हो जाता था। यह घण्टी वाला टेलीफोन इस लिये लगाया गया था कि प्रधान मंत्री आवश्यकता होने पर अपने निजी कर्मचारियों को तथा डाक्टर को बुला सकें। इससे यह स्पष्ट है कि यह कभी नहीं कहा गया कि घण्टी वाला टेलिफोन प्रधान मंत्री के बिस्तर के पास था, अपितु यह कहा गया था कि घण्टी वाला टेलीफोन प्रधान मंत्री के आवास में था। प्रधान मंत्री के आवास स्थान में एक बैठक थी जिसका दरवाजा उनके सोने के कमरे में खुलता था। सभी टेलीफोन आन्तरिक, अन्तर्राष्ट्रीय तथा घंटी वाला बैठक के कमरे में में रखे हुये थे जो कि प्रधान मंत्री के बिस्तर से कुछ ही कदम पर थे। इस प्रकार उस वक्तव्य में कोई गलती नहीं थी तथा तथ्यों को छुपाने का कोई प्रसन्न नहीं किया गया है। हर संभव सावधानी बरती गई थी तथा प्रधान मंत्री को हर संभव सुविधा दी गई थी। यह आक्षेप लगाना कि लापर्वाही से काम किया गया बिल्कुल अवांछनीय है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री के आराम के लिये प्रत्येक सुविधा दी गई थी, जिसके लिये हम रूस सरकार के आभारी है।

एक और आरोप यह लगाया गया है कि मृत्यु के समय प्रधान मंत्री को अकेले छोड़ दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अनुमान मेरे वक्तव्य तथा डाक्टर की रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया है। परन्तु मैं समझता हूं कि मेरे वक्तव्य तथा डाक्टर की रिपोर्ट में कोई विरोधी बात नहीं है। यह समझ लेना चाहिये कि जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री अपने कमरे के पास वाले कमरे के दरवाजे पर आये और उन्होंने

डाक्टर को बुलाया उस समय उनके तीन निजी कर्मचारी सामान बांध रहे थे और उनके डाक्टर अन्दर सो रहे थे। एक ओर तो सर्वश्री कपूर तथा शर्मा शीघ्रता से आगे बढ़कर प्रधान मंत्री को उनके कमरे में ले गये, और दूसरी ओर श्री सहाय ने एकदम डाक्टर चुग को जगाया, जो तुरन्त प्रधान मंत्री के कमरे में दौड़े गये। मेरे पहले वक्तव्य में केवल श्री सहाय के नाम का उल्लेख करना इस बात का द्योतक नहीं है कि डा० चुग को जगाने के लिये सर्वश्री शर्मा तथा कपूर ने प्रयत्न नहीं किया। जब वे प्रधान मंत्री को उनके कमरे में ले गये तो उसके बाद उनको किसी समय भी अकेला नहीं छोड़ा गया। मेरे पहले वक्तव्य में तथा डाक्टर की रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं है, जिसका कोई अन्य अर्थ लगाया जा सके। यह आश्चर्य की बात है कि माननीय सदस्य ने कहा है कि मुझे तथ्यों को छुपाने के लिये पांच दिन का समय मिल गया। वास्तव में स्वर्गीय प्रधान मंत्री का निधन ताशकन्द में गत जनवरी में हुआ था और उसके एक मास तथा पांच दिन बाद मैंने संसद में वक्तव्य दिया था। तथ्यों को छुपाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह बहुत दुःख की बात है कि डा० लोहिया प्रधान मंत्री के निधन के बारे में ऐसे अनुमान लगा रहे हैं तथा ऐसे आरोप लगा रहे हैं। प्रधान मंत्री की मृत्यु एक बहुत दुःखद घटना है। उनकी मृत्यु सब मानवीय शक्तियों से बाहर थी। उनकी मृत्यु इस प्रकार से हुई कि इसके बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। उनकी मृत्यु की परिस्थितियों की जांच करने के लिये किसी संसदीय, न्यायिक अथवा किसी अन्य प्रकार की जांच समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : This is no reply. This reply has rather complicated the matter.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) **:** Mr. Speaker, I want to know whether on the fateful day of Prime Minister's death, the U.S.S.R. Government . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। मुझे यह बताया गया था कि इस घटना के बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में कोई अशुद्धि है। इसलिये निदेश 115 के अन्तर्गत मैंने इस को अनुमति दे दी है। उपबन्ध यह है कि यदि कोई सदस्य आग्रह करे कि मंत्री महोदय के वक्तव्य में कोई अशुद्धि है और मंत्री महोदय इस को स्वीकार करने के लिये तैयार न हों तो वे अपने अपने वक्तव्य दे सकते हैं। साधारणतया ये विवरण सभा-पटल पर रख दिये जाते हैं और कभी कभी इन्हें पढ़ने की भी अनुमति दे दी जाती है। चूंकि अब वक्तव्य दे दिये गये हैं इसलिये अब इस पर अग्रेतर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। अब सभा इस बात का फैसला करेगी **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री रंगा (चित्तूर) **:** चूंकि ये वक्तव्य अभी दिये गये हैं अतः आप सभा से यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वह अपना फैसला अभी सुना दे। इस के साथ साथ इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है कि सदस्य इन विवरणों का ठीक तरह से परीक्षण कर सकें और इन पर बाद में चर्चा कर सकें?

अध्यक्ष महोदय : ये रिकार्ड में हैं। प्रत्येक सदस्य इन्हें पढ़ सकता है।

श्री रंगा : मैं उस प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा हूं जो हमें अपनानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्तव्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया जाना है। यदि चर्चा के लिये कोई सूचना दी जाती है तो वह बिल्कुल ही एक अलग बात होगी। अभी इस समय और कुछ भी नहीं किया जा सकता।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, you are only to give your judgement on this matter. After all buzzer telephone had been useful only when it would have been within the reach of the Prime Minister. But now the hon. Minister has stated that it was beyond his reach.

Mr. Speaker : No further discussion can be allowed on this matter now. Nor I have to give any judgment on this matter. Both the statements are now before the House. It is now for the House to give any judgment. If some notice is given for discussion, that would be a different matter.

Dr. Ram Manohar Lohia : This matter should be enquired into by a Parliamentary Committee.

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सैतालीसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 47वें प्रतिवेदन से, जो 21 अप्रैल, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मुझे खुशी है कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिये दो घंटे का और समय देने के लिये समिति सहमत हो गई है और मुझे आशा है कि उन मंत्रालयों के बारे में, जिनके सम्बन्ध में अब चर्चा नहीं हो सकी है, चर्चा करने के लिये आगामी सत्र में पर्याप्त समय दिया जायेगा ।

पिछली बार मेरे द्वारा उठाये गये एक मामले के बारे में आपने बताया था कि इस सम्बन्ध में राज्य सभा के सभापति से बातचीत हो रही है। आशा है कि कोई ऐसा उपाय किया जायेगा जिससे इस सभा द्वारा नियुक्त की कई तीन व्यक्तियों की समिति राज्य सभा के लेखों तथा मांगों की जांच-पड़ताल कर सके। इस बारे में अब क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने राज्य-सभा के सभापति तथा नेता से बातचीत की है। वे सुझाव जो सभा ने यहां दिये थे, उनके सामने रख दिये गये हैं। उस सभा के नेता इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैंने आपको तथा इस सभा को जो सुझाव दिया था वह यह है कि यदि राज्य सभा के प्राक्कलनों का परीक्षण करना ही है तो इनका परीक्षण लोक-सभा तथा राज्य-सभा की एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : पहले यह सुझाव दिया गया था कि यदि इन प्राक्कलनों का परीक्षण करना है तो दोनों सभाओं के प्राक्कलनों का परीक्षण करने के लिये एक संयुक्त समिति होनी चाहिये। मैंने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया था और यह सुझाव दिया था कि यदि दोनों सभाओं का कार्य सुचारू रूप से चलाया जाना है तो यह अधिक अच्छा होगा कि राज्य-सभा के प्राक्कलनों का परीक्षण करने के लिये, एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाये। हमारी सभा इस को स्वीकार कर लेगी। यह सुझाव मने सभा की ओरसे दिया था और सभा इस से सहमत है तथा मुझे प्रसन्नता है कि राज्य-सभा के नेता ने भी यही कहा है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह नहीं हो सकता . . . . **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, इस समस्या का शायद यही सर्वोत्तम हल है। हमने यह स्वीकार कर लिया है कि जहां तक लोक-सभा के प्राक्कलनों का सम्बन्ध है, इनका परीक्षण केवल इस सभा की समिति द्वारा किया जायेगा तथा जहां तक राज्य-सभा के प्राक्कलनों का सम्बन्ध है, इनका परीक्षण दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या ऐसा इसी वर्ष से किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह अभी से नहीं हो सकता है क्योंकि प्राक्कलन भेजे जा चुके है और सब कुछ पास हो गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : समिति अब भी इन पर विचार कर सकती है और हम इन मांगों पर अब भी चर्चा कर सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं सभा से यह अनुरोध करता रहा हूं कि आपातकाल की स्थिति को समाप्त करने तथा भारत रक्षा नियमों को वापस लेने के बारे में यथासम्भव शीघ्र वक्तव्य दिया जाये। मुझे खुशी कि आज के समाचार पत्रों में यह छपा है कि मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है और मुख्य मंत्रियों को भी बुलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा हम गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के अन्तर्गत कर सकते है।

श्री स० मो० बनर्जी : समाचार पत्रों में यह भी छपा है कि प्रधान मंत्री आपातकाल स्थिति समाप्त करने के पक्ष में हैं। मुख्य मंत्रियों की बैठक के पश्चात सोमवार को एक वक्तव्य दिया जाने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बैठक तो होने दीजिये। क्या वे पहले ही वक्तव्य दे दें ?

श्री स० मो० बनर्जी : आगामी सप्ताह में सोमवार को वक्तव्य दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन तथा हवी इंजीनियरी कारपोरेशन में आग लगने के बारे में भी चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : It has been accepted by Business Advisory Committee that a discussion can take place on Indo-Pak. conflict.

Mr. Speaker : In next week it is not possible to take any other discussion except financial activities.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Sir, you have announced in this august House that there will be no sittings on Saturdays and as such the decision to sit on Saturday may cause inconvenience to several Members in their programmes that they have already made. The session may be extended by one or two days instead of calling sitting on Saturday.

Shri Maurya : Sir, the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are received very late. His report for the year 1963-64 has been received now in 1966 and this report is pending for discussion. Some arrangements should be made to place the Report on the Table and discuss it immediately after the same is received.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, the matter relating to illegal occupation of 36 acres of land in Sialkot by Pakistan should be taken up for discussion in this House during the current session.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Sir, the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was not discussed last year and the year before that also. According to present indications, this time also, the Repoort is likely to be referred to the committee without taking it up for discussion. It is necessary to have a discussion on this Report by or before 29th April.

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : अगले सप्ताह प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति के लिए चुनाव हो रहे हैं। मैं आपके जरिये गृहकार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या नजरबन्द संसद सदस्यों को इन चुनावों में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी ?

Shri A. P. Sharma (Buxar) : Sir, there was an outbreak of fire in the Ranchi Heavy Engineering regarding which we have been demanding a discussion on that incident for the last two years. You were also pleased to give us an assurance regarding the same. I request that the same may also be taken up for discussion in this session.

श्री मुहम्मद ताहिर (किशनगंज) : गत वर्ष वर्षा कालीन अधिवेशन में शिक्षा मंत्री ने इस सभा में कहा था कि वह अगले सत्र में अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में एक व्यापक विधेयक पुर:-स्थापित करेंगे। क्या इस सत्र में ऐसा एक विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान, इस सत्र में हम दो से अधिक अनियत दिन वाले प्रस्ताव नहीं ले सकते और ऐसे किन दो प्रस्तावों को लिया जाये, यह निर्णय सभा को करना है।

जहां तक शनिवार, 30 अप्रैल को सभा की बैठक का सम्बन्ध है, कार्य-मंत्रणा समिति में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके एकमत से यह निर्णय किया गया था कि 30 अप्रैल को सभा की बैठक होगी।

चूंकि सभा 13 तारीख को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो रही थी, हमने यह निर्णय किया है कि सभा तीन दिन और बैठेगी, इस लिये हमने शनिवार, 14 तारीख को भी उसमें शामिल कर दिया है।

उठाये गये अन्य प्रश्नों के बारे में मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा। जहां तक कमिश्नर, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां, के प्रतिवेदन के सम्बन्ध है, किसी भी पुरानी रिपोर्ट पर चर्चा होनी बाकी नहीं है। केवल नवीनतम प्रतिवेदन सभा के समक्ष है। यदि समय उपलब्ध हुआ, तो उस पर इसी सत्र में चर्चा की जायेगी अन्यथा अगले सत्र में उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 47 वें प्रतिवेदन से, जो 21 अप्रैल, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

वर्ष 1966-67 के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
16	वैदेशिक-कार्य	14,41,69,000
17	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	5,10,82,000

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : अध्यक्ष महोदय, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में इस बात को छिपाया नहीं गया है कि पाकिस्तान तथा चीन के साथ जो भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं, हमारे संबंध काफी अच्छे नहीं हैं। आज संसार की सम्पूर्ण स्थिति को देखते हुये ऐसा महसूस होता है कि हमारी समस्यायें तब तक अन्तिम रूप से हल नहीं हो सकती जब तक विश्व के दक्षिण पूर्व एशियाई भाग में भारत, नैपाल, पाकिस्तान, बर्मा तथा श्रीलंका देशों का एक ऐसा महासंघ न बन जाये जो केवल वास्तव में धर्म निर्पेक्ष ही नहीं अपितु पाकिस्तान को भी स्वीकार्य हो। आज के विश्व में बड़ी शक्तियों के मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के यही एकमात्र उपाय हो सकता है।

साम्यवादी चीन को खुश करने अथवा "भाई-भाई" के तैयार किये गये वातावरण को नष्ट न करने की दृष्टि से हमने फार्मोसा की लोकतंत्रीय चीनी सरकार को राजनयिक मान्यता नहीं दी। किन्तु अब इस वातावरण की कोई भी संभावना नहीं है, अत: फार्मोसा की चीनी सरकार को, जो लोकतंत्रीय है और मित्र सरकार है, मान्यता न देने का कोई उचित कारण नहीं है। भारत सरकार को इस समस्या पर नये सिरे से तथा बिना किसी पक्षपात के विचार करना चाहिये।

जहां तक हमारे सबसे निकट पड़ौसी देश पाकिस्तान का सम्बन्ध है, वह केवल भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं अपितु ऐतिहासिक तथा अध्यात्मिक दृष्टि से भी भारत का एक अंग है। किन्तु जब तक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कटु बने रहेंगे, जैसे कि इस समय है, तब तक इस उपमहाद्वीप में कोई प्रगति नहीं हो सकती। निरन्तर संघर्ष तथा एक दूसरे के प्रति अविश्वास की स्थिति में भारत तथा पाकिस्तान दोनों में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इस दृष्टिकोण से भारत और पाकिस्तान के बीच यही मूलभूत प्रश्न है और न कि काश्मीर समस्या। इसी कारण हमें पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करना आवश्यक है। हर वक्त बड़े बड़े मामलों पर पारस्परिक वार्ता के लिये अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें पाकिस्तान के साथ स्थायी रूप से बातचीत करने का तरीका निकालना चाहिये।

दक्षिण वियतनाम की समस्या विश्व में आज तक एक चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रतिवेदन में दक्षिण वियतनाम के बारे में यह कहा गया है कि वियतनाम का स्थायी हल केवल शान्तिपूर्ण तरीकों से ही किया जा सकता है और अमरीका को दक्षिण वियतनाम से अपनी सेनायें हटानी चाहिये। किन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि वियतनाम समस्या का शान्तिपूर्ण हल के लिये वहां से अमरीकी सेनाओं

[श्री कपूर सिंह]

का हटाया जाना क्यों आवश्यक है। संसार के इस प्रदेश की राजनैतिक स्थिति के बारे में अमरीका का दृष्टिकोन यह है कि यदि दक्षिण वियतनाम नेशन लिबरेशन फ्रन्ट के रूप में क्रियाशिल साम्यवादी तत्वों के कब्जे में चला जाता है, तो कम्बोडिया, लाओस, इन्डोनेशिया, मलयेशिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका और अन्ततोगत्वा भारत भी साम्यवाद के शिकार हो जायेंगे। किन्तु हमारा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इस डोमिनोस मत कल्पनाशील मात्र समझता है। इस प्रश्न पर गहन रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिये इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जाना चाहिये।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत तथा अरब विश्व के बीच परम्परागत अच्छे सम्बन्ध कायम रखे गये हैं। किन्तु यह बात भी समझ में नहीं आती कि अरब देशों के साथ हमारी मित्रता से यह किस प्रकार अनिवार्य हो जाता है कि हम इसरायल जैसे लोकतंत्रीय सरकार के साथ ऐसा व्यवहार करें जसा कि हम कर रहे हैं। कोई भी ईमानदार तथा निष्पक्ष आदमी इस नीति का अनुमोदन नहीं करेगा। अरब दशों के नाराज हो जाने के आशंका से भारत उसे मान्यता नहीं दे रहा है, किन्तु यकीनन भारत जसा बड़ा और महान देश केवल मित्रों तथा शत्रुओं की नाराजगी को ध्यान में रख कर अपनी स्वतंत्र वदेशिक नीति निर्धारित नहीं कर सकता। यदि निष्पक्ष रूप से विचार किया जाये तो इसरायल को राजनयिक मान्यता न दिये जाने का कोई भी कारण नहीं बनता और ऐसी मान्यता न देना उन्नत लोगों की दृष्टि में भारत की शान तथा मान को कम करना है।

जहां तक रोडेशिया का संबंध है, प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत सरकार ने आइन स्मिथ की श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा गैर-कानूनी रूप से सत्ता के हथियाने की कड़े शब्दों में निन्दा की। 11 और 12 फरवरी, 1966 को लागोस में राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में केवल हमारा ही एक मात्र ऐसा देश था जिसका प्रतिनिधित्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जो न तो देश का प्रधान था और न ही प्रधान मंत्री था। इस सम्मेलन में केवल एक ही विवाद पर विचार किया गया वह यह कि श्वेत अल्पसंख्यक जातियों द्वारा सत्ता का हथियाया जाना। इस सम्मेलन में हमारे प्रतिनिधि का केवल यही योगदान था कि उन्होंने यह कहा कि स्वाधीनता की एकपक्षीय घोषणा को स्वाधीनता की अवैध घोषणा कहा जाना चाहिये अर्थात रोडेशिया में श्वेत अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्वाधीनता की जो एकपक्षीय घोषणा की गई है उसे स्वाधीनता की अवैध घोषणा कहा जाना चाहिये। हम वैदेशिक-कार्य मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारी स्थिति यह है कि सत्ता बदलने के ढंगों को ध्यान में रखे बिना सत्ता बदलने के सभी मामलों में केवल वैधता ही सार है। उदाहरणार्थ यदि ब्रिटेन की साम्राज्ञी द्वारा रोडेशिया की सत्ता संवैधानिक आधार पर उसी श्वेत अल्पसंख्यक समुदाय को सौंपी जाती जिसने इस समय सत्ता हथियाई है, तो क्या हम इसे स्वीकार कर लेते? क्या जातीय भेदभाव वाली सत्ता की वधता को मानना हमारी मूल नीतियों तथा विचारधाराओं के अनुकूल है; यदि नहीं, तो लागोस में हमारे प्रतिनिधि ने ऐसा क्या कहा?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : हमारी वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्तों जिन्हें सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है, के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है किन्तु उन समस्याओं के बारे में मैं अपना वास्तविक दृष्टिकोण सभा के समक्ष रखूंगा जिनका असर हमारे देश पर गहरे रूप से पड़ता है। सबसे पहले जो बात आती है वह है—पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध। ताशकन्द समझौते के पश्चात् हमने यह महसूस किया थ, कि हम कुछ द्विपक्षीय बैठकों तथा कार्यवाहियों द्वारा पाकिस्तान से अपने मतभद दूर कर लेंगे। और हमने इस समझौते का वास्तविक अर्थों में पालन कराने की शीघ्र घोषणा की। हमने बड़े संयम से काम लिया और पाकिस्तान की उत्तेजनाओं के बावजूद भी हमने यथासंभव सीमा तक संयम सेकाम लिया जहां हम प्रधान मंत्री के इस दृढ़ निश्चय का स्वागत करते है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिये दृढ़ कार्यवाही करेंगी कि ताशकन्द समझौते की भावना को समाप्त न होने दिया जाय, वहां एक बड़ाप्रश्न यह उठता है कि पाकिस्तान ने ऐसा रुख क्यों अपना रखा है जब कि भारत ने पाकिस्तान को उत्तेजत करने के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं किया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के वर्तमान शासक या तो कुछ घरेलू दबाव अथवा बाह्य राय के

कारण शान्ति के मार्ग पर नहीं चलना चाहते। यदि हम इस मामले की वास्तविक स्थिति समझने की कोशिश नहीं करते और स्थिति की गंभीरता की जांच नहीं करते तो इसका अर्थ यह होगा कि हम स्थिति की वास्तविकता की उपेक्षा कर रहे हैं। पिछले सितम्बर में पाकिस्तान का आक्रमण करने का उद्देश्य काश्मीर को बल द्वारा लेना था जिसमें वह असफल रहा है। अब उसने महसूस कर लिया है कि वह भविष्य में भी बल प्रयोग द्वारा काश्मीर नहीं ले सकेगा। इसलिये पाकिस्तान ताशकन्द समझौते की आड़ में कुछ प्राप्त करना चाहता था जिसे उसने प्राप्त कर लिया है और उसके बाद उसने वही अपना पुराना रवया अपना लिया है। अब वह अपनी स्थिति समझता है और अब वह पहले से अधिक बुद्धिमत्ता से भी काम लेगा। वह अब खुले आक्रमण की अपेक्षा अधिक खतरना कार्य करना चाहता है। उसने मिजों लोगों तथा चीन से सम्पर्क स्थापित कर लिये हैं। चीनी नेताओं ने खुलेआम यह घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान पर आक्रमण होने की स्थिति में वह उसका हर संभव तरीके से समर्थन करेगा और उसने पहले ही पर्याप्त मात्रा में हथियार, विस्फोटक पदार्थ, काफी टैंक तथा जेट विमान भेजना आरम्भ कर दिया है जिनकी वहां प्रदर्शनी भी लगाई गयी थी। हमें पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से यह महसूस करा देना चाहिये कि यदि वह फिर से शरारतें करेगा, अथवा हमारे साथ चालबाजी करेगा या हमें परेशान करेगा तो उसे भी उसी ढंग में उत्तर दिया जायेगा जिससे कि उसका जीना कठिन हो जायेगा। उसके साथ नरमी से पेश आने का कोई भी भयंकर परिणाम निकल सकता है। भारत के प्रति ब्रिटेन के रवैये तथा अपनाई जा रही नीतियों को देखते हुये हमें यह महसूस करना चाहिये कि ब्रिटेन भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के अधिक निकट है और इसलिये हम उससे कुछ आशा नहीं कर सकते। अमरीका के रवैये से हमें अधिक आश्चर्य हुआ है। चीन के साथ पाकिस्तान की सांठगांठ होने के बावजुद भी अमरीका अभी तक स्पष्ट रूप से यह निश्चित नहीं कर पाया है कि पाकिस्तान को फिर से सैनिक सहायता दी जाये अथवा नहीं। यदि चीन और रूस के विरुद्ध इस्तेमाल के लिये अमरीका पाकिस्तान को हथियार न देता, तो वह कभी भी भारत के विरुद्ध आक्रमण नहीं कर सकता था। अमरीका ने खेद प्रकट करने तथा उन उपकरणों का प्रयोग भारत के विरुद्ध प्रयोग करने के लिये भत्सना करने के बजाये भारत तथा पाकिस्तान को समान स्तर पर रखा है और भारत को वह आर्थिक सहायता देना भी बन्द कर दिया जिसके लिये उसने वचन दिया था। अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों में यह सबसे अधिक हैरानी की बात है।

हम किसी भी देश से कोई चीज प्राप्त करने का दावा नहीं रखते। इसलिये हमें आत्म-निर्भर बनाना आवश्यक है। जब तक हम आर्थिक मामलों में अपनी स्वतंत्र नीति नहीं अपनाते तब तक हमारी विदेशी नीति स्वतंत्र नहीं हो सकती। यदि देश में कपड़ा और अनाज उपलब्ध हो तो देश किसी भी कठिनाई का मुकाबला कर सकता है। यदि हम अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये सच्चे प्रयत्न करें तो हम आसानी से आयात बन्द कर सकते हैं। हमें खाद्य तथा कृषि उत्पादन के लिये सिंचाई और बिजली की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। इससे केवल हमारी आर्थिक व्यवस्था ही मजबूत नहीं होगी, अपितु हम औद्योगिक क्षेत्र में भी स्वतंत्र हो जायेंगे और हमें उर्वरक करार आदि जैसे अपमानजनक करार नहीं करने पड़ेंगे। राजनैतिक स्वतंत्रता के लिये आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र होना जरूरी है।

जहां तक निशस्त्रीकरण का सम्बन्ध है, निशस्त्रीकरण जिस विषय पर हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री काफी रुचि लेते रहे थे, सम्बन्धी सम्मेलनों तथा बैठकों के 17 वर्ष बाद हम यही समझ पाये हैं कि यह तो केवल एक खोखला नारा है, इसके साथ ही हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि परमाणु बम एक वास्तविकता है। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिये कि यदि एक या दो वर्ष में कोई वास्तविक अच्छा हल नहीं मिला तो क्या हम समय के अन्दर परमाणु शस्त्रों के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। सरकार को परमाणुबम की आवश्यकता तथा संभावना को ध्यान से परे नहीं करना चाहिये और उसके लिये सदैव तैयार रहना चाहिये।

अभी हाल ही में प्रधान मंत्री ने अमरीका और कुछ अन्य देशों का दौरा ठीक समय पर किया था। उनकी फ्रांस, लंदन और अमरीकी की यात्रा बहुत सफल रही।

[श्री हरिश्चन्द्र माथूर]

परन्तु उनकी यात्रा की सफलता की कसौटी क्या है। उन्होंने मुख्य रूप से यात्रा अमरीका की थी। परन्तु अमरीका का भारत और पाकिस्तान के प्रति रवैया क्या है? उनकी यात्रा से अमरीका भारत के कितना नजदीक आया है? अमरीकी सहायता को पुनः जारी करने के बारे में किये गये प्रयास का क्या परिणाम निकला है? वियतनाम के प्रश्न के बारे में अपने दृटिकोण को समझने के लिये हमें कितनी सफलता मिली है? यात्रा की सफलता इन चीजो से परखी जायेगी। दूसरी बात जिसके लिये मैं चिन्तित हूं वह यह है कि प्रधान मंत्री को महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में क्या सलाह दी जाती है। "न्यू दिल्ली रिपोर्ट" में यह बताया गया है कि सलाहकारों की सलाह से उन्हें कैसे अपनी विचारधारा बदलनी पड़ती है। यह बड़ी विचित्र बात है। मुझे पता नहीं यह कहां तक सही है। ऐसी बात लोगों के मन में नहीं रहनी चाहिये। परन्तु यह लोगों के मन में घर कर रही है। ऐसे विचारो को फैलने नहीं दिया जाना चाहिये।

हमें आपातकाल को हटाते समय अपनी सीमाओं की स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिये। हमें सीमाओं की स्थिति का मुकाबला करने के लिये भी प्रयास करने चाहिये।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
16	1	श्री यशपाल सिंह	चीन के अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्र को मुक्त न करा सकना।	100
16	2	,,	हमारे दूतावासों के कार्यचालन में सुधार लाने की आवश्यकता।	100
16	3	,,	बर्मा से लौटाये गये भारतीयों के मंजूर किये गये ऋण तथा अन्य सहायता कार्य।	100
16	4	,,	इजराइल तथा पूर्व जर्मनी को मान्यता देने का प्रश्न	100
16	5	,,	वैदेशिक प्रचार डिविजन के कार्यचालन में सुधार लाने की आवश्यकता।	100
16	6	,,	पारपत्र जारी करने में विलम्ब दूर करने की की आवश्यकता।	100
16	7	श्री शिवमूर्ति स्वामी	विदेशों में हमारे दूतावासों द्वारा धन का व्यर्थ व्यय रोकने की आवश्यकता।	100
16	8	,,	विदेशों में उच्च प्रतिभावाले सामाजिक और राजनैतिक नेताओं को राजनयविज्ञों के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
16	9	सरदार कपूर सिंह	ताइवान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
16	10	,,	दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये क्षेत्रीय सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था न करना ।	,,
16	11	,,	इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित न करना ।	,,
16	12	श्री उ० मू० त्रिवेदी	ताइवान और इज़राइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित न करना और संयुक्त अरब गणराज्य में अनावश्यक व्यय करना ।	1,000,000
16	13	श्री ही०ना०मुकर्जी	भारत द्वारा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को पूरी राजनयिक मान्यता दिये जाने की वांछनीयता ।	100
16	14	,,	रोडशिया के जातिवादियों द्वारा जनता की स्वतंत्रता को खतरे में डालने और ब्रिटन द्वारा उन्हें ठीक मार्ग पर लाने का मामला ।	100
16	15	,,	हिन्द महासागर क्षेत्र में पश्चिम जर्मनी की सांठगांठ से पूर्वयोजित ब्रिटिश-अमरीकी सैनिक अड्डा ।	100
16	16	,,	एक ब्रिटिश अमरीकी संस्थान के बारे में अत्याधिक हानिकारक करार का सम्भव परिणाम ।	100
16	17	,,	प्रधान-मंत्री की हाल की अमरीका यात्रा और उन के द्वारा वहां दिये गये भाषणों की प्रतिक्रिया ।	100
16	18	,,	विदेशों में हमारे दूतावासों और विदेश-कार्यालय के कार्यचालन के तरीकों में सुधार लाने में काफी विलम्ब ।	100
16	19	,,	ताशकंद घोषणा की समुचित कार्यान्विति कराने में भारत द्वारा पहल किये जाने की वांछनीयता ।	100
16	20	,,	काश्मीर प्रश्न पर गत्यवरोध भंग करने की वांछनीयता ।	100
16	21	,,	नव-उपनिवेशवादी योजनाओं को असफल बनाने के लिये सामान्यतः अफ्रीकी-एशियाई देशों और विशषतः भारत के पडौसी देशों के साथ अधिक निकट सम्पर्क ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
16	22	श्री ही०ना० मुकर्जी	चीन के साथ सम्मानजनक फैसले के उद्देश्य के अनुसरण में ठोस कार्यवाही की वांछनीयता।	100
16	23	,,	वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप के बारे में सरकार का द्वयूर्थक तथा यदा कदा कायरतापूर्ण रुख।	100
16	24	,,	वियतनाम में शान्ति की स्थापना के लिये भारत का अपर्याप्त अंशदान।	100

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आशंका है कि सरकार की विदेश नीति देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है।

जब विदेश नीति के बारे में यहां चर्चा हो रही है तो यदि प्रधान मंत्री यहां उपस्थित होती तो बहोत अच्छा होता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री कपूर सिंह चाहे इस बात से सहमत न हों परन्तु हमारी विदेशी नीति की परम्परा शान्ति गुटों से बाहर रहने और उपनिवेशवाद का विरोध करने की ही रही है। परन्तु इस परम्परा को अब लगभग छोड़ दिया गया है।

यह बात रिकार्ड में है कि प्रधान मंत्री ने अमरीका के राष्ट्रपति की "वियतनाम में शान्ति रखने की इच्छा" की सराहना की है।

ऐसी सराहना करना दोष को कम करके दिखाना है परन्तु फिर भी इस से आवश्यक परिणाम नहीं निकल सकते हैं जैसे श्री माथुर ने अभी कहा है।

अमरीका के लगभग सभी समाचारपत्रों ने यह प्रकाशित किया है कि हमारे प्रधान मंत्री ने पुनः विश्वास दिलाया है कि वह वियतनाम में अमरीकी कार्यवाही के प्रति अपनी सरकार की आलोचना को दबायेंगे। यही कारण है कि उनके मंत्रालय के प्रतिवेदन में दक्षिण वियतनाम से अमरीकी सेनाओं को हटाने के बारे में मामूली सा उल्लेख हो जाने से ही अमरीका में इतनी अधिक खलबली मच गई है। अमरीका के समाचार पत्रों ने अपनी मोटी मोटी खबरों में छापा है कि भारतीय प्रवक्ता कैसे टालमटोल कर रहे हैं।

13 अप्रैल के "बाल्टीमोर सन" में प्रकाशित सम्पादकीय से पता चलता है कि हमारे विदेशी मंत्री श्री स्वर्ण सिंह ने भारत स्थित अमरीकी कार्य दूत को बताया था कि विवरण में प्रशासनिक गलती हो गई थी परन्तु इस अमरीकी समाचारपत्र में यह प्रकाशित किया गया है कि श्री सिंह ने भारतीय संवाददाताओं को कहा है कि यह जो टिप्पणी की गई थी वह वियतनाम में युद्ध हटाने की भारत की पुरानी नीति के अनुरूप थी।

हमारे समाचारपत्रों ने यह प्रकाशित किया है कि विदेश सचिव ने विरोध करने वाले अमरीकियो को यह कहा है कि यह एक कनिष्ठ अधिकारी की गलती थी और उसको ताड़ना दी गई है। यदि यह समाचार ठीक नहीं है तो मंत्री महोदय को इसका विरोध करना चाहिये और हमें बताना चाहिये कि सच्चाई क्या है। इस से मालूम होता है कि चूंकि हमें सहायता की आवश्यकता है इसलिये हम अपने आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता का त्याग करने के लिये भी तयार है जिसे हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये लड़ते समय सीखा था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वियतनाम में अमरीकी नीति का यदि खुले तौर पर समर्थन नहीं किया है तो उन्होंने उस के विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा है।

लंदन की "न्यू स्टेट्समैन" ने 15 अप्रैल को अपने विशेष सम्पादकीय में प्रकाशित किया था कि अमरीका इस वर्ष वियतनाम में सैनिक तथा आर्थिक कार्यों पर 25,000 मिलियन डालर खर्च करने वाला है। इसका तात्पर्य यह है कि अमरीका इस वर्ष दक्षिण वियतनाम में 12,500 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

नय उपनिवेशवाद को बनाये रखने और उसे स्थायी करने के लिये वियतनाम में अभद्र बबरता बरती जा रही है। यह शर्म की बात है कि इस सभा में इस प्रकार की बर्बरता का कभी कभी समर्थन भी किया जाता है। अमरीकी नेपाम बम का प्रयोग करने लग गये है।

अन्तःसंसदीय संघ की हाल में कैन्बैरा में हुई बैठक में रूसी प्रतिनिधियो ने विश्व की सभी संसदों से प्रार्थना की थी कि वे वियतनाम को सहायता करें। हमें भी इस बारे में कुछ करना चाहिये। मेरा विचार है कि वियतनाम ने भी हमें इस बारे में लिखा है। मेंह यह कहना चाहिये कि जनेवा समझौता लागू किया जाये। उसका कडाई से पालन किया जाना चाहिये। अमरीकी आक्रमण बन्द होना चाहिये। विदेशी सेना वहां से निकल जानी चाहिये। यह भारत की विदेश नीति के लिये आवश्यक है।

प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क में व्यापारी नेताओ को भाषण देते हुए कहा था कि हम विदेशी विनियोजकों के साथ भारतीय विनियोजको जैसा व्यवहार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार निश्चय ही कई वर्तमान नियंत्रण हटाने के लिये तैयार है। हम उर्वरक के मामले में ऐसा देख चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने अमरीका में यह कहा कि जब शरद ऋतु आ जाती है तो मौसम में बहार कैसे पीछे रह सकता। जब उर्वरक के मामले में सौदा समझौता हो गया है तो तेल व अन्य वस्तुएं के बारे में भी अवश्य हो जायेगा।

मुझे पता नहीं है कि प्रधान मंत्री स्वयं ऐसा भाषण देती हैं अथवा सचिवालय आदि में कोई गुप्त लेखक उसे तैयार करते हैं। उन्हें किसी समय अपने पिता की कृतियों को पुनः पढ़ना चाहिये। उन्हें इस बात से सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये कि पश्चिम में वह बहुत प्रसिद्ध है। यदि वह ऐसी प्रसन्नता चाहती हैं तो वह इसका स्वागत कर सकती हैं, देश नहीं।

ऐसी बातों के कारण भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान का जिक्र आ रहा है। यह प्रतिष्ठान बुद्धीजीवी लोगों के विचारों को ढालने का प्रत्यक्ष हथियार है। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने हमें बताया था कि उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस बारे में परामर्श किया था। चाहे उनका इस सरकारी एजेंसी ने समर्थन किया परन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय के 54 विद्यार्थियों ने शिक्षा नीति के मामले में सरकार की विदेश नीति को धिक्कारा है। यह सब कुछ इस लिये हो रहा है क्योंकि हमारी विदेश नीती बिल्कुल निर्जीव हो गई है।

जर्मन संघीय गणराज्य के डर से हम जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को मान्यता नहीं दे रहे हैं। जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिये प्रार्थना की है। रूस तथा बहुत से अन्य देशों ने उसका समर्थन किया है। हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। मंत्री महोदय ने कहा है कि हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। हम डर के

[श्री हीं० ना० मुकर्जी]

कारण नहीं कह रहे हैं कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाना चाहिये क्यों पश्चिमी जर्मनी अर्थात् जर्मन संघीय गणराज्य यह धमकी देता है कि जो की देश जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करेगा हम उसके साथ सम्बन्ध विच्छेद कर देंगे। यह फजूल की धमकी है और कभी लागू नही हो सकती। सोवियत संघ के दुतावास पूर्वी बर्लन और पश्चिमी जर्मनी में भी हैं। युगोस्लाविया, श्रीलंका, ईराक, बर्मा आदि बहुत से देशों के सम्बन्ध दोनों देशों के साथ हैं। दूसरे जर्मनी संघीय गणराज्य ने पाकिस्तान के सम्बन्ध में भारत विरोधी रूख अपनाया था। हमें संघीय गणराज्य के साथ साथ जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को भी मान्यता प्रदान करनी चाहिये। वह विश्व में आठवां सब से बड़ा औद्योगिक देश है। इस देश से हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। चीन और पाकिस्तान के मामले में उसने हमारी सहायता की थी। भारी रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों तथा कृषि सम्बन्धी मशीनों का उस देश के साथ हमारा व्यापार बढ़ा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी वह देश हमारी सहायता कर सकता है। परन्तु हम समय समय पर उसकी निन्दा करते रहे हैं। भूतपूर्व राज्य मंत्री श्रीमती मेनन पश्चिम बर्लन में गईं और हर किस्म के वक्तव्य दिये। श्रीमती पंडित भी सब देश छोड़ कर राष्ट्रपति लुबके को मिलने गईं। फरवरी 1965 में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की सरकार के प्रधान को राष्ट्रपति नासर द्वारा दिये गये स्वागत समारोह में हमारे वहां के राजदूत ने भाग नही लिया। ये सभी बातें तभी हो रहीं हैं क्योंकि हम पश्चिमी जर्मनी से डरते हैं। हम उन से सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

1961 में श्री जवाहरलाल ने कहा था कि हमें पूर्वी जर्मनी को मान्यता प्रदान करनी चाहिये। अब तो उस बात को कहे बहुत समय गुजर चुका है। अब हमें कम से कम दो बातें करनी चाहिये। एक तो जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की राजधानी पूर्व बर्लिन में एक व्यापार प्रतिनिधि रखना चाहिये और दूसरे उस देश के पारपत्रों के मान्यता दी जानी चाहिये।

जहां तक एशिया अफ्रीका के मामलों का सम्बन्ध है वहां ऐसी चीजों की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये जैसे युवराज सिहमनूक ने हाल में प्रार्थना की थी कि एशिया के नेताओं का सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये। उन्होंने यह बता दिया था कि वह भारत के साथ कितनी मित्रता रखते हैं। हमें उनसे अवश्य मिलना चाहिये। वह हमारे बहुत मित्र है। इस दृष्टि से मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें चीन के साथ गतिरोध को तोड़ने की सम्भावना पर विचार करना चाहिये। हमारे राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने भी यही सुझाव दिया था कि हमें अपने पड़ौसी देशों से सम्बन्ध सुधारने चाहिये। चीन और पाकिस्तान की तो हमारे पड़ौसी देश हैं। उनके उपेक्षापूर्ण रवैये के बावजूद भी हमें सम्माननीय समझौते की तलाश में रहना चाहिये। हमें संयुक्त अरब गणराज्य, रुमानिया अथवा तनजानिया जैसे देशों द्वारा, जिनमें दोनों देशों का विश्वास हैं, मध्यस्थी किये जाने की बात पर विचार करना चाहिये। हमें याद होना चाहिये कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरु, ने विश्व न्यायालय द्वारा मध्यस्थता किये जाने की भी पेशकश की थी।

अब मैं ताशकन्द समझौते और भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आजकल स्थिति यह है कि पाकिस्तान-चीन और अमरीका-दोनों का मित्र बना हुआ है। जबतक हम काश्मीर के बारे में बातचीत न करने का निश्चय किये हुए है तब तक ऐसी स्थिति ही रहेगी। क्या हम यह कह सकते हैं कि ताशकन्द समझौते के अनुसार शान्तिपूर्ण ढंग से काश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता है। इस सूरत में क्या हम पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा परिषद को बीच लाने तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाली सभी खतरनाक संभावनाओं को रोक सकते है? आजकल ठीक यही हो रहा है। अमरीका सुरक्षा परिषद को इस मामले पर पुनः विचार करने के लिये कह रहा है। इसलिय मैं सुझाव दूंगा कि हमें ताशकन्द समझौते में उल्लिखित शान्तिपूर्ण तथा द्विपक्षीय उपायों द्वारा काश्मीर प्रश्न को हल करने की सम्भावना की बात पर विचार करने के लिये तैयार रहना चाहिये। मेरा यह विचार है कि यदि काश्मीर मसला स्वीकृत सूत्र के आधार पर हल हो जाये तो अन्य मसले भी हल हो सकते हैं।

पाकिस्तान यह आरोप लगा रहा है कि भारत बहुत से लोगों को गलत तरीके से पाकिस्तान भेज रहा है। ताशकन्द समझौते के बाद हमें कुछ करना चाहिये था परन्तु हमने एसा नहीं किया है। यदि पाकिस्तान अच्छा व्यवहार न भी करे तो भी हमें उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिये।

मैं सभा को याद कराना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरु ने 1956 में काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा के बारे में पेशकेश की थी। इस मसले को हल करने के लिये ऐसे सुझाव दिये जा सकते हैं। हम काश्मीर के मसले को कैसे हल कर सकते हैं यदि मान लीजिये कि पाकिस्तान कहता है कि हमारा भारत के साथ यही मुख्य झगड़ा है। इसलिये यदि हमारा सम्मानपूर्वक समझौता हो जाता है तो हम उसके लिये तैयार हैं। पाकिस्तान की उत्तेजनात्मक कार्यवाही के बावजूद भी हमें इस सम्बन्ध में सूत्रपात करना चाहिये। हमें श्री लाल बहादूर जी के शब्द याद रखने चाहिये कि दोनों देशों के बीच शान्ति कायम करने के लिये हम उतने ही उत्साह से काम लेंगे जितना हमने लड़ाई के समय लिया था।

हमें पाकिस्तानी व चीन के साथ झगड़े को समाप्त करना चाहिये। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिये। यदि हम उसमें असफल भी रहते है तो हम विश्व को बता सकते हैं कि हमने कितने प्रयास किये हैं।

यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः।

यदि हम ताशकन्द समझौते को अच्छी तरह से लागू करना चाहते हैं तो हमें उसके लिये सूत्रपात करना चाहिये। चीन और पाकिस्तान बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं परन्तु वे सीमा पर गड़बड करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें खतरा तो अमरीका से हो सकता है जो दक्षिण वियतनाम में एक वर्ष में 12,500 करोड़ रुपये खर्च कर सकता है तथा जिसके 500 विभिन्न स्थानों पर अड्डे हैं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रालय के प्रतिवेदन में वर्ष की लगभग सभी घटनाओं का वर्णन किया हुआ है। मेरा विचार से इस वर्ष की सब से महत्वपूर्ण घटना ताशकन्द समझौता है। पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया। हम युद्ध नहीं चाहते थे परन्तु आत्म-रक्षा के लिये हमें लड़ना पड़ा। हमने पाकिस्तान व उसके साथी चीन और अमरीका को दिखा दिया है कि चाहे हम शान्ति के लये लड़ते हैं परन्तु इस प्रकार से अपनी प्रभूसत्ता नहीं खो सकते हैं। अतः चाहे हमें सैनिक विजय प्राप्त हुई परन्तु जब समय आया कि कोई समझौता होना चाहिये तो हम ने तुरन्त ताशकन्द समझौते को स्वीकार कर लिया। हमने विजय प्राप्ति के बावजूद भी इस लिये ताशकन्द समझौते को स्वीकार किया क्योंकि हम चाहते थे कि पड़ौसी देशों के साथ नही बल्कि संसार में शान्ति से रहा जाये।

जब समझौते के लिये प्रयास किया जा रहा था तो हमारे प्रधान मंत्री ने यह घोषणा कर दी थी कि हम बातचीत नहीं करेंगे जबतक पाकिस्तान यह घोषणा नहीं कर देता है कि वह सेना का प्रयोग नहीं करेगा। दुसरी ओर पाकिस्तान ने यह शर्त रखी थी कि वह तब तक युद्ध बन्द नहीं करेगा जबतक काश्मीर की समस्या हल करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। पाकिस्तान ने युध्द न करने के लिये घोषणा करने की हमारी शर्त मंजूर कर ली और तब हमने ताशकन्द समझौता स्वीकार किया।

हमने ताशकन्द समझौते का पूरी तरह पालन किया है। दूसरी ओर पास्किातान इसका कतई पालन नहीं कर रहा है। जब श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा कि काश्मीर का विभाजन होना चाहिये तो उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।

महोदय, वामपंथी साम्यवादियों के लिये सब से अच्छी जगह जेल ही है। हम ताशकंद समझौते का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं परन्तु पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम तो पाकिस्तान के साथ मित्रता बनाना चाहते हैं परन्तु पाकिस्तान हमसे मित्रता करना

[श्री भागवत झा आझाद]

नहीं चाहता। इसलिये हमें सतर्क रहना है। अमरीका तथा इंगलैंड यह तो कहते हैं कि वे संसार में शान्ति चाहते हैं परन्तु उनके कृत्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे वास्तव में शान्ति नहीं चाहते। पाकिस्तान की ओर उनके रवैये से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है।

मेरा विचार है कि काश्मीर के बारे में रूस के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उनका यही विचार है कि इस मामले को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिये। हम भी यही चाहते हैं। ताशकंद समझौता करके हमने इस बात का पर्याप्त प्रमाण दिया है कि हम शान्ति चाहते हैं। परन्तु हमारे दूसरे दो मित्र--अमरीका तथा इंगलैण्ड लगातार भारत को नीचा दिखाने का यत्न कर रहे हैं।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 31 तथा 32 में यह बिल्कुल ठीक कहा गया है कि वियतनाम का कोई सैनिक हल नहीं निकल सकता। यदि वास्तव में अमरीका वियतनाम में शान्ति चाहता है तो उसको उत्तरी वियतनाम पर बम वर्षा बन्द कर देनी चाहिये और जनेवा की तरह का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये। यदि संसार के इस भाग में अमरीका साम्यवाद के विस्तार को रोकना चाहता है तो उसको वियतनाम से अपनी सेना हटा लेनी चाहिये तथा शान्तिपूर्ण ढंग से वियतनाम को एक कर दिया जाना चाहिये। वियतनाम के बारे में प्रतिवेदन के पृष्ठ 31 तथा 32 में बताई गई नीति का मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। अमरीका की यात्रा के समय श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में अमरीका के समाचार-पत्रों में जो कुछ भी कहा गया हो हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये। वियतनाम के बारे में हमें अपनी नीति पर दृढ़ रहना चाहिये।

श्री जवाहरलाल नेहरु ने भारत को गुटो से अलग रहने का मार्ग बताया है और हमे इस मार्गपर चलते रहना चाहिये। वैदेशिक कार्य मंत्रालय में अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं जो पश्चिम समर्थक हैं। मंत्रालय से ऐसे व्यक्तियों को हटाना चाहिये।

हमारे प्रधान मंत्री का अमरीका में बहुत अच्छा स्वागत हुआ था। उन्होंने पर्याप्त सहानुभूति भी दिखाई थी परन्तु पाकिस्तान जो कि चीन के साथ साठ-गांठ कर रहा है, के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है।

विदेश संपर्क समिति के सम्मुख साक्ष्य देते समय मि० मैकन्मारा ने जानबूझकर पाकिस्तान की सहायता करने की कोशिश की है। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि भारत के साथ झगड़े के कारण ही पाकिस्तान तथा चीन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि अमरीका वास्तव में चीन के विस्तारवाद को रोकना तथा एशिया में लोकतन्त्री को बनाये रखना चाहता है तो उसको भारत की सहायता करनी चाहिये। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो संसार के इस भाग में साम्यवाद को बढ़ने से रोक सकता है।

यदि अमरीका और इंगलैण्ड पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर सैनिक सहायता नहीं देते तो वह भारत पर कभी आक्रमण नहीं कर सकता था। पहले पाकिस्तान को सैनिक सहायता चीन के विरुद्ध दी जाती थी। परन्तु आज चीन पाकिस्तान का सबसे अच्छा मित्र है इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि अब यह सहायता पाकिस्तान को किसके विरुद्ध दी जाती है।

भारत के राष्ट्रमण्डल से बाहर आ जाने के बारे में मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि हमें विश्व में इतना बड़ा धोखा किसी ने नहीं दिया जितना कि ब्रिटेन ने दिया है।

मेरा विचार है कि ब्रिटेन ने अभी तक हमें फालतू पूर्जे नहीं दिये हैं। श्री स्वर्ण सिंह को ब्रिटेन को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि हम उनके साथ अन्य देशों की तरह सामान्य सम्बन्ध ही रखना चाहते हैं न कि विशेष सम्बन्ध। हमें या तो ब्रिटेन के बिना राष्ट्रमण्डल बनाना चाहिये अथवा स्वयं राष्ट्रमण्डल छोड़ देना चाहिये।

हमें फ्रांस के साथ अपने सम्बन्ध बढ़ाने चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, विकास के लिये आर्थिक सहायता लेना भी अच्छी बात है परन्तु जिस प्रकार अमरीका ने भारत अमरीका संस्थान के रुप में सहयोग दिया है वह अच्छा नहीं है। हाल ही में जो उर्वरक करार किया गया है तथा अमरीका जो विश्व बैंक की मार्फत सहायता देने पर जोर दे रहा है वह भी अच्छी बात नहीं है।

हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतन्त्र फले फूले तथा हमारा देश समृद्ध हो। हमें इस सबके लिये अमरीका के सहयोग तथा सहायता की आवश्यकता है परन्तु अमरीका को यह नहीं भूलना चाहिये कि जिस प्रकार से उसने अपनी सहायता का प्रदर्शन किया है उससे कई देशों को हानि हुई है। इसलिये अमरीका को हमें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में नीति बदलने के लिये नहीं कहना चाहिये।

मैं श्री स्वर्ण सिंह से निवेदन करूंगा कि यदि इस सहायता के साथ किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव पड़े तो हमें ऐसी सहायता नहीं लेनी चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं महसूस करता हूं कि हमारी वैदेशिक नीति राष्ट्र हितों पर आधारित न हो कर शंकाओं तथा पक्षपात पर आधारित है। यदि हम चाहते हैं कि विश्व में राष्ट्र के रुप में हमारा सम्मान हो तो हमें किसी राष्ट्र से डरना नहीं चाहिये। हमारा देश विश्व में सब से बड़ा लोकतन्त्रात्मक देश है। इसलिये हमें दूसरे देशों को अपने आन्तरीय मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

हमें अपनी वैदेशिक नीति अपने राष्ट्र हितों के अनुसार बनानी चाहिये चाहे संयुक्त अरब गणराज्य या अमरीका अथवा अन्य कोई देश इससे नाराज ही क्यों न हो। इस बात की हमें बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिये।

पाकिस्तान ने पहले अमरीका अथवा ब्रिटेन से हथियार लिये और अब वह चीन से हथियार ले रहा है तथा सांठ-गांठ कर रहा है। यह सच है कि हम युद्ध, नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि विश्व में युद्ध नहीं हो परन्तु हमें किसी देश से डरना नही है। हमें पाकिस्तान को बता देना चाहिये कि हम लड़ने से नहीं डरते और यदि उसने हमारे देश पर पुन: आक्रमण किया तो इसका पूरी शक्ति से मुकाबला करेंगे। हमने ताश्कन्द समझौता किया है परन्तु इसका यह अर्थ नही लिआ जाना चाहिये कि हम युध्द से डरते है हमारे सनिकों ने सिद्ध कर दिया है कि हम युद्ध कला से अच्छी तरह परिचित हैं। हमें शत्रुओं का मुकाबला करने के लिये अपनी तयारियां जारी रखनी चाहिये।

राज्य सभा में भी चर्चा के समय कुछ सदस्यों ने कहा है कि जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य को मान्यता दी जानी चाहिये। परन्तु हमें देखना है जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य क्या कर रहा है। वहां स्कूलों में जो भूगोल की पुस्तकें तथा एटलसें पढ़ाई जाती हैं उनमें काश्मीर को पाकिस्तान का तथा नेफा और लद्दाख को चीन का भाग दिखाया गया है। जो लोग जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य को मान्यता देने के लिये कह रहें हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिये।

यह बड़े शर्म की बात है कि जब जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य से प्रतिनिधि आये तो हमने उनको मुफ्त सुविधायें प्रदान की परन्तु इसरायल के प्रधान से सुविधायें देने के लिये 400 रुपये ले लिये गये थे। हालांकि हमने दोनों देशों को मान्यता नहीं दी है। दोनों के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध हैं।

यह सच है कि ताइवान एक छोटा सा देश है परन्तु उसके पास आधुनिक हथियारों से पूरी तरह लैस 6 लाख की सेना है। जब साम्यवादी चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया है तो हमें ताइवान से लाभ उठा कर साम्यवादी चीन के लिये कठिन स्थिति उत्पन्न करनी चाहिये। चीन ने लाखों लोगों की हत्या की है परन्तु हम ऐसा नहीं चाहते। यदि हम ऐसा करना चाहते तो 3 लाख नागा हमें प्रतिदिन परेशान नहीं कर सकते थे और न ही कभी मिजो की समस्या ही उत्पन्न हो सकती थी। हमें लोकतन्त्रात्मक देशों से मित्रता बनानी चाहिये। मलेयशिया तथा इसरायल भी ऐसे ही देश हैं। समझ में नहीं आता कि हम इसरायल को मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं। इसरायल ने कृषि,रसायन तथा दूसरे क्षेत्रों में बहुत उन्नति की है। हमें उनसे बहुत सी बातें सीख सकते हैं।

[श्री उ० मु० त्रिवेदी]

श्री भागवत झा आजाद ने ठीक ही कहा है कि हमारे वैदेशिक कार्य विभाग में एक विशेष दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति वहां पर कार्य कर रहे जिनको हमारे देश के इतिहास के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मंत्रालय से हटाया जाये।

विदेशों में स्थित अपने राजदूतावासों में नियुक्ति करते समय हमें केवल इसी बात को ध्यान में रखना चाहिये कि हम सब भारतीय हैं। यदि कोई मुस्लिम देश किसी हिन्दू अथवा अन्य जाति के व्यक्ति को राजदूत के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो हमें उसके साथ अपने सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिये। इस बात का निर्णय हमने करना है कि किस देश में कौन सा व्यक्ति भेजा जाये।

अभी कल ही मैंने कहा था कि नागालैंड को वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन रखा जाना आवश्यक नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय मुझ से सहमत हैं।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : यह एक सराहनीय बात है कि गत 18 वर्षों से हम एक ही नीति का अनुसरण कर रहे हैं। किसी देश की प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि हमने कुछ देशों को मान्यता नहीं दी है तो इसका कारण यह नहीं है कि हमने ऐसा किसी विशेष विचाराधारा अथवा भय के कारण किया है। अपितु कुछ अन्य बातों को ध्यान में रख कर इस बारे में नीति निर्धारित की गई है।

जहां तक इसरायल को मान्यता देने का सम्बन्ध है हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि यदि हम इसको मान्यता देते हैं तो सारे अरब देश बुरा मानेंगे। धर्म के आधार पर राज्य बनाने का अर्थ है देशों में स्थायीरुप से विभाजन करना। पाकिस्तान के बनने से हमें बहुत हानि हुई है। हमें कम से कम उन झगड़ों के सम्बन्ध में अरब देशों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिये जो कि इसरायल वहां पर उत्पन्न कर रहा है।

जहां तक फार्मोसा को मान्यता देने का सम्बन्ध है, यह सच है कि आजकल साम्यवादी चीन के साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़े हुए हैं परन्तु वर्तमान सम्बन्ध सदा ऐसे नहीं रह सकते, इसलिये फार्मोसा को मान्यता दे कर हमें मुख्य भूमि चीन के 70 करोड़ व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध नहीं बिगड़ने चाहिये। इस तथ्य के बावजूद कि फार्मोसा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है उसका विश्व में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है।

राष्ट्रपति अय्यूब का ताशकंद घोषणा के प्रति वर्तमान रवैया शायद आन्तरिक समस्याओं के कारण है। हमें ताशकंद घोषणा को कार्यान्वित कराने के लिये दबाव डालते रहने के साथ साथ ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे उसके लिये इस घोषणा को कार्यान्वित करना कठिन हो जाये। यद्यपि हम यह जानते हैं कि पाकिस्तान शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में लगा हुआ है तथापि हमें ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिये। हमें इस बात को याद रखना है कि भारत तथा पाकिस्तान के लोग एक थे और उनको एक दिन फिर एक होना है। इसके बावजूद जो बातें हमारे विरूद्ध हों हमें उसके लिये पाकिस्तान को विरोध प्रकट करते रहना चाहिये। परन्तु जब कि हमें खतरा है हमें अपनी सैनिक कमाण्ड में परिवर्तन नहीं करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जनरल चौधरी तथा वायुसेना के मुख्य मार्शल अर्जन सिंह की सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी जाये क्योंकि उनको युद्ध का अनुभव है।

दूसरे देशों के साथ हुए समझौते में पाकिस्तान सदा उन खण्डों को कार्यान्वित करने पर जोर देता है जो उसके हित में हों। पाकिस्तान ने जिस ढंग से इस समझौते को स्वीकार किया है हमें उसके बारे में समचे विश्व को बता देना चाहिय।

अमरीका वियतनाम में शान्ति स्थापित करने के लिये उत्सुक है। वह जिस जाल में फंस गया है उससे निकलना चाहता है। यही कारण है कि वह शान्ति सम्बन्धी शर्तों का पुनरीक्षण कर रहा है।

सहायता के मामले में हमारे उपर जो दबाव डाला जा रहा है हमें उसके आगे झुकना नहीं चाहिये। यदि आवश्यकता पड़े तो हमें सहायता के बिना भी गुजारा करने के लिये तैयार रहना चाहिये। इसका परिणाम यह निकला है कि दक्षिणी वियतनाम का दो तिहाई भाग वियतकांग के हाथ में है। आज स्थिति यह है कि वहां के लोग शान्ति चाहते हैं और इस उद्देश्य से वे वियतकांग से बातचीत करना चाहते हैं। एक ओर तो अमरीकी कहते है कि वे साम्यवाद का विरोध करते हैं और वे उत्तरी वियतनाम पर गोलाबारी इसलिये करते हैं क्योंकि उत्तरी वियतनाम वाले दक्षिणी वियतनाम को हथियार दे रहे हैं। वे यह भी कहते हैं कि उत्तरी वियतनाम द्वारा ये हथियार चीन दे रहा है परन्तु वे वहां पर गोलाबारी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे यह नहीं चाहते कि युद्ध का क्षेत्र और बढ़ जाये। यह सब कुछ हो रहा है परन्तु वे यह महसूस नहीं करते हैं कि वे राष्ट्रवाद के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं न कि साम्यवाद के विरूद्ध। आज अदन में भी यही स्थिति है वहां के लोग ब्रिटेन सेनाओं से जो मार खाने आ रहे हैं तो क्या यह राष्ट्रवाद नहीं है। वहां भी क्या कोई चीन का हाथ है? फिर भी वहां पर लोगों की बल प्रयोग द्वारा दबाया जा रहा है। परन्तु दूसरी ओर ब्रिटेन रोडेशिया में बल प्रयोग करने के लिये तैयार नहीं है। इस देश को स्वाधीनता प्राप्त हुए 18 वर्ष हो गये हैं। साम्यवाद के विरूद्ध युद्ध तो वास्तव में यहां हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वाधीन होना कितना अच्छा है।

विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के बारे में मेरे कुछ मित्रों ने इसे आत्मसम्मान के विरुद्ध बताया है। मेरे विचार में हमें एक न एक दिन बाहर से सहायता न लेने का पक्का इरादा करना होगा। अब कुछ लोग रूपये के अवमूल्यन तथा कुछ लोग नियन्त्रण लागू करने के बारे में कहते हैं और कुछ अन्य लोग सहायता प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान से शान्ति स्थापित करने की बात कहते हैं। वास्तविकता यह है कि हम पर दबाव डाला जा रहा है और यदि हम इस दबाव में आ गये तो यह हमारे लिये एक बहुत बुरी चीज़ होगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ वर्ष पूर्व सरकार द्वारा गुटों में अलग रहने की जो विदेशी नीति अपनाई जाती थी वह साम्राज्यवाद के विरूद्ध थी परन्तु अब सरकार वास्तव में अमरीका के गुट के अधिक निकट हो जाने की नीति का अनुकरण कर रही है। वियतनाम के बारे में सरकार द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा है वह ही सरकारी नीति की कसौटी है।

देखना यह है कि वियतनाम में हो रहे युद्ध में आक्रमक कौन हैं और आक्रान्त कौन है। यह सुज्ञात है कि अमरीकी साम्राज्यवादियों ने वहां पर युद्ध छेड़ रखा है। वियतनाम के लोगों की स्वाधीनता प्राप्त करने की लहर को दबाने के लिये पहले ये फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों की सहायता करते रहे। इस के बावजूद भी जब फ्रांस को हार माननी पड़ी तो इस के फलस्वरूप 1954 में जेनेवा करार हुआ। परन्तु अमरीकियों ने इस समझौते को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। उक्त समझौते के अनुसार वियतनाम को दो प्रशासनिक भागों—दक्षिण तथा उत्तर वियतनाम—में बांटा गया था और यह उपबन्ध किया गया था कि 1966 तक होने वाले चुनावों के आधार पर इन दो भागों को मिला दिया जायेगा। परन्तु दक्षिणी वियतनाम में एक कठपुतली प्रेसीडेन्ट नियुक्त कर के अमरीकी साम्राज्यवादियों ने उसके द्वारा जेनेवा समझौते को तोड़ दिया। यदि अब वियतनाम के लोग इस प्रकार लादे गये एक कठपुतली प्रेज़ीडेंट के विरूद्ध युद्ध करते हैं तो कहा जाता है कि साम्यवादियों ने आक्रमण कर दिया है। समझ में नहीं आता कि दक्षिणी वियतनाम में जिस लोक-तन्त्र को बचाने के लिये अमरीकी सरकार ने युद्ध छेड़ रखा है, वह है कहां? वहां के लोगों पर नृशंस गोलाबारी करके वे बर्बरता में फासिस्टों से भी आगे बढ़ गये हैं। वियतनाम के लोगों का यह संघर्ष संसार भर में स्वाधीनता संग्रामो के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। वहां के लोगों ने अपनी वीरता तथा साहस से अमरीकी साम्राज्यवादियों को अपनी शर्तों पर शान्ति की बातें करने के लिये बाध्य कर दिया है। यदि अमरीकी साम्राज्यवादी वियतनाम को छोड़ दें तो वहां पर शान्ति स्थापित हो सकती है।

वियतनाम के लोगों का समर्थन करने की बजाय भारत सरकार अमरीकी सरकार को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही है। यह बात मंत्रालय के प्रतिवेदन में वियतनाम के बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा अमरीका के भारसाधक दूत को दिये गये स्पष्टीकरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। प्रतिवेदन

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

में यह बताया गया है कि भारत सरकार चाहती है कि दक्षिणी वियतनाम में युद्ध बन्द होना चाहिये और अमरीका को वहां से अपनी सेनायें हटा लेनी चाहिये तथा सम्बद्ध पक्षों को जेनेवा समझौते का पूरी तरह पालन करना चाहिये। इस संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए हमारे विदेश मंत्री, श्री स्वर्ण सिंह ने अमरीका के भारसाधक दूत को यह बताया कि प्रतिवेदन में यह विवरण दुर्भाग्यपूर्ण है और इस से वियतनाम के बारे में हमारी सरकारी स्थिति प्रतिबिम्बित नहीं होती है। यह अमरीकी साम्राज्यवादियों के सामने घुटने टेकने और वियतनाम के लोगों के साथ विश्वासघात करने के अतिरिक्त और क्या है?

जहां तक पड़ौसियों के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है, मुझे यह कहना है कि हमारे लोगों के कई वर्ग अब यह महसूस करने लगे हैं कि चीन से निरंतर शत्रुता बनाये रखने के फलस्वरूप हमारे देश के हितों को हानि हो रही है। बढ़ते हुए रक्षा सम्बन्धी आयव्ययक से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। परन्तु चीन के साथ इस विवाद को सुलझाने तथा शीतयुद्ध का अन्त करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस के बावजूद भी कि पाकिस्तान ने हमारे काश्मीर के एक बड़े भाग पर कब्जा कर रखा है और जब वह हमारे साथ वास्तव में युद्ध में जूझा हुआ था, हमने उससे बातचीत करना स्वीकार कर ताशकन्द समझौता किया परन्तु चीन के साथ युद्ध समाप्त होने के तीन वर्ष पश्चात भी हम उससे बातचीत करने के लिये तैयार नहीं है। वर्तमान गतिरोध को समाप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि बातचीत की जाये। अब कहा जाता है कि चीन के साथ बातचीत करने का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उसका रवैया अमैत्रीपूर्ण तथा आक्रामक है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान से बातचीत की गई थी, क्या उसका रवैया मैत्रीपूर्ण था? हमारे देश के विख्यात समाचारपत्रों में यह छपता रहा है और हमारे देश के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति बार बार यह कहते रहे हैं कि चीनी विरोधी रवैया हम अमरीका से सहायता लेने के कारण अपना रहे हैं। यही नहीं श्री मु० क० चागला ने सुरक्षा परिषद में काश्मीर पर वादविवाद में काश्मीर पर इस आधार पर अमरीकी समर्थन प्राप्त करना चाहा कि एशिया में हमारा ही एक बहुत बड़ा देश है जो चीन का विरोधी है। इन सभी बातों से यह स्पष्ट है कि हम चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आर्थिक सहायता के लिये हम अमरीका पर निर्भर हैं। हाल ही के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में हमने आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के बारे में बहुत डींगे मारी थी परन्तु अब इस बारे में किसी को भी इतनी अधिक चिंता नहीं है। इस के विपरीत आर्थिक सहायता के लिये हम अमरीका की ऋण लेते हैं। विश्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हुए बिना हम अपनी चौथी योजना भी आरम्भ नहीं कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में ऐसी नीतियों के होते हुए एक स्वतंत्र विदेश नीति को बनाये रखने की बात करना निरर्थक है। आखिरकार विदेश नीति हमारी आन्तरिक नीति की एक प्रक्षेप मात्र है। चूंकि हमारी आन्तरिक तथा आर्थिक नीति में प्रतिक्रियावादी परिवर्तन हो रहा है इसलिये हमारी विदेश नीति में भी प्रतिक्रियावादी परिवर्तन हो रहा है।

पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में यदि सरकार ने आरम्भ से ही एक सही नीति अपनाई होती तो नागालैंड समस्या उत्पन्न ही न होती। जब 1951 में नागाओं ने मांग की कि उनका एक अलग प्रदेश बनाया जाये तो सरकार ने उन की इस मांग को रद्द कर दिया किन्तु जब उन्होंने भारत से भी अलग होने की बात कही तो सरकार ने अलग राज्य स्थापित करना स्वीकार कर लिया। नागालैंड तथा इस के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों को स्वायत्तता देने का आश्वासन दिया गया था परन्तु इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार को वहां के लोगों को विश्वास दिलाना चाहिये कि वह सारे नागालैंड के हितों का ध्यान रखना चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कृ० चं० पंत (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि हमारी नीति के मूल सिद्धान्त और मूल उद्देश्य कभी कभी बहुत ही आदर्शवादी मालूम होते हैं तथापि गत कई वर्षों से ये हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हैं। हमारा सदा यह उद्देश्य रहा है कि देश में शान्ति बनी रहे जिससे हम अपना आर्थिक विकास कर सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम सदा यह चाहते रहे हैं कि विश्व में शान्ति बनी रहे

हम सदा सभी देशों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते रहे हैं और किसी गुट में शामिल नहीं हुए हैं। इस के बावजूद भी कि हमें विवश हो कर चीन और पाकिस्तान के विरूद्ध हथियार उठाने पड़े, हमारी विदेश नीति के आधार अब भी उतने ही वैध हैं जितने कि पहले थे। चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के समय हमारी मूल आन्तरिक तथा विदेश नीतियों का कड़ा परीक्षण हुआ है और ये समय की कसौटी पर पूरी उतरी हैं। यही इन नीतियों का वास्तविक औचित्य तथा प्रमाण है कि इन नीतियों से देश का भला हुआ है। इन नीतियों के फलस्वरूप आज स्थिति यह है कि अमरीका, रूस तथा अन्य विभिन्न देशों के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध है। रूस के साथ हमारे सम्बन्धों को बिगाड़ने के लिये चीन के प्रयत्न असफल रहे हैं। चीन और रूस के बीच फूट बढ़ती जा रही है। यही नहीं अफ्रीका, एशिया तथा लातीनी अमरीका में चीन का अब कोई मित्र नहीं रहा है। फिर भी हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिये कि चाहे चीन का कोई मित्र बने अथवा न बने किन्तु वह अपनी मूल नीतियों का पूरी तरह से अनुसरण करेगी।

यदि पाकिस्तान में हुई हाल की घटनाओं को देखा जाये, यदि श्री भुट्टो के बयानों को पढ़ा जाये और यदि चीन के साथ पाकिस्तान के गाठजोड़ को देखा जाये तो हमें सन्देह होने लगेगा कि क्या पाकिस्तान ताशकन्द समझौते का पूर्णतया पालन करना चाहता है। यद्यपि पाकिस्तान केवल बदले की भाषा को ही समझता है तथापि इस मामले में हमें अपने अन्तिम उद्देश्यों को नहीं भूलना चाहिये।

मुझे संयुक्त राष्ट्र के पिछले अधिवेशन में जाने का अवसर मिला था। मैंने वहां देखा कि अब काश्मीर में आत्मनिर्णय की बात को समाप्त कर दिया गया है। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमें अपनी नीति पर मज़बूत रहना है। केवल तब ही हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पाकिस्तान फिर सैनिक तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान पर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते। परन्तु हमारी यही कोशिश होनी चाहिये कि पाकिस्तान बातचीत द्वारा मान जाये। हमारे अन्य पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। इन देशों में नेपाल, श्रीलंका, बर्मा तथा अफगानिस्तान हैं। मलयेशिया तथा सिंगापुर ने हमारे देश का बहुत अच्छा साथ दिया है। हां, दक्षिण-पूर्वी एशिया में हमें अपने सम्बन्धों को और मज़बूत करना है। हाल के प्रधान मंत्री के अमरीका के दौरे से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें अपने काम को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। हमारी ऐसी नीति जिस से किसी को भी नाराज़गी न हो। लातीनी अमरीका के देशों में सद्भावना प्राप्त करने के लिये हमें अभी बहुत कुछ करना है। इसी प्रकार हमें अफ्रीका के देशों में बहुत कार्य करना है। यूरोप के छोटे देशों की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र सघ में हमें अपणी स्थिति और सदृढ़ करती है। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में अब काफी परिवर्तन होने चाहिये। अब इस की सदस्यता में एफ्रो-एशियाई देशों की संख्या बहुत बढ़ गई है। साम्यवादी चीन अब इसका सदस्य बनने ही वाला है, यह कोशिश करेगा कि इसे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाय। इससे हमें बहुत हानि होगी। हमें अपने पिछले 20 वर्षों के नाम के आधार सुरक्षा परिषद में यह स्थान प्राप्त करना चाहिये। भारत को पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का मुकाबला नहीं करना चाहिये।

हमें उन देशों का आभारी होना चाहिये जिन्होंने हमें सहायता दी हैं। चीन द्वारा अणु बम के विस्फोट से स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है और विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि चीन का नया विस्फोट पहले से अधिक आधुनिक प्रकार का है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये और इसे बनाने की क्षमता प्राप्त कर लेनी चाहिये। हमें मालूम होना चाहिये कि बम कैसे बनाया जाता है ताकि आवश्यकता के समय हमें कठिनाई न हो।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : एक देश की नीति उस देश हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। हमारे देश ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बहुत पहले अपनी विदेश नीति निर्धारित कर ली थी। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को इसका श्रेय प्राप्त है। भारत ने कोरिया में शान्ति स्थापना के लिये

[श्री अन्सार हरवानी]

बहुत अच्छा काम किया। स्वेज नहर के मामले में भारत ने बहुत अच्छा कार्य किया था। इस प्रकार अफ्रीकी-एशियाई समस्याओं में भारत का काम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। खेद की बात है कि आज हमारा विदेश मंत्रालय ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। वीयतनाम इसका एक उदाहरण है। आज अफ्रीकी-एशियाई देशों का झुकाव नई दिल्ली की ओर न होकर काहिरा की ओर है। भारत को इन देशों में अपनी प्रभाव से कार्य करना चाहिये।

खद की बात है कि हमारे राजनैतिक मिशनों ने ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया है। हमें अपने वदेशिक कार्य मंत्रालय में आवश्यक सुधार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण सोमवार को जारी रखें। अब सभा में गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य होगा।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS, AND RESOLUTIONS

छियासीवां प्रतिवेदन

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियासवें प्रतिवेदन से जो 20 अप्रैल, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियासवें प्रतिवेदन से जो 20 अप्रैल, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted.*

साम्यवादी चीन के विस्तारवाद को रोकने के बारे में प्रशान्त क्षेत्र में एकता के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : PACIFIC CONCORD AGAINST COMMUNIST CHINESE EXPANSIONISM—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा साम्यवादी चीन के विस्तारवाद को रोकने के बारे में संकल्प पर चर्चा करेगी।

श्री व० बा० गांधी (बम्बईनगर-मध्य दक्षिण) : श्रीमानजी, मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रतुस्त करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री व० बा० गांधी : इस एकता के समझौते से इस क्षेत्र में हमारी स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी। हमारी तटस्थता की नीति है। इस प्रकार के समझौते से हमारी नीति को दृढ़ता मिलेगी।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

चीन की नीती विस्तारवादी है। उसके सम्बन्ध में हमें सतर्क रहना है। हमारे इस प्रकार के समझौते में जापान और आस्ट्रेलिया बहुत सहायक हो सकते है।

हम यह कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जापान ऐसी व्यवस्था के लिये राज़ी हो जायेगा। पिछले कुछ ही वर्षों में जापान और चीन के बीच व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और हाल ही में एक सम्मेलन में चीन द्वारा जापानी पत्रकारों को यह बताया गया कि वास्तव में उनका शत्रु रुस है न कि चीन। जहां तक आस्ट्रलिया का संबंध है वह प्रतिरक्षा की दृष्टि से सीमित महत्व का देश है। इसलिये एक पड़ौसी देश के विरुद्ध इस प्रकार के प्रबन्ध के पक्ष में मैं नहीं हूं।

Shri Shreenarayan Das (Darbhanga) : Mr. Chairman, at the present moment I cannot support the Resolution moved by Shri Ranga. Our late Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru concluded the "Panch-Sheel" Agreement with China. In that great emphasis was laid on the principle of peaceful co-existence. Now the Nations of Africa and Asia have realised that the act of Chinas' signing that Agreement was only a farce and actually it wanted to carry on its expansionist activities in its protection. China poses a potentia l danger to the countries of South-East Asia. In view of this our policy of non-alignment is a step in the right direction. In view of the fact that China is a powerful country the fear of South-East Asian countries is quite natural. The Atomic Powers in the American block have their own axe to grind and they will not come to our rescue in times of emergency. Now, what these smaller countries should do is not to make a third block but to find out measures to contain China in its expansionist aim. We should have a concord with the other Block to protect South-East Asian countries from the expansionist policy of China. Therefore I have proposed for the appointment of a high-powered Commission to think over these matters. All the Afro-Asian countries including Russia, Malaysia, Singapore should be called in the Afro-Asian Conference where we should discuss the measures for the security of these countries and for non-interference of any foreign country in their internal affairs. This is a very serious matter and the recommendations which may be given by the commission should be given a serious thought by the Government. While moving my amendment I hope it will be acceptable to the House.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : चीन की विस्तारवादी नीति को आज एशिया को कोई भी देश सहन नहीं कर सकता। इसलिये आवश्यकता है कि एशिया के देश मिलकर एक समझौता करें जिससे चीन की विस्तारवादी नीति को रोका जा सके। दुर्भाग्य से अब अफ्रेशियाई विचार धारा क्षीण होती जा रही है और विशेष रुप से चीन के आक्रमक रवैये के कारण अफ्रेशियाई देश वर्गों में विभक्त होते जा रहे हैं।

इससे पहले कि हम किसी प्रतिरक्षा संबंधी समझौते पर विचार करें हमें क्रियात्मक सहयोग को मजबूत करना है। हमें एशियाई देशों और प्रशान्त क्षेत्रीय देशों में परामर्श संबंधी संस्थानों की स्थापना करनी चाहिये। हमें एशिया के महाद्वीप पर एक क्रियात्मक आधार पर विशेषित अभिकरणों

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

को मज़बूत करना चाहिये। हाल ही मे लंका में एक विधिवेत्ताओं का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। मैं उस सम्मेलन की कार्यवाही से कुछ पंक्तियां उद्धरित करना चाहता हूं ; जो इस प्रकार हैं :

"एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के अनेक देशों ने हाल ही में स्वाधीनता प्राप्त की है। इन देशों की तथा अन्य देशों की अनेक सामहिक हित की समस्याएं हैं। अतः इस सम्मेलन का यह मत है कि इनके सामूहिक आदर्शों तथा सिद्धान्तों की सुरक्षा के लिये एक संगठन स्थापित किया जाये।"

प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये कोई भी समझौता करने से पूर्व मैं समझता हूं कि हमें इस बात का अध्ययन करना चाहिये कि यूरोपीय परिषद ने किस प्रकार धीरे धीरे संरचनात्मक तरीके से कार्य किया है।

चीन की विस्तारवादी नीति से जो खतरा पैदा हो गया है उसके प्रति हमें एशिया के देशों का एकमत्य प्राप्त करना चाहिये। हो सकता हम प्रा० रंगा की बात से पूरी तरह सहमत न हों परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार का समझौता करने की आज बड़ी आवश्यकता है। इसमें भी सन्देह नहीं कि यूरोपीय परिषद के तरीके पर एक क्रियात्मक अभिकरण से हमारी समस्याओं के समाधान में काफी सहायता मिलेगी।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : The idea suggested in Shri Ranga's resolution is not a new one. Hundred and twentyfive years back the Chief Minister of Nepal, Shri Bhim Sen Thapa and Raja Ranjit Singh of Punjab had resolved to contain European Imperialists in their expansionist policy by establishing some form of unity in Asia.

We have to give thought as to what our policy should be; what should be our guiding principles in forming our policy. We must know as to who stood by us and who betrayed us in our times of emergency and on that basis we whould form our foreign policy. Malaysia, Thailand and Taiwan are our tried friends.

In the recent Indo-Pak. conflict Turkey, Saudi Arabia, Iran and Jordan openly supported Pakistan. These countries should realise that the slogan of theocratic society is outdated now. All the Asian countries should unite themselves against the expansionist policy of Europe and the South-East Asian countries should be united to fight the expansionist policy of China. We are pained to see the miserable plight of our Asian brothers in Vietnam at the hands of Americans. It is because of Taiwan's great military strength that China had to march back. We should organise all the South-East Asian countries into our unit and work vigorously for it. The basis for this unity should be our common culture and civilisation. We should also seek the support of New Zealand and Australia and it is for this purpose that we have moved an amendment. It is foolish to rely upon Britain. We should change our policy towards Britain. Britain gave us no help in our times of crisis. We should have direct relations with New Zealand and Australia and only through the Commonwealth. We should form an organisation of all the Buddhist nations since Pakistan is organising certain nations in the name of Islam.

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया) : श्रीमन्, जापान के साथ कोई प्रतिरक्षा संबंधी समझौता करना इसलिये ठीक नहीं है कि जापान और अमरीका के बीच रुस के विरुद्ध सैनिक संधि मौजूद है। यदि अफ्रेशियाई देशों में प्रस्तावित समझौते के परिणामस्वरूप अमरीका का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो अफ्रशियाई देश और भारत चीन और रुस के प्रभाव दायरों में विभक्त हो जायेंगे।

यदि काश्मीर के प्रश्न पर भारत और चीन में लड़ाई छिड़ गई तो जापान चीन का साथ देगा और यदि वियतनाम के प्रश्न पर चीन और अमरीका में लड़ाई हुई तो जापान चीन का साथ देगा। राष्ट्रपति आइजनहावर को जापान में नहीं उतरने दिया था। हमें जापान के लोगों की भावनाओं को नहीं भूलना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। हमारी नीति गुटों से अलग रहने की है और इस नीति की बुनियाद श्री जवाहरलाल नेहरु द्वारा आज से कई वर्ष पूर्व रखी गई थी। उस समय श्री जवाहरलाल नेहरु ने कहा था कि यदि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी हमारे विरुद्ध हो जाती है तो हमें डरना नहीं चाहिये। श्री रघुनाथ सिंह ने ताइवान के बारे में बहुत कुछ कहा परन्तु मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जहां तक भारत के विरुद्ध चीन की सीमानिर्धारण संबंधी मांगों का संबंध है ताइवान उन मांगों से सहमत था। संसार के देशों के बीच अनेक बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय करार हैं। और उन सब में अमरीका की मर्जी चलती है।

हमारी नीति यह है कि हम शांति चाहते हैं और दोनों गुटों से बच कर चलना चाहते हैं। 1950–60 में, पश्चिमी ताकतों के कारण पहले कोरिया की लड़ाई हुई और फिर नहर स्वेज़ में इंगलैंड और फ्रांस द्वारा आक्रमण हुआ। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार लड़ाइयां हों। नवम्बर, 1961 में संयुक्त राष्ट्रमहासभा ने एक संकल्प पारित किया था कि युद्ध प्रयोजनों के लिये परमाणु अस्त्रों का प्रयोग निषिद्ध है। आस्ट्रेलिया, अमरीका, इंगलैंड ने इसके विरुद्ध मत दिया। यह तो इन लोकतंत्रात्मक देशों का चरित्र है। जब अल्जीरिया अपनी स्वाधीनता के लिये लड़ रहा था तो फ्रांसने अमरीका से 'नाटो' द्वारा प्राप्त हथियारों का प्रयोग किया। क्या हम नहीं जानते हैं कि आज ब्रिटेन और जापान चीन से गहरे संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? क्या आप नहीं जानते हैं कि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के लिये इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है कि वे अमरीका की हां में हां मिलायें। क्या दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियतनाम, ताइवान, थाइलैंड, फिलीपीन्स आदि जैसे देशों के बीच में इस प्रकार का समझौता हो सकता है ?

हम विदेशी सैनिक अड्डों के विरूद्ध रहे है। परन्तु जापान अब भी एक बहुत बडा सैनिक अड्डा है जिसे अमरीका इस्तेमाल करना चाहता है। अमरीका की हमेशा से यह नीति रही है कि एशिया के देशों को आपस में लड़ाया जाये।

हमारी नीति यह होनी चाहिये कि हम शांति में तो विश्वास करें परन्तु इसके साथ साथ युद्ध के लिये भी तैयार रहें। साम्यवाद के विस्तार से लड़ने का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Vishwanath Rai (Devariya) : Mr. Chairman, the purpose of this resolution is to defend our country from the expansionist policy of Communist China. For this end a third Block has got to be created, which will include those Imperialist countries also whom we call democracies. Such sort of alliance goes against the very fundamentals of our policy of non-alignment. We are wedded to the policy of secularism. All countries that cooperate with us in a good cause are our friends. But to make ourselves a tool in the hands of others to check the expansionist policy of one country is not proper. Therefore, I oppose this resolution. I also oppose the amendment which says that this should be reported to a Commission for consideration. There is nothing special in this resolution which this House cannot consider. Our policy of non-alignment has won us sympatny from all parts of the world in our conflicts with Pakistan and China. To lose this sympathy by joining any block will not be in the interest of the country.

Shri Sheo Narain (Bansi) : Mr. Chairman, this resolution is a step in the direction of peace. This resolution aims at the unity of Afro-Asian countries. When those small countries become united, they will be a power to be reckoned with and America or Russia will not be able to dominate over them. Instead of going to America or any far off country we should forge alliance with Japan,

[Shri Sheo Narayan]

Australia and other neighbour countries enumerated by Shri Ranga and Shri Raghunath Singh. China is our bitterest enemy; it has committed breach of trust with us. Malaysia openly supported us in the recent Indo-Pak. conflict and we should honour that country. India has always stood for peace. In the olden days Lord Buddha gave message of peace to the world and now we gave the principle of Panch Sheel and peaceful coexistence to the world. We are wedded to the policy of non-alignment. This resolution is in conformity with all our peace efforts. Therefore we should adopt this resolution.

श्री खाडिलकर (खेड) : सभापति महोदय, इस संकल्प के बारे में हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह हमारी विदेशी नीति के अनुकूल है।

8 अप्रैल के स्टेट्समैन में मैं ने एक लेख पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाले नये नये देश किस प्रकार धीरे धीरे अमरीका के प्रभाव में आते जा रहे हैं और अमरीका उनको किस प्रकार साम्यवाद के विरुद्ध अपनी कठपुतली बनाता जा रहा है। क्या हम भी यही रुख अपनाना चाहते हैं ? जवाहरलाल नेहरु ने कहा था कि यदि आप अमरीकी नीति का साधन बनना चाहते हैं तो शांति और विकास का कोई प्रश्न ही नहीं है।

पहले, फिलीपीन्स, थाईलैंड, जापान और आस्ट्रेलिया के बीच एक प्रकार का सैनिक समझौता था। परन्तु अब प्रश्न यह है कि यदि हम उनके साथ मिलें भी तो क्या वे किसी भी तरह से सशक्त सैनिक राष्ट्र हैं ? जब तक वे अमरीका की विदेश नीति को अपनी नीति का आधार नहीं बनाते तब तक क्या उनके पास इतनी शक्ति है कि वे चीन के विस्तारवाद को रोक सकें ?

हमें यह भी याद रखना चाहिये कि जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो जवाहरलाल नेहरु ने कहा था और बाद में विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि की थी कि हमारा झगड़ा चीन से है साम्यवाद से नहीं है ; साम्यवाद एक दर्शन है ; इसका मुकाबिला हम एक अन्य दर्शन के समान करेंगे।

आज संसार में क्या स्थिति है ? पश्चिम में फ्रांस चीन के बारे में एक पृथक रुख अपनाना चाहता है। पूर्व में जापान में बड़ा मतभेद पाया जाता है और तथाकथित समाजवादी लोग चीन से घनिष्ठ संबंध बनाना तथा चीन से दुर रहना चाहते हैं।

आश्चर्य की बात यह है कि प्रस्तावक का संकल्प यह है कि हम ऐसे छोटे राष्ट्रों से गटजोड़ करें जो कुछ अन्य बड़े राष्ट्रों पर निर्भर हैं। वे सही अर्थों में स्वतन्त्र नहीं हैं। उनकी शक्ति बहुत सीमित है। यदि चीन से खतरा है तो इसका मुकाबला हमें अवश्य करना चाहिये। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। परन्तु इस खतरे के कारण हमें एक ऐसे गुट में शामिल नहीं होना चाहिये जिसमें नीति का आधार अमरीकी नीति है। संकल्प हमारी नीति के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Unless our country becomes militarily strong no country will like to make friends with us. Everybody worships the rising sun and nobody worships the setting sun.

It is most unfortunate that during the last eighteen years we have suffered defeat and humiliation even at the hands of smaller countries. If in these past years we had paid more attention towards increasing our military strength, there would have been a completely different situation today. More radical changes are necessitated in our foreign policy to make our country strong. We should laid a good bye to our present policy of appeasement.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : प्रस्तावक महोदय कहते हैं कि हम कुछ देशों से रक्षात्मक सैनिक संधि करें। परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि संसार में अब तक जो सैनिक संधियां की गई हैं उनका क्या परिणाम निकला है ? हम जानते हैं कि 'नाटो' और 'सेंटो' जैसी संधियों का क्या परिणाम निकला है। मुझे इसमें सन्देह है कि सीटो से राष्ट्रों में सामूहिक सुरक्षा की कोई भावना आई हो जिसके लिये यह संगठन कार्य कर रहा है। वास्तविकता यह है कि ये सभी सैनिक संधियां दुर्बल होती जा रही हैं।

प्रस्तावक को चाहिये था कि इसकी बजाये वह हमें अमरीकी सैनिक गुट में शामिल होने के लिये कहते, परन्तु उन्होंने प्रस्थापना को घुमाफिरा कर प्रस्तुत किया है। हमारी विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट है और वह यह है कि हम किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं होंगे। यदि हम सैनिक गुटों में शामिल होना भी चाहते हैं तो उनमें शामिल होने का समय अब नहीं रहा है। सैनिक गुटों का कोई अर्थ नहीं रहा है और लोगों को मालूम हो गया है कि यह सर्वथा असफल रहे है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Chairman, we must improve our relations with Taiwan. This is essential because Taiwan has stopped taking help from America and in this context it has become more independent than India. Without aligning ourselves with any military block we should try to improve our relations with Thailand, Malaysia, Philippines, South Korea, South Vietnam and Japan.

Indias' foreign policy is very dubious and utterly confused. China attacked our country and swallowed our territory and yet India is trying to get her admitted in the U.N.O. It is not being realised that once China is admitted to the U.N., it would become a member of the Security Council and then it would exercise its veto power against India on the question of Kashmir.

The correct procedure is that we should severe our connections with China. We should have diplomatic relations with Taiwan; atleast we should improve our relations with that country.

Let us understand that Taiwan, Philippines, Japan, Malaysia, Thailand etc., are no ordinary powers today. We should remember that these are the countries who came to our help when we needed it. That is the point we should bear in mind while considering the resolution.

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : इस संकल्प का उद्देश्य कुछ देशों के साथ गुटबन्दी करना है। डा० लोहिया ने कहा कि हमें चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाने के लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने इस बारे में स्पष्टीकरण किया था और बताया था कि हमें बेकाबू चीन को किसी न किसी नियन्त्रण के अधीन लाना चाहिये और संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक ऐसी जगह है जहां इसके लिये कुछ किया जा सकता है।

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि हम शक्तिशाली नहीं हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझता है कि हमारा देश एक कमजोर देश है।

इस संकल्प में हमारी शक्ति के बारे में गलत अनुमान लगाया गया है। हमारा देश दुर्बल नहीं है। हमारी वर्तमान नीति के कारण कई देश हमारे मित्र बने हैं। तथा उनकी सहानुभूति हमें प्राप्त हुई है।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यदि प्रशांत समझौते का अर्थ यह सुझाव देना है कि हमें आर्थिक संबंध सुदृढ़ करने में, तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान और आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिये एक दूसरे की हर प्रकार से सहायता करना है, तो मैं उसका

[श्री स्वर्ण सिंह]

समर्थन करता हूं। हमें अन्य देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने चाहिये। हम संयुक्त राष्ट्र संघ तथा कई अन्य संगठनों में इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियों में पहले ही भाग ले रहे हैं।

यदि सुदृढ़ प्रतिरक्षात्मक समझौते का अर्थ यह है कि हम कुछ प्रतिरक्षात्मक समझौतों में शामिल होने के लिये कुछ कार्यवाही करने में पहल करें तो यह सुझाव हमारी वर्षों से चली आ रही उस नीति के बिल्कुल विरुद्ध होगा जिसके कारण दश के विभिन्न भागों में शांति स्थापित करने में बहुत सफलता मिली है और संकट तथा कठिनाई के समय में भी हमें तथाकथित विभिन्न सैनिक गुटों वाले देशों से समर्थन और सहयोग प्राप्त हुआ है। अपने देश को तथा विश्व के इस भाग में शांति की शक्तियों को सुदृढ़ बनाने तथा सर्वत्र तनाव कम करने के लिये अपना योगदान जारी रखने का एकमात्र तरीका यह है कि हम शांति तथा गुटनिर्पेक्षता की नीति पर चलते रहें।

यदि संकल्प का उद्देश्य यह है कि हम जापान और आस्ट्रेलिया से अपनी प्रतिरक्षा सामर्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिये सहायता प्राप्त करें तो हम इसका स्वागत करते हैं। हमें जहां से भी सैनिक सामान मिल सकता है, हमें उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु यदि उन देशों के साथ सन्धि करने का विचार है तो यह अच्छा सुझाव नहीं है। यह उचित नहीं है कि भारत जैसा कोई बड़ा देश, जो कुछ आदर्शों और सिद्धान्तों के अनुसार काम कर रहा हो, किसी भी अवस्था में कार्य की स्वतन्त्रता को दूसरों के पास गिरवी रख दे। हमने सदा ही सैनिक सन्धियों से दूर रहने की नीति अपनाई है क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि उन से तनाव में वृद्धि होती है और उनसे वर्तमान समस्या भी हल नहीं होती। स्वयं प्रतिरक्षा सन्धियों का सिद्धान्त और स्वरूप बदल रहा है। उनके प्रभाव में भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। जब उन सन्धियों में भाग लेने वाले देशों को कठिनाई होती है तो उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं होता है।

चीनी खतरा केवल सैनिक खतरा ही नहीं है। इसका सैनिक स्वरूप तो है परन्तु उससे कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं। संभव है कि चीन द्वारा अपनाई जा रही नीति तथा विभिन्न देशों मे उनकी गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से सैनिक संघर्ष का रूप न धारण करें बल्कि कई और रुप धारण करें। चीन जैसा देश दूसरों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति को पुर्णतया नहीं समझता अथवा उस पर नहीं चलता। विश्व के देशों का यह अनुभव है कि देश के अन्दर गड़बड़ कई तरीकों से पैदा की जा सकती है।

ऐसी परिस्थितियों में तोड़फोड़ की किसी भी कार्यवाही के प्रयत्नों को सुदृढ़ प्रगतिशील राष्ट्रवादी तत्वों को और मजबूत बना कर ही रोका जा सकता है और इसका मुकाबला सैनिक गठबन्धनों द्वारा नहीं किया जा सकता। चीन की धमकी का सामना केवल सनिक गठबन्धनों से करने की बात सोचना ऐसे मामले की गम्भीरता को कम करना है।

श्री रंगा : खेद की बात है कि हम इस अवसर का लाभ नहीं उठा रहे और प्रशान्त क्षेत्र में देशों की एकता का लाभ नहीं उठा रहे हैं। रुसने युद्ध की धमकी द्वारा विदेशों में साम्यवाद फैलाने की नीति का त्याग कर दिया है। अब रुस शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास रखता है। हो सकता है ऐसा समय आयें जब चीन भी ठीक रास्ते पर आ जाये और ऐसी नीति का अनुसरण करने लगे। परन्तु जब तक साम्यवादी चीन से विस्तारवाद का खतरा बना हुआ है तब तक यह आवश्यक है कि भारत सरकार इस प्रकार के समझौते द्वारा अपने देश तथा अन्य देशों को मजबूत बनाने के लिये अपने प्रतिरक्षा तथा सांस्कृतिक नीतियों के साथ साथ अपनी विदेश नीति को उन्नतिशील बनाने के लिये तत्पर रहे। यह बड़ खेद की बात है कि माननीय मंत्री ने इसके महत्व को नहीं समझा है। साम्यवादी चीन को विस्तारवादी नीति छोड़ने के लिये तैयार करने के लिये भारत तथा अन्य देशों को सामूहिक रूप से शक्तिशाली बनना होगा। इन देशों को अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था में एकरूपता लानी होगी ताकि खतरे के समय वे सैनिक तथा असैनिक क्षेत्रों में एक दूसरे की सहायता कर सके।

चीन के आक्रमण के समय हमें अनुभव हुआ था कि दूसरे देशों की सहायता कितनी आवश्यक होती है। परन्तु अब भी हम अपनी नीति में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हमें पिछले अनुभव के आधार पर अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। मैंने स्वर्गीय श्री नेहरू से भी प्रशान्त क्षेत्र के देशों में एकता लाने के लिये ऐसे समझौते का सुझाव दिया था। चीन से खतरा उस समय और भी बढ़ गया था जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। यदि प्रशान्त क्षेत्र मे ये देश एक समझौता कर लेते हैं तो वे खतरे के समय एक दूसर की सहायता कर सकते है। इन दशों का विकास इस प्रकार होना चाहिये कि एक दूसरे की यथासंभव सहायता कर सकें। 1962 में बहुत कम देशों ने खुले रूप से हमारी सहायता की घोषणा की थी। इस प्रकार का समझौता भारत तथा प्रशान्त क्षेत्र के अन्य देशों के हित में होगा।

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री व० बा० गांधी : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभी संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।/*The amendments were, by leave withdrawn.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि साम्यवादी चीन के विस्तारवाद को रोकने की दृष्टि से सरकार को प्रशान्त क्षेत्र में एकता बढ़ाने के लिए, जापान और आस्ट्रेलिया तथा अन्य सम्बन्धित लोकतंत्रात्मक देशों के साथ ठोस रक्षात्मक समझौतों के रूप में कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The Motion was Negatived.*

आपात की उद्घोषणा और भारत रक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : PROCLAMATION OF EMERGENCY AND DEFENCE OF INDIA ACT

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह आपात की उद्घोषणा का प्रतिसंहरण करने और भारत रक्षा अधिनियम का निरसन करने के लिये अविलम्ब कार्यवाही करे।"

श्रीमन, यह सरकार पुलीस के तरीके अपना कर लोकतन्त्र के ऊंचे नाम को मलिन कर रही है। प्रधान मंत्री ने कई बार आश्वासन दिया है कि आपात काल की उद्घोषणा को आवश्यकता से एक दिन भी अधिक नहीं रखा जायेगा। मैं यह उचित नहीं समझता कि इस बारे में मुख्य मंत्रियों से सलाह की जाये। इस बारे में इस सभा की बात को अधिक महत्व मिलना चाहिये।

आजकल केन्द्रीय सरकार लगभग शक्तिहीन हो गई है। मुख्य मंत्री ने अपने अधिकार बहुत अधिक बढ़ा लिये है। यह शायद इसलिये है कि वे प्रधान मंत्री के अपने दल के नेता चुने जाने में बहुत सहायक थे। सरकार को इस आपात कालीन स्थिति को जारी रखने के कारण बताने चाहिये। संविधान के अन्तर्गत जनता के कुछ मूलभूत अधिकार है। मुख्य मंत्रियों का इस से कोई सम्बन्ध नही है। राज्य सरकारें

[श्री स रेंद्रनाथ द्विवेदी]

आपात कालीन स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर लोगों को बिना किसी दोष के तंग किया है। आजकल हमारे देश में एक प्रकार की तानाशाही चल रही है। यह बड़े खेद की बात है। राज्य सरकारें आन्तरिक गड़बड़ तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनों से निपटने के लिये भारत रक्षा नियमों का दुरुपयोग कर रही है। सरकार को संसद् तथा संविधान के प्रति अधिक मान दिखाना चाहिये।

यदि देश को युद्ध का सामना करना पड़ रहा हो और या देश की अर्थ-व्यवस्था के बिगड़ने का भय हो तो क्या इन असाधारण अधिकारों को बनाये रखनें में कुछ औचित्य है। इन में से कोई भी बात इस समय नहीं है।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 25 अप्रैल 1966/5 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 25, 1966/ *Vaisakha* 5, 1888 (*Saka*).

7236

GIPN—SV—61 L. S./66—23-9-67—565